खण्ड-192, अंक-1
सोमवार, 5 फाल्गुन, शक संवत् 1879
(24 फरवरी, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 192 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

सोमवार, ५ फाल्गुन, शक संवत् १८७९
(२४ फरवरी, १९५८ ई०)

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–४
प्रश्नोत्तर	५–३८
साप्ताहिक कार्यक्रम की सूचना	३८–३९
१९५८–५९ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	३९–८३
नत्थियां	८४–८७

मंगलवार, ६ फाल्गुन, शक संवत् १८७९
(२५ फरवरी, १९५८ ई०)

उपस्थित सदस्य	८९–९३
प्रश्नोत्तर	९३–११९
इलाहाबाद में डकैती और कत्ल के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	११९
इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित सदस्यों के संबंध में सूचना ..	११९–१२०
जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१२०
विधान सभा से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा के लिये श्री श्रीनाथ भार्गव की प्रार्थना (स्वीकृत)	१२०–१२१
१९५८–५९ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (समाप्त)	१२१–१६२
नत्थियां	१६३–१८२

बुधवार, ७ फाल्गुन, शक संवत् १८७९
(२६ फरवरी, १९५८ ई०)

उपस्थित सदस्य	१८३–१८६
प्रश्नोत्तर	१८७–२०८
होली की छुट्टी के संबंध में जानकारी	२०८
इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९५७ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान-सभा-सदस्यों का निर्वाचन	२०९–२११
१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	२११
अनुदान संख्या ८—लेखा शीर्षक १३—अन्य कर और शुल्क (स्वीकृत) ..	२११–२१२
अनुदान संख्या ३७—लेखा शीर्षक ५५—बुढ़ौती भत्ते और पेंशन (स्वीकृत)	२१२–२१३

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या ५०--लेखा शीर्षक ८३--पेंशनों की संराशि का भुगतान (स्वीकृत)	२१३
अनुदान संख्या १४--लेखा शीर्षक २५--गांव सभायें और पंचायतें, अनुदान संख्या ३४--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान तथा अनुदान संख्या ३९--लेखा शीर्षक ५७---प्रकीर्ण व्यय (जारी)	२१३-२५३
नत्थियां	२५४-२५६
बृहस्पतिवार, ८ फाल्गुन, शक संवत् १८७९ (२७ फरवरी, १९५८ ई०)	
उपस्थित सदस्य	२५७-२६०
प्रश्नोत्तर	२६१-२९१
प्रश्नों का उत्तर समय से न मिलने की शिकायत	२९१
चिनकुरी खान दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के क्षतिग्रस्त परिवारों की सहायतार्थ प्रार्थना	२९१
वादविवाद की व्यवस्था पर वैधानिक आपत्ति	२९२
१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १४--लेखा शीर्षक २५--गांव सभायें और पंचायतें, अनुदान संख्या ३४--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान तथा अनुदान संख्या ३९--लेखा शीर्षक ५७--प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत)	२९२-३०६
अनुदान संख्या ५२--लेखा शीर्षक त--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण (स्वीकृत)	३०७-३३४
नत्थियां	३३५-३४३
शुक्रवार, ९ फाल्गुन, शक संवत् १८७९ (२८ फरवरी, १९५८ ई०)	
उपस्थित सदस्य	३४५-३४८
प्रश्नोत्तर	३४९-३७८
प्रथम पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट हिन्दी में न मिलने की शिकायत ..	३७८-३७९
बजट साहित्य का समय से वितरण न होने की शिकायत	३७९
चिनकुरी खान दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के क्षतिग्रस्त परिवारों की सहायता के संबंध में जानकारी	३७९-३८०
१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	३८०-३८२
अनुदान संख्या ५--लेखा शीर्षक १०--वन (जारी)	३८२-३९२
मुख्य मंत्री व कुछ अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न का सूचना (जारी)	३९३-३९४
१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान --अनुदान संख्या ५--लेखा शीर्षक १०--वन (स्वीकृत)	३९५-४०६

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या ४२--लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय तथा अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक ८५-क--राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत (जारी)	४०६-४२१
मुख्य मंत्री व कुछ अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)	४२१-४३६
१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४२--लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय तथा अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक ८५-क--राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	४३७
नत्थियां	४३८-४४५
शनिवार, १० फाल्गुन, शक संवत् १८७९ (१ मार्च, १९५८ ई०)	
उपस्थित सदस्य	४४७-४५०
भावी कार्यक्रम के संबंध में सूचना	४५१-४५२
चिनकुरी खान दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के क्षतिग्रस्त परिवारों की सहायता के संबंध में जानकारी की मांग	४५२
लखनऊ मेडिकल कालेज तथा गांधी मेमोरियल अस्पताल के क्लिनिकल व पेड असिस्टेंट द्वारा हड़ताल के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४५३
बद्रीनाथ मंदिर में लाखों रुपये के गोलमाल, भ्रष्टाचार और अपव्यय के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४५३
गवर्नमेंट वर्कशाप रुड़की के मजदूरों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४५३
मुख्य मंत्री व कुछ अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	४५३-४६६
द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति का प्रथम प्रतिवेदन (प्रथम भाग) (प्रस्तुत किया गया)	४६६-४६७
कार्य-सूची में कटौती के प्रस्तावों में नेता विरोधी दल का नाम सब से ऊपर रखने का सुझाव	४६७-४७४
१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या १५--लेखा शीर्षक २७--न्याय प्रशासन (स्वीकृत) ..	४७४-४९३
अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०--कृषि संबंधी विकास, अभियंत्रण और खोज, अनुदान संख्या २३--लेखा शीर्षक ४१--पशु-चिकित्सा तथा अनुदान संख्या ४५--लेखा शीर्षक ७१--कृषि सुधार और खोज की योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	४९३-५०७

सोमवार, १९ फाल्गुन, शक संवत् १८७९
(१० मार्च, १९५८ ई०)

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५०९–५१२
प्रश्नोत्तर	५१२–५३८
नैनीताल जिले में जगदीशपुर के निकट भूमि वितरणार्थ समवेत प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५३८–५४०
अन्य कार्य-स्थगन प्रस्तावों के संबंध में पूछताछ	५४०–५४१
श्री कल्याण चन्द मोहिले की गिरफ्तारी की सूचना	५४१
कार्य-क्रम में परिवर्तन की सूचना	५४२–५४३
प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५४३
दंड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५४३
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५७–५८ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९५८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	५४३
१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक ३९—जन-स्वास्थ्य (स्वीकृत)	५४३–५७९
नस्थियां	५८०–५८८

मंगलवार, २० फाल्गुन, शक संवत् १८७९
(११ मार्च, १९५८ ई०)

उपस्थित सदस्य	५८९–५९२
प्रश्नोत्तर	५९२–६२३
शाहजहांपुर जिला बोर्ड के सभापति के निर्वाचन के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	६२४
जिलाधीश बाराबंकी द्वारा सोशलिस्ट प्रदर्शनकारियों से मिलने से इन्कार करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	६२४
बाराबंकी में होली के अवसर पर झगड़े के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	६२५
रुद्रपुर, जिला नैनीताल में भूमि-वितरणार्थ समवेत प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	६२५–६२६
१९५८–५९ की सार्वजनिक लेखा समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम	६२६–६२७
तारांकित प्रश्न ९८ से संबंधित अनुपूरक प्रश्न का गलत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना ..	६२७

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का १९५४–५५ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसका ज्ञापन (मेज पर रखे गये)	६२७
बृहत् जोतकर नियमावली, १९५७ में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	६२७–६२८
१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन	६२८
अनुदान संख्या १––लेखा शीर्षक ४––कृषि आय-कर की उगाही पर व्यय, अनुदान संख्या २––लेखा शीर्षक ७––मालगुजारी, अनुदान संख्या २२––लेखा शीर्षक ४०––कृषि उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या ३५––लेखा शीर्षक ५४––दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि (जारी)	६२८–६३९
सरकार द्वारा 'ब्लिट्ज' को विज्ञापन दिये जाने पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना	६३९
१९५८–५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १––लेखा शीर्षक ४––कृषि आय कर की उगाही पर व्यय, अनुदान संख्या २––लेखा शीर्षक ७––मालगुजारी, अनुदान संख्या २२––लेखा शीर्षक ४०––कृषि उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या ३५––लेखा शीर्षक ५४––दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि (जारी)	६४०–६६९
नत्थियां	६७०–६७४
बुधवार, २१ फाल्गुन, शक संवत् १८७९ (१२ मार्च, १९५८ ई०)	
उपस्थित सदस्य	६७५–६७८
प्रश्नोत्तर	६७९–७०८
११ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न ९८ से सम्बन्धित एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का संशोधन	७०८
विशेषाधिकार की अवहेलना के तीन प्रश्नों की सूचना	७०८–७१३
भदोही के कालीन उद्योगपतियों तथा मजदूरों में झगड़े के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	७१३
रुड़की वर्कशाप के अधिकारियों द्वारा दिये गये आश्वासन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	७१३
इलाहाबाद पुलिस की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	७१४
डूल्हापुर, जिला मुरादाबाद के साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	७१४–७१५
श्री बंशीधर शुक्ल द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	७१५

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १---लेखा शीर्षक ४---कृषि आय कर की उगाही पर व्यय, अनुदान संख्या २---लेखा शीर्षक ७---मालगुजारी, अनुदान संख्या २२---लेखा शीर्षक ४०---उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या ३५---लेखा शीर्षक ५४---दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रामित धनराशि (स्वीकृत)	७१५-७५७
गुड़ और खांडसारी गृह-उद्योगों को प्रोत्साहन से सम्बन्धित ३-२-५८ के तारांकित प्रश्न २६ के विषय पर विवाद	७५७-७६३
नस्थियां	७६४-७७१
बृहस्पतिवार, २२ फाल्गुन, शक संवत् १८७९ (१३ मार्च, १९५८ ई०)	
उपस्थित सदस्य	७७३-७७६
प्रश्नोत्तर	७७७-८१५
प्रश्नों के सम्बन्ध में पूछताछ	८१५-८१६
श्री गेंदासिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना	८१६-८२०
तीन कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	८२०
उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	८२०
स्थायी समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव	८२०
कार्य-सूची में कटौती के प्रस्तावों में नेता विरोधी दल का नाम सब से ऊपर रखने के सुझाव पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	८२१-८२५
१९५८-५९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---विभिन्न अनुदानों के लिए समय-विभाजन	८२५
अनुदान संख्या २८---लेखा शीर्षक ४७---श्रम और अनुदान संख्या ४१---लेखा शीर्षक ५७---समाज कल्याण (स्वीकृत)	८२५-८५८
लगान व मालगुजारी की छूट से सम्बन्धित १३ फरवरी, १९५८ के अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न ४ व ५ के विषय पर विवाद	८५८-८६४
नस्थियां	८६५-८८२

शासन

राज्यपाल

श्री वराहगिरि वेंकटगिरि

मंत्रि-परिषद्

मन्त्री (जो मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान-सभा-सदस्य, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन एवं नियोजन मंत्री ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, वित्त, उद्योग तथा विद्युत् मंत्री ।

श्री हुकुमसिंह बिसेन, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, स्वास्थ्य, कृषि, वन तथा पुनर्वासन मंत्री ।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान-सभा-सदस्य, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, माल मंत्री ।

श्री सैयद अली जहीर, बार-एट-ला, विधान-सभा-सदस्य, न्याय, वन तथा अन्न मंत्री ।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान-सभा-सदस्य, गृह, शिक्षा तथा सूचना मंत्री ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, विधान-सभा-सदस्य, स्वशासन मंत्री ।

आचार्य जुगल किशोर, विधान-सभा-सदस्य, श्रम तथा समाज कल्याण मंत्री ।

श्री मोहनलाल गौतम, विधान-सभा-सदस्य, सहकारिता मंत्री ।

मन्त्री (जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं हैं)

श्री मंगला प्रसाद, बी० ए०, एल-एल०-बी०, विधान-सभा-सदस्य, हरिजन सहायक मंत्री ।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान-सभा-सदस्य, समाज सुरक्षा मंत्री ।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी० विधान-सभा-सदस्य, सिंचाई मंत्री ।

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (बिस), पी-एच० डी०, विधान-सभा-सदस्य, मादक कर तथा परिवहन मंत्री ।

उप-मन्त्री

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, नियोजन उपमंत्री ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, विधान-सभा-सदस्य, न्याय एवं अन्न उपमंत्री ।

श्री कैलाश प्रकाश, विधान-सभा-सदस्य, शिक्षा उपमंत्री ।

श्री रऊफ जाफरी, एम० ए०, विधान-सभा-सदस्य, उद्योग उपमंत्री ।

श्री परमात्मानन्द सिंह, विधान-परिषद्-सदस्य, माल उपमंत्री ।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी, विधान-सभा-सदस्य, स्वास्थ्य उपमंत्री ।

श्रीमती प्रकाशवती सूद, विधान-सभा-सदस्य, समाज कल्याण उपमंत्री ।

सभा-सचिव

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान-सभा-सदस्य।

श्री राजविहारीसिंह, विधान-सभा-सदस्य।

कृषिमंत्री के सभा-सचिव

श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान-सभा-सदस्य।

वित्त मंत्री के सभा-सचिव

श्री वर्मसिंह, विधान-सभा-सदस्य।

स्वशासन मंत्री के सभा-सचिव

श्री रामस्वरूप यादव, विधान-सभा-सदस्य।

गृह मंत्री के सभा-सचिव

श्री इस्तफा हुसैन, विधान-सभा-सदस्य।

श्रम मंत्री के सभा-सचिव

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा, विधान-सभा-सदस्य।

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा-सचिव

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा, विधान-सभा-सदस्य।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सभा-सचिव

श्री महावीरसिंह, विधान-परिषद्-सदस्य।

उत्तर प्रदेश सभा
प्रतिवेदन

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१	अक्षयवरसिंह, श्री	पिपराइच
२	अजीज इमाम, श्री	कंतित
३	अनन्तराम वर्मा, श्री	अलोगढ़
४	अब्दुल रऊफ लारी, श्री	विनायकपुर
५	अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री	कोपागंज
६	अब्दुस्समी, श्री	बरौंसा
७	अभयराम यादव, श्री	जसवंतनगर
८	अमरनाथ, श्री	महाराजगंज
९	अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री	मिर्जापुर
१०	अमोलादेवी, श्रीमती	अठेहा
११	अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री	सलेमपुर (पूर्व)
१२	अली जरीर जाफरी, श्री	उतरौला
१३	अली जहीर, श्री सैयद	लखनऊ शहर (पश्चिम)
१४	अवधेश कुमार सिन्हा, डाक्टर	मिसरिख
१५	अवधेशचन्द्रसिंह, श्री	भोजपुर
१६	अवधेशप्रतापसिंह, श्री	बोकापुर (पूर्व)
१७	अशफाक अली खां, श्री	शाहजहांपुर
१८	असलम खां, श्री	रामपुर
१९	अहमद बख्श, श्री	जानसठ
२०	आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	झांसी
२१	आत्माराम पांडेय, श्री	सैदपुर
२२	आदिराम सिंघल, श्री	आगरा शहर
२३	आनन्दब्रह्म शाह, श्री	राबर्ट्सगंज
२४	आर्थर सी० फाइस, श्री	नाम निर्देशित (आंग्ल भारतीय)
२५	इन्दुभूषण गुप्त, श्री	सगरी
२६	इरतजा हुसैन, श्री	सियाना
२७	इस्तफा हुसैन, श्री	गोरखपुर
२८	उग्रसेन, श्री	सलेमपुर (पश्चिम)
२९	उदयशंकर दुबे, श्री	बस्ती
३०	उबैदुर्रहमान, श्री	बांसी (पूर्व)
३१	उमाशंकर शुक्ल, श्री	कानपुर शहर
३२	उल्फतसिंह, श्री	सहसवान
३३	ऊदल, श्री	कोलासला
३४	एस० अहमद हसन, श्री	कानपुर शहर
३५	कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	शाहाबाद
३६	कमल कुमारी मोइंदो, कुमारी	करछना
३७	कमलापति त्रिपाठी, श्री	चन्दौली
३८	कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले	पुवायां
३९	कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु	इलाहाबाद शहर (दक्षिण)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
४०	कल्याण राय, श्री . .	. . इलाहाबाद
४१	कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री	. . महाइच
४२	कालीचरण अग्रवाल, श्री	. . बालगंज
४३	काशीप्रसाद पांडेय, श्री	. . बादशाहपुर
४४	किशनसिंह, श्री . .	. . ठाकुरद्वारा
४५	किशोरीरमण सिंह, श्री	. . इगलास
४६	कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	. . सुल्तानपुर
४७	केशभान राय, श्री . .	. . मगहर
४८	केशव पांडेय, श्री . .	. . मनीराम
४९	केशवराम, श्री . .	. . बिसौली
५०	कैलाशकुमार सिंह, श्री	. . इस्लामनगर
५१	कैलाशनारायण गुप्त, श्री	. . इलाहाबाद शहर (उत्तर)
५२	कैलाशवती, श्रीमती	. . शिल्लुपुर
५३	कैलाशप्रकाश, श्री . .	. . मेरठ शहर
५४	कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री	. . शिवराजऊ
५५	कृपाशंकर, श्री . .	. . नगर
५६	खजानसिंह, चौधरी . .	. . उन्नाव
५७	खमानीसिंह, डाक्टर	. . मुरादाबाद (देहात)
५८	खयालीराम, श्री . .	. . मोहनलालगंज
५९	खुशीराम, श्री . .	. . पिथौरागढ़
६०	खूबसिंह, श्री . .	. . रामपुर
६१	गंगाधर जाटव, श्री	. . एतमादपुर
६२	गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)	. . एटा
६३	गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)	. . गोंडा (दक्षिण)
६४	गंगाप्रसाद सिंह, श्री	. . रसरा
६५	गजेन्द्रसिंह, श्री	. . सिधूना
६६	गज्जूराम, श्री . .	. . ललितपुर
६७	गणेशप्रसाद पांडेय, श्री	. . बांसगांव
६८	गनेशचन्द्र काछी, श्री	. . भोगांव
६९	गनेशीलाल चौधरी, श्री	. . सिस्वां
७०	गयाप्रसाद, श्री . .	. . बुंडा
७१	गयाबख्शसिंह, श्री . .	. . इगोली
७२	गरीबदास, श्री . .	. . कालपी
७३	गिरधारी लाल, श्री	. . रामपुर
७४	गुप्तारसिंह, श्री . .	. . सरेनी
७५	गुरुप्रसाद सिंह, श्री . .	. . मुसाफिरखाना
७६	गुलाबसिंह, श्री . .	. . मछरी
७७	गेंदादेवी, श्रीमती . .	. . खलीलाबाद
७८	गेंदासिंह, श्री . .	. . पडरौना (पूर्व)
७९	गोकुल प्रसाद, श्री . .	. . चायल
८०	गोपाकृष्ण आजाद, श्री	. . नारायनी
८१	गोविन्दनारायण तिवारी, श्री	. . जालौन
८२	गोविन्द सहाय, श्री . .	. . नगीना
८३	गोविन्द सिंह विष्ट, श्री	. . अल्मोड़ा

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
८४	गौरीराम गुप्त, श्री	..	फरेंदा (पश्चिम)
८५	गौरीशंकर राय, श्री	..	बलिया
८६	घनश्याम डिमरी, श्री	..	बद्रीनाथ
८७	घासीराम जाटव, श्री	..	भरथना
८८	चन्द्रज्योत यादव, श्री	..	मोहम्मदाबाद गोहना
८९	चन्द्रदेव, श्री	..	पडरौना (उत्तर)
९०	चन्द्रबली शास्त्री, ब्रह्मचारी, श्री	..	निजामाबाद
९१	चन्द्रसिंह रावत, श्री	..	पौड़ी
९२	चन्द्रहास मिश्र, श्री ..	..	बिलग्राम
९३	चन्द्रावती, श्रीमती ..	..	बिजनौर
९४	चन्द्रिकाप्रसाद, श्री ..	..	बछरावां
९५	चरणसिंह, श्री ..	..	कोटना
९६	चित्तरसिंह निरंजन, श्री	..	कौंच
९७	चिरंजीलाल जाटव, श्री	..	जलेसर
९८	छत्रपति अम्बेश, श्री	..	आगरा शहर
९९	छेदीलाल, श्री ..	..	श्रीनगर
१००	छोटेलाल पालीवाल, श्री	..	सिरहपुरा
१०१	जंगबहादुर वर्मा, श्री	..	हैदरगढ़
१०२	जगदीशनारायण, श्री	..	बिलारो
१०३	जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री	..	मोहम्मदी
१०४	जगदीशप्रसाद, श्री ..	..	हसनपुर
१०५	जगदीशशरण अग्रवाल, श्री	..	बरेली शहर
१०६	जगन्नाथ, चौधरी ..	..	सिकन्दरपुर
१०७	जगन्नाथप्रसाद, श्री	..	धौरेहरा
१०८	जगन्नाथ लहरी, श्री	..	फिरोजाबाद
१०९	जगपतिसिंह, श्री ..	..	करवी
११०	जगमोहनसिंह नेगी, श्री	..	गंगा सलाण
१११	जगवीरसिंह श्री ..	..	अगोटा
११२	जमुनासिंह, श्री ..	..	गुन्नौर
११३	जयगोपाल, डाक्टर ..	..	हरौरा
११४	जयदेवसिंह आर्य, श्री	..	विरोर
११५	जयराम वर्मा, श्री ..	..	टांडा
११६	जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	..	खीरी
११७	जरगाम हैदर, श्री सैयद	..	बहराइच (उत्तर)
११८	जवाहरलाल, श्री ..	..	मंझनपुर
११९	जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	..	कानपुर शहर
१२०	जागेश्वर, श्री ..	..	किशनपुर
१२१	जितेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	..	कांठ
१२२	जुगलकिशोर, आचार्य	..	गोवर्धन
१२३	जोखई, श्री ..	..	मेजा
१२४	ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री	..	घाटमपुर
१२५	झारखंडे राय, श्री	..	घोसी
१२६	टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री	..	खैराबाद
१२७	टीकाराम, श्री	..	बदायूं

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१२८	टीकाराम पुजारी, श्री	..	सादाबाद
१२९	डूंगरसिंह, श्री	..	राठ
१३०	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	..	सिधौली
१३१	तारादेवी, डाक्टर	..	मांड़याहूं
१३२	तिरमलसिंह, श्री	..	सहावर
१३३	तेज बहादुर, श्री	..	लालगंज
१३४	तेजासिंह, श्री	..	गाजियाबाद
१३५	त्रिलोकी सिंह, श्री	..	लखनऊ शहर (पूर्व)
१३६	दत्त, श्री एस० जी०	..	कानपुर-शहर
१३७	दशरथ प्रसाद, श्री	..	बलरामपुर
१३८	दाताराम, चौधरी ..	..	नाकुड़
१३९	दीनदयालु करुण, श्री	..	बलरामपुर
१४०	दीनदयालु शर्मा, श्री	..	अनूपशहर
१४१	दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	रुड़की
१४२	दीवाकर, आचार्य ..	..	बरौत
१४३	दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री	..	देवरिया (दक्षिण)
१४४	दुर्योधन श्री	..	महाराजगंज
१४५	दुलारादेवी, श्रीमती	..	फर्रुखपुर
१४६	देवकीनन्दन विभव, श्री	..	आगरा शहर
१४७	देवदत्तसिंह, श्री	..	टप्पल
१४८	देवनारायण भारतीय, श्री	..	जमौर
१४९	देवराम, श्री	..	शादियाबाद
१५०	देवी प्रसाद मिश्र, श्री	..	अकबरपुर
१५१	द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री	..	मुजफ्फरनगर
१५२	द्वारिका प्रसाद, श्री	..	कन्नौज
१५३	द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री	..	फरेन्दा (पूर्व)
१५४	धनीराम, श्री	..	लालगंज
१५५	धनुधारी पांडेय, श्री	..	महुली
१५६	धरमपाल सिंह, श्री	..	तुलसीपुर
१५७	धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	सिरौला
१५८	धर्मसिंह, श्री ..	..	अनूपशहर
१५९	नत्थाराम रावत, श्री	..	बाराबंकी
१६०	नत्थू सिंह, श्री (बरेली)	..	परीदपुर
१६१	नत्थू सिंह, श्री (मैनपुरी)	..	बरहल
१६२	नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री	..	हाथरस
१६३	नन्दराम, श्री	..	कुण्डा
१६४	नरदेवसिंह दतियानवी, श्री	..	चांदपुर
१६५	नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री	..	केदारनाथ
१६६	नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	..	चिथौरागढ़
१६७	नवलकिशोर, श्री	..	रामनगर
१६८	नागेश्वर प्रसाद, श्री	..	कैरवारा
१६९	नारायणदत्त तिवारी, श्री	..	नैनीताल
१७०	नारायणदास पासी, श्री	..	बीकापुर (पश्चिम)
१७१	निरंजनसिंह, श्री	..	पीलीभीत

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१७२	नेकराम शर्मा, श्री . .	अतरौली
१७३	पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री . .	अतरौलिया
१७४	पब्बरराम, श्री . . .	गाजीपुर
१७५	परमानन्द सिनहा, श्री . .	सोरांव (पश्चिम)
१७६	परमेश्वरीदीन वर्मा, श्री . .	पुर्वा
१७७	पहलवानसिंह, चौधरी . .	बांदा
१७८	प्रकाशवती सूद, श्रीमती . .	मेरठ (छावनी)
१७९	प्रतापबहादुर सिंह, श्री . .	फखरपुर
१८०	प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री . .	लहरपुर
१८१	प्रतापसिंह, श्री . .	टनकपुर
१८२	प्रभावती मिश्र, श्रीमती . .	लम्भुआ
१८३	प्रभुदयाल, श्री . .	बानगंगा (पश्चिम)
१८४	फतेहसिंह राणा, श्री . .	सरधना
१८५	बंशाधर शुक्ल, श्री . .	श्रीनगर
१८६	बलदेवसिंह, श्री . .	महदेवा
१८७	बलदेव सिंह आर्य, श्री . .	शाहाबाद
१८८	बलवान सिंह, श्री . .	अकबरपुर
१८९	बसन्तलाल, श्री . .	लखनऊ (छावनी)
१९०	बादाम सिंह, श्री . .	शिकारपुर
१९१	बाबूराम, श्री . .	भोजीपुर
१९२	बाबूलाल कुसुमेश, श्री . .	प्रतापगंज
१९३	बालकराम, श्री . .	तिलहर
१९४	बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री . .	डोमरियागंज (दक्षिण)
१९५	बिन्दुमती दास, श्रीमती . .	प्रतापगंज
१९६	बिशम्बर सिंह, श्री . .	हस्तिनापुर
१९७	बिहारीलाल, श्री . .	बोसलपुर
१९८	बुलाकीराम, श्री . .	हरदोई
१९९	बुद्धूलाल, श्री . .	नानपारा
२००	बुद्धूसिंह, श्री	बहजोई
२०१	बृजवासी लाल, श्री . .	बीकापुर (पश्चिम)
२०२	बृजरानी मिश्र, श्रीमती . .	बिल्हौर
२०३	बेचनराम, श्री . .	ज्ञानपुर
२०४	बेचनराम गुप्त, श्री . .	ज्ञानपुर
२०५	बेरोबाई, श्रीमती . .	मऊ
२०६	बैजूराम, श्री	सिधौली
२०७	ब्रजनारायण तिवारी, श्री . .	पडरौना (पश्चिम)
२०८	ब्रजभूषणशरण, श्री . .	देहरादून
२०९	ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री . .	कानपुर शहर
२१०	भगवती प्रसाद दुबे, श्री . .	भावापुर
२११	भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री . .	प्रतापगढ़ (दक्षिण)
२१२	भगवतीसिंह विशारद, श्री . .	भगवन्तनगर
२१३	भगौती प्रसाद वर्मा, श्री . .	बाराबंकी
२१४	भजनलाल, श्री . .	औरैया
२१५	भोलालाल, श्री	हसनगंज

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२१६	भीमसेन, श्री	..	शुर्जा
२१७	भुवनेश भूषण शर्मा, श्री	..	इटावा
२१८	भूपकिशोर, श्री	..	प्रतापगंज
२१९	मंगलाप्रसाद, श्री	..	मेजा
२२०	मंजूरुलनबी, श्री ..	..	सहारनपुर
२२१	मथुराप्रसाद पांडेय, श्री	..	नीगढ़
२२२	मदनगोपाल बंद्य, श्री	..	शमीसन
२२३	मदन पांडेय, श्री ..	..	तिलपुर
२२४	मदनमोहन, श्री ..	..	फैजाबाद
२२५	मन्नालाल, श्री	..	मोहमदी
२२६	मलखान सिंह, श्री	..	सिकन्दराबाद
२२७	मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)	..	मैनपुरी
२२८	महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)	..	बसना
२२९	महमूद अली खां, श्री (रामपुर)	..	रबार टांडा
२३०	महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)	..	मुजफ्फराबाद
२३१	महमूद हुसैन खां, श्री	..	सम्भल
२३२	महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री	..	बेंवाई
२३३	महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	..	लखनऊ शहर (मध्य)
२३४	महीलाल, श्री	..	सिलारी
२३५	महेन्द्रिपुदमन सिंह, राजा	..	बाह
२३६	महेशसिंह, श्री ..	..	हरदोई
२३७	माता प्रसाद, श्री	..	शाहगंज
२३८	मान्धाता सिंह, श्री	..	कोपाचीत
२३९	मिहरवानसिंह, श्री	..	भरथना
२४०	मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री	..	रुदौली
२४१	मुक्तिनाथ राय, श्री	..	गोपालपुर
२४२	मुजफ्फर हसन, श्री	..	चायल
२४३	मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री	..	बीसल
२४४	मुबारक अली खां, श्री	..	उपेहट
२४५	मुरलीधर, श्री ..	..	माहुल
२४६	मुरलीधर कुरील, श्री	..	बिल्हौर
२४७	मूलचन्द, श्री	..	मिसारेख
२४८	मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री	..	सफीपुर
२४९	मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	..	वाराणसी शहर (उत्तर)
२५०	मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज	..	नसीराबाद
२५१	मुहम्मद फारुक चिश्ती, श्री	..	देवरिया (उत्तर)
२५२	मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	..	बालगंगा (पूर्व)
२५३	मुहम्मद हुसैन, श्री	..	बरेली छावनी
२५४	मोतीलाल अवस्थी, श्री	..	कानपुर (देहात)
२५५	मोहनलाल, श्री	..	महोबा
२५६	मोहनलाल गौतम, श्री	..	कोयल
२५७	मोहन लाल वर्मा, श्री	..	संडीला
२५८	मोहनसिंह मेहता, श्री	..	दादनपुर
२५९	यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री	..	रायबरेली (उत्तर)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२६०	यमुनासिंह, श्री	..	शादियाबाद
२६१	यशपालसिंह, श्री	..	देवबन्द
२६२	यशोदादेवी, श्रीमती	..	बांसगांव
२६३	यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा	..	जौनपुर
२६४	रऊफ जाफरी, श्री	..	मछलीशहर
२६५	रघुनाथसहाय यादव, श्री	..	किशनपुर
२६६	रघुरनतेज बहादुर सिंह, श्री उपनाम लालसाहब	..	सादुल्लानगर
२६७	रघुराजसिंह चौधरी, श्री	..	बुलन्दशहर
२६८	रघुवीरराम, श्री	..	मोहम्मदाबाद
२६९	रघुवीरसिंह, श्री (एटा)	..	जलेसर
२७०	रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)	..	बागपत
२७१	रणबहादुरसिंह, श्री	..	हरैया (पश्चिम)
२७२	रमाकान्त सिंह, श्री	..	अमेठी
२७३	रमानाथ खैरा, श्री	..	ललितपुर
२७४	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	..	बरसाथी
२७५	राघवराम पांडेय, श्री	..	गोंडा (दक्षिण)
२७६	राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री	..	मनकापुर
२७७	राजकिशोर राव, श्री	..	इकौना
२७८	राजकुमार शर्मा, श्री	..	चुनार
२७९	राजदेव उपाध्याय, श्री	..	सिधुवाजोबना
२८०	राजनारायण, श्री	..	कसवर सरकारी
२८१	राजनारायणसिंह, श्री	..	अहरौरा
२८२	राजबिहारीसिंह, श्री	..	कसवर राजा
२८३	राजाराम शर्मा, श्री	..	खलीलाबाद
२८४	राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती	..	डोमरियागंज (उत्तर)
२८५	राजेन्द्रदत्त, श्री	..	शिकारपुर
२८६	राजेन्द्र सिंह, श्री	..	गोंडवा
२८७	राजेन्द्रसिंह यादव, श्री	..	शमशाबाद
२८८	रामअधार तिवारी, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर)
२८९	रामअभिलाख, श्री	..	गोंडा (उत्तर)
२९०	रामकिंकर, श्री	..	पट्टी
२९१	रामकुमार वैद्य, श्री	..	अमरोहा
२९२	रामकृष्ण जैसवार, श्री	..	कन्तित
२९३	रामकृष्ण सारस्वत, श्री	..	फर्रुखाबाद
२९४	रामचन्द्र विकल, श्री	..	सिकन्दराबाद
२९५	रामजीलाल सहायक, श्री	..	सरधना
२९६	रामजी सहाय, श्री	..	सिलहट
२९७	रामदास आर्य, श्री	..	जानसठ
२९८	रामदीन, श्री	..	करहल
२९९	रामनाथ पाठक ,श्री	..	दोआबा
३००	रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	सुरहुरपुर
३०१	रामपाल त्रिवेदी, श्री	..	मलांहाबाद
३०२	रामप्रसाद, श्री	..	सलोन

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३०३	रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	कोयल
३०४	रामप्रसाद नौटियाल, श्री	..	लैंसडाउन
३०५	रामबली, श्री	..	मुसाफिरखाना
३०६	राममूर्ति, श्री	..	बहेड़ी
३०७	रामरतन प्रसाद ,श्री	..	रसरा
३०८	रामरती देवी, श्रीमती	..	अकबरपुर
३०९	रामलक्षण तिवारी, श्री	..	बांसडीह (पूर्व)
३१०	रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)	..	रारी
३११	रामलखन , श्री (वाराणसी)	..	चन्दौली
३१२	रामलखन मिश्र , श्री	..	बांसी (पश्चिम)
३१३	रामलाल , श्री	..	नगर
३१४	रामवचन यादव , श्री	..	माहुल
३१५	रामशरण यादव, श्री	..	मोहनलाल गंज
३१६	रामसनेही भारतीय, श्री	..	बबेरू
३१७	राम समझावन, श्री	..	केराकत
३१८	रामसिंह चौहान, श्री वैद्य	..	पुतमादपुर
३१९	रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	नत्थूपुर
३२०	रामसूरत प्रसाद, श्री	..	पिपराइच
३२१	रामस्वरूप यादव, श्री	..	जसराना
३२२	रामस्वरूप वर्मा, श्री	..	भोगनीपुर
३२३	रामहेतसिंह, श्री	..	छाता
३२४	रामायणराय, श्री	..	पडरौना (दक्षिण)
३२५	रामेश्वर प्रसाद, श्री	..	बछरावां
३२६	रुक्नुद्दीन खां, श्री	..	कोंहडौर
३२७	रूपसिंह, श्री	..	खेरा बजेहरा
३२८	लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	काशीपुर
३२९	लक्ष्मणराव कदम, श्री	..	गरोथा
३३०	लक्ष्मीनारायण, श्री	..	पहाड़पुर
३३१	लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री	..	फतेहाबाद
३३२	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	..	माट
३३३	लायकसिंह, चौधरी	..	शिकोहाबाद
३३४	लालबहादुर सिंह, श्री	..	केराकत
३३५	लुत्फअल्ला खां, श्री	...	हापुड़
३३६	लोकनाथ सिंह, श्री	..	कटेहर
३३७	वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री	..	हैदरगढ़
३३८	वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	..	जमानिया
३३९	वसी नकवी, श्री	..	रोखा
३४०	वासुदेव दीक्षित, श्री	..	खागा
३४१	विचित्रनारायण शर्मा, श्री	..	मोदीनगर
३४२	विजयशंकर सिंह, श्री	..	मुहम्मदाबाद
३४३	विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती	..	शाहाबाद
३४४	विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती	..	देवप्रयाग
३४५	विशालसिंह, श्री	..	भिटौली
३४६	विश्रामराय, श्री	..	आजमगढ़

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३४७	विश्वनाथसिंह गौतम, श्री	..	करांद
३४८	विश्वेश्वरानन्द, स्वामी	..	फतेहपुर सीकरी
३४९	वीरसेन, श्री	..	हापुड़
३५०	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	..	कैराना
३५१	वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री	..	बहराइच (दक्षिण)
३५२	वीरेन्द्रशाह, राजा	..	कालपी
३५३	व्रजगोपाल सक्सेना, श्री	..	महोबा
३५४	व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री	..	घाटमपुर
३५५	शंकरलाल, श्री	..	कादीपुर
३५६	शकुन्तलादेवी, श्रीमती	..	हरौरा
३५७	शब्बीरहसन, श्री	..	खजुहा
३५८	शमसुल इस्लाम, श्री	..	निधपुर
३५९	शम्भुदयाल, श्री	..	संडीला
३६०	शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	..	हरद्वार
३६१	शिवगोपाल तिवारी, श्री	..	सफीपुर
३६२	शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)	..	सिधुवाजोबना
३६३	शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)	..	खीरी
३६४	शिवमंगल सिंह, श्री	..	बांसडी (पश्चिम)
३६५	शिवमूर्तिसिंह, श्री	..	फूलपुर
३६६	शिवराजबलीसिंह, श्री	..	फतेहपुर
३६७	शिवराजबहादुर, श्री	..	नवाबगंज
३६८	शिवराजसिंह यादव, श्री	..	बिसौली
३६९	शिवराम पांडेय, श्री	..	डेरापुर
३७०	शिवचन राव, श्री	..	सलेमपुर (दक्षिण)
३७१	शिवशंकरसिंह, श्री	..	डलमऊ
३७२	शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	..	इकौना
३७३	शीतलाप्रसाद, श्री	..	तरबगंज
३७४	शोभनाथ, श्री	..	राबर्ट्सगंज
३७५	श्याममनोहर मिश्र, श्री	..	लखनऊ (छावनी)
३७६	श्यामलाल, श्री	..	माट
३७७	श्यामलाल यादव, श्री	..	मुगलसराय
३७८	श्रृद्धादेवी शास्त्री, कुमारी	..	किथोर
३७९	श्री कृष्ण गोयल, श्री	..	उझानी
३८०	श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री	..	खैरागढ़
३८१	श्रीनाथ, श्री	..	मोहम्मदाबाद गोहाना
३८२	श्रीनाथ भार्गव, श्री	..	मथुरा
३८३	श्रीनिवास, श्री	..	गांगिरी
३८४	श्रीपालसिंह, कुंवर	..	शाहगंज
३८५	संग्रामसिंह, श्री	..	सोरांव (पूर्व)
३८६	सईद अहमद अन्सारी, श्री	..	ज्वालापुर
३८७	सजीवन लाल, श्री	..	हसनगंज
३८८	सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती	..	शिवपुर
३८९	सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती	..	दादरी
३९०	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	वाराणसी शहर (दक्षिण)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३९१	सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती	..	सरजू
३९२	सियादुलारी, श्रीमती	..	बारबंकी
३९३	सीताराम, डाक्टर	..	सिलहट
३९४	सीताराम शुक्ल, श्री	..	हरैया (पूर्व)
३९५	सुक्खनलाल, श्री	..	हसनपुर
३९६	सुखरानी, देवी श्रीमती	..	फतेहपुर
३९७	सुखराम दास, श्री	..	टांडा
३९८	सुखलाल, श्री	..	औरैया
३९९	सुखीराम भारतीय, श्री	..	पालपुर
४००	सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री	..	गऊ
४०१	सुनीता चौहान, श्रीमती	..	सालोन
४०२	सुन्दरलाल, श्री	..	फरीदपुर
४०३	सुरथबहादुर शाह, श्री	..	सिंघासन
४०४	सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	..	हमीरपुर
४०५	सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार	..	पवायां
४०६	सुरेशप्रकाशसिंह, श्री	..	बिसवां
४०७	सुल्तानआलम खां, श्री	..	कायमगंज
४०८	सूरतचन्द रमोला, श्री	..	टेहरी
४०९	सूर्यबली पांडेय, श्री	..	हाटा
४१०	सोहनलाल धुसिया, श्री	..	बांसी (पूर्व)
४११	हमीदुल्ला खां, श्री	..	शारदा
४१२	हरकेशबहादुर, श्री	..	पट्टी
४१३	हरदयालसिंह, श्री	..	इलालाबाद
४१४	हरदयालसिंह पिपल, श्री	..	हाथरस
४१५	हरदेव सिंह, श्री	..	देवबन्द
४१६	हरिदत्त काण्डपाल, श्री	..	रानीखेत (उत्तर)
४१७	हरिश्चन्द्रसिंह, श्री	..	कातागंज
४१८	हरिहरबख्शसिंह, श्री	..	पाली
४१९	हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर
४२०	हरीसिंह, श्री	..	किथौर
४२१	हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री	..	मुरादाबाद शहर
४२२	हिम्मतसिंह, श्री	..	देवबाई
४२३	हुकुमसिंह विसेन, श्री	..	कैसरगंज
४२४	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	..	मंझनपुर
४२५	हीरालाल यादव, श्री	..	कन्नौज
४२६	[रिक्त]	..	रानीखेत (दक्षिण)
४२७	[रिक्त]	..	अफजलगढ़
४२८	[रिक्त]	..	बुढ़ाना
४२९	[रिक्त]	..	भवन
४३०	[रिक्त]	..	खुर्जा
४३१	[रिक्त]	..	गौदहा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०

उपाध्यक्ष

श्री रामनारायण त्रिपाठी, बी० एस-सी०।

सचिव, विधान मंडल

श्री रूपचन्द्र, एच० जे० एस०।

सचिव, विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी०।

सहायक सचिव

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी०।

कमेटी आफिसर

श्री भोलादत्त उपाध्याय।

अधीक्षक

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० (अवकाश पर)।

श्री अहीन्द्रनाथ मित्र।

श्री श्रीपति सहाय, बी० ए०।

श्री गिरधारीलाल, बी० ए०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २४ फरवरी, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३३७)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीजइमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेश चन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह,श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री

चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री

देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पन्नेरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री

बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री

रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मासिह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सज्जानदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सिद्धादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखधन लाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुलतानआलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २४ फरवरी, १९५८ ई०

तारांकित प्रश्न

झांसी जिले में चिरगांव के निकट रौकर की दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिवार को मुआवजा

*१—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि अप्रैल, १९५७ में चिरगांव (झांसी) के समीप ३०० बोरी सीमेंट लदे हुये नहर विभाग के दो रौकरों में से एक के उलट जाने से उसके ड्राइवर व आपरेटर की वहीं मृत्यु हो गई थी ?

स्वशासन उप मंत्री के सभा सचिव (श्री राम स्वरूप यादव)—जी हां ।

*२—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मृतक लोगों के कुटुम्बों में कितने-कितने व्यक्ति हैं तथा उनकी क्या सहायता की गई है ?

श्री राम स्वरूप यादव—स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद आपरेटर के कुटुम्ब में केवल २ व्यक्ति हैं, उनके पिता व पत्नी ।

स्वर्गीय महेन्द्रनाथ सहायक (helper) के कुटुम्ब में उनके माता पिता तथा पांच भाई हैं । दोनों के कुटुम्बियों को Work-mans Compensation Act के अनुसार मुआवजा देने की कार्यवाही हो रही है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि रौकर इस काबिल नहीं थे कि कहीं भेजे जाते ? यदि हां, तो उनके भेजने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं, ऐसी बात नहीं थी, रौकर ऐसे थे जो काम में लाये जाने लायक थे । दूसरी ओर से एक ट्रक आ रही थी, उसकी रोशनी पर ड्राइवर ने उसको मोड़ा और वह एक पुलिया से टकरा कर गिर गया ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एक वर्ष हो जाने के बाद भी मृतक लोगों के कुटुम्बियों को सहायता अभी तक क्यों नहीं दी गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—विभाग की ओर से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिख दिया गया है कि एक के परिवार को ३,५०० रुपये और दूसरे के परिवार को १,३५० रुपये मुआवजा दे दिया जाय । जिस समय वह स्वीकार हो जायगा, मुआवजा दे दिया जायगा ।

आजमगढ़ जिले में खादी केन्द्रों पर व्यय

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मन्त्री आजमगढ़ जिले के खादी केन्द्रों के विषय में २६-८-५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १९, २० और २१ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि खोले गये सभी खादी केन्द्रों पर अलग-अलग कितना-कितना रुपया मासिक प्रत्येक मद में व्यय होता है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—प्रत्येक खादी केन्द्र पर हर माह औसत खर्च लगभग २५० रुपया होता है । मदों का विवरण यों हैं :

	रुपया
१—कर्मचारियों का वेतन	७०
२—स्थानीय कार्यकर्त्ताओं के वेतन के लिये अनुदान ..	१४०
३—मकान का किराया	१५
४—अन्य फुटकर व्यय	२५

उक्त व्यय में सूत खरीद पर दी जानेवाली सहायता तथा चर्खा वितरण शामिल नहीं है ।

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मझवारा खादी केन्द्र को सहायता कब दी गई है तथा ग्राम कार्यकर्त्ताओं को मासिक कितना-कितना वेतन मिलता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मझवारा सरकारी खादी केन्द्र पर प्रत्येक गुन्डी पर दो-दो आने की सरकारी सहायता का धन कब-कब और कितना-कितना दिया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

आगरे में टर्मिनल डिस्ट्रीब्यूटरी पर पैदल पुलिया का टूट जाना

*६—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में टर्मिनल डिस्ट्रीब्यूटरी (१ मील ६ फर्लांग) पर पैदल पुल को टूटे हुये कितना समय होगया और उसके अब तक न बन सकने का क्या कारण है ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति) (अनुपस्थित)—टर्मिनल डिस्ट्रीब्यूटरी मील १ फर्लांग ६ पर पैदल पुलिया बरसात में टूट गई थी और उसे टूटे हुये ६ महीने हुए हैं।

जनता की सम्मिलित स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कि किस स्थान पर पुलिया फिर से निर्माण की जाय, देर हो रही थी। अब पुलिया का निर्माण शुरू कर दिया गया है।

*७—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में टर्मिनल डिस्ट्रीब्यूटरी से सन् १९५७ में कितनी चैनलें निकाले जाने की योजना थी, वे कौन-कौन सी चैनलें थीं, उनकी अलग-अलग क्या लम्बाई होगी और उनका कार्य कब तक पूरा हो सकेगा ? सन् ५८ में इस डिस्ट्रीब्यूटरी से कितनी नई चैनलें और निकाले जाने की योजना है वे कहां-कहां पर होंगी और उनकी अलग-अलग लम्बाई क्या होगी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—सन् १९५७ में टर्मिनल डिस्ट्रीब्यूटरी से चैनल निकालने की कोई योजना नहीं थी। माइनर बमरौली अहीर फतिहाबाद और रामगढ़ के क्षेत्र का सर्वे किया जा रहा है और अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था टर्मिनल डिस्ट्रीब्यूटरी से की जा सकेगी या नहीं।

फतेहपुर सीकरी रजबहे से पलेवा चैनलों का निकाला जाना

*८—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर सीकरी रजबहे से जिसका रिमाडलिंग किया जा रहा है और जिसकी अनुमानित लागत साढ़े पांच लाख से ऊपर है कौन-कौन सी पलेवा चैनलें निकाली जा रही हैं और उनकी अलग-अलग लम्बाई क्या होगी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—रजबहा फतेहपुर सीकरी पर निम्नलिखित पलेवा चैनलें बनाई जा चुकी हैं।

	लम्बाई		
	मील	फर्लांग	फीट
१—पुरा माइनर	१	५	३३०
२—साधन ,, ...	२	२	
३—भंडौली	२	०	३३०
४—बासैया बोलवा	०	४	३३०
५—जगौरा माइनर	२	४	३३०
सन् १९५८ में रजबहा फतेहपुर सीकरी से औल माइनर जिसकी लम्बाई	०	०	३३०

है, के बनाये जाने की योजना है।

*९-१०--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--[स्वशासन मन्त्री से सम्बन्धित सातवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १०८-१०९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

आजमगढ़ जिले में बुनकरों की करघा सहकारी समिति, मिश्रपुर को अनुदान के लिए मांग

*११--श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)--क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के मिश्रपुर नामक स्थान पर बुनकरों की सहकारी समितियों द्वारा तैयार किये गये कपड़े की बिक्री की व्यवस्था के लिये आढ़त खुलवाने के लिये अनुदान देने का विचार कर रहे हैं ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)--जी नहीं ।

*१२--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या उद्योग मन्त्री आजमगढ़ जिले में बुनकरों की करघा सहकारी समितियों को सहायता के सम्बन्ध में प्रश्न संख्या ७०, दिनांक २-९-५७ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि वे तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के मिश्रपुर सोसाइटी को ग्रान्ट रिबेट उन्नतशील यन्त्रों की सहायता देने का विचार कर रहे हैं ?

श्री रऊफ जाफरी--इस सोसाइटी ने ग्रान्ट, रिबेट और उन्नतशील यंत्रों के लिये मांग की है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

*१३--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार की ओर से हेड आफिस कानपुर से कोई सरकुलर जारी किया गया है कि हैन्डलूम के समस्त कपड़ों पर अब किसी प्रकार का रिबेट न दिया जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी--(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में बुनकर सहकारी समितियों द्वारा तैयार किये गये कपड़े की बिक्री के लिये कहां कहां आढ़त और बिक्री-केन्द्र खुले हैं और सरकार द्वारा उनको क्या अनुदान दिया जाता है ?

श्री रऊफ जाफरी--यह सवाल एक खास सोसाइटी से सम्बन्धित है । उस सोसाइटी का सेल डिपो महाराजगंज में खुला है । जहांतक दो आने गुण्डी देने का सवाल है, सन् १९५६ में ४,००० रुपये उस सोसाइटी को सेल डिपो खोलने के लिये दिया गया है । वर्किंग कैपिटल के लिये काफी लोन दिया जाता है और जहां तक उनके यन्त्रों के सिलसिले में सवाल है, उस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मिश्रपुर सोसाइटी कब कायम हुई है ?

श्री रऊफ जाफरी--इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हैन्डलूम के सूत पर से सेल्स टैक्स हटाने के सिलसिले में सरकार के पास कोई रिप्रेजेंटेशन आया हुआ है ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां, रिप्रेजेंटेशन आया हुआ है ।

श्री भगवती सिंह विशारद--यदि इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुआ है तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—उस पर विचार हो रहा है ।

विधायक निवासों में टेलीफोन एक्सचेंज टूटने से असुविधा

*१४—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवासों में से टेलीफोन एक्सचेंज तोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—टेलीफोन के आटोमेटिक सिस्टम (Automatic system) हो जाने के बाद विधायक निवास का एक्सचेंज तोड़ दिया गया क्योंकि यह असुविधाजनक तथा महंगा पड़ा ।

*१५—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टेलीफोन से सम्बन्धित टेलीफोन एक्सचेंज के समय कितना स्टाफ था और अब कितना है ?

श्री धर्मसिंह—विधायक निवास में एक्सचेंज के समय ४ टेलीफोन आपरेटर तथा १२ टेलीफून अटेन्डेन्ट थे । इस समय ३ टेलीफोन आपरेटर हैं जो एन्क्वायरी क्लर्क तथा रिप्शनिस्ट कहे जाते हैं और १२ टेलीफून अटेन्डेन्ट हैं ।

*१६—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार टेलीफोन एक्सचेंज टूट जाने से जो असुविधा सदस्यों को हो रही है उस कठिनाई को मिटाने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—टेलीफोन एक्सचेंज तोड़ देने के कारण सरकार के पास सदस्यों से कोई शिकायत नहीं आयी है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि स्वयं उनसे कुछ सदस्य मिले थे और उन्होंने इस दिक्कत को उनसे बताया था और उन्होंने इसकी फाइल को भी मंगाया था?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये जहां तक मेरा सम्बन्ध है कोई माननीय सदस्य नहीं मिले ।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यदि कोई सज्जन बाहर से दारुलशफा को टेलीफोन करना चाहें तो एकदम बात नहीं कर सकते बल्कि उनका नम्बर नोट कर लिया जाता है और फिर उस सदस्य को टेलीफोन करना होता है ?

श्री धर्मसिंह—इस तरह की कोई शिकायत तो नहीं आयी है और यदि कोई असुविधा होती है तो उस पर विचार किया जायगा और उसपर कार्यवाही की जायगी ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि आज कल दो आने का क्वायन (सिक्का) नहीं मिलता और आटोमेटिक सिस्टम में दो आने का क्वायन डालने पर ही बात हो सकती है, इस वजह से बड़ी असुविधा होती है ?

श्री धर्मसिंह—जहां तक दो आने का क्वायन न मिलने का सवाल है वह तो मिलता है बहुत आसानी से और जब मिलता है तो उसमें दिक्कत क्या है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफफरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने प्रश्न संख्या १४ के उत्तर में यह कहा है कि महंगाई के कारण उसको समाप्त करना पड़ा तो इस प्रकार कितनी बचत सरकार को हुई ?

श्री धर्मसिंह—पहले जब एक्सचेंज था तब १३,६२० रुपया खर्च होता था, अब वह १०,४७६ रुपया खर्च होता है ।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास नम्बर ३ में न ट्रंककाल की सुविधा है और जो वहां एक टेलीफोन है वह भी कई महीने से सस्पेंडेड है ?

श्री धर्मसिंह---अब इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है। यह ज्ञात नहीं है कि वहां खराब पड़ा है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि सदस्यों को एक टाक के लिये ४ आने पैसे देने पड़ते हैं जबकि दूसरों को दो ही आने पड़ते हैं ?

श्री धर्मसिंह---जी ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा नियम नहीं है कि चार आने कोई भी दे और यदि इस तरह की कोई शिकायत है तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि विधायक निवास नम्बर ४ में जो फेमिली सूट्स बने हुए हैं उनके लिए टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं है?

श्री धर्मसिंह---जहां तक नम्बर ४ का सम्बन्ध है यदि रायल होटल से मतलब है तो वहां तो टेलीफोन है।

गोरखपुर जिले की रोहिन नहर के सम्बन्ध में पूछताछ

*१७---श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रोहिन कैनाल जो गोरखपुर जिले में बनी है उसमें कुल कितना खर्च हुआ है और उसका कमान्ड एरिया कितना है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---रोहिन कैनाल पर १९५६-५७ के अन्त तक निर्माण कार्य पर ८,५६,५८१ रुपया व्यय हो चुका है और इस नहर का क्रमानुसार एरिया निम्नलिखित है :

	एकड़
धान	३,२६२
गन्ना	१०९
अन्य खरीफ	३२६
रबी	३,९१४
योग ..	७,६११

*१८---श्री अब्दुल रऊफ लारी (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कैनाल से १ अप्रैल, १९५३ से ३० मार्च, १९५७ तक सालाना कितनी आमदनी हुई और क्या खर्चा पड़ा ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---रोहिन कैनाल से १ अप्रैल, १९५३ से ३० मार्च, १९५७ तक निम्नलिखित आमदनी और खर्चा हुआ :---

वर्ष	आमदनी (रुपयों में) रबी	खरीफ	मिश्रित	योग रबी-खरीफ	व्यय (रुपयों में)
१९५३-५४ ..	१४,१६०	१२,४७०	३५८	२६,६३०	४९,९९६
१९५४-५५ ..	६,८६९	२९,६०२	३६१	३६,४७१	८,३८९
१९५५-५६ ..	७,५३५	२७२	३६३	७,८०७	२४,२१८
१९५६-५७ ..	६,७७८	३९२	१,२९८	७,१७०	११,२७९
योग ..	३५,३४२	४२,७३६	२,३८०	७८,०७८	९३,८८२

*१९--श्री अब्दुल रऊफ लारी (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोहिन कैनाल में जनवरी के बाद पानी की कमी को रोकने के लिये वह क्या उपाय कर रही है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--रोहिन नहर में जनवरी और विशेषतया मार्च के पश्चात् पानी की कमी को रोका नहीं जा सकता । यह नहर रोहिन नदी से निकलती है जिसका मूल स्रोत बर्फीला पानी न होने के कारण तथा नैपाल की सीमा में नदी में बांध बांध देने के कारण पानी की कमी हो जाती है ।

राजकीय पोलीटेकनिक, गाजीपुर में हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों के लड़कों की भर्ती

*२०--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार कृपा कर बतावेगी कि गाजीपुर राजकीय टेक्निकल स्कूल में शिक्षा पाने के लिये कितने लड़कों के प्रार्थना-पत्र सन् १९५७ में आये थे ?

श्री रऊफ जाफरी--राजकीय पालीटेकनिक, गाजीपुर में शिक्षा पाने के लिये ५५० लड़कों के प्रार्थना-पत्र सन् १९५७ में आये थे ।

श्री यमुनासिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन आये हुए प्रार्थनापत्रों में से कितने हरिजन और कितने पिछड़ी जाति के लड़के चुने गए ?

श्री रऊफ जाफरी---७ हरिजन और २५ पिछड़ी जातियों के। कुल दाखिला जो था वह ५७ था और उसमें ३२ यह दोनों मिलाकर के थे ।

श्री यमुनासिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कुल कितनी सीटें हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने बता दिया, ५७ ।

*२१--श्री यमुना सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्रों में कितने हरिजन तथा कितने पिछड़ी जाति के लड़कों के प्रार्थना-पत्र आये थे ?

श्री रऊफ जाफरी---उपरोक्त आवेदन-पत्रों में १७ हरिजन तथा ७१ पिछड़ी जाति के लड़कों के प्रार्थना-पत्र आये थे ।

*२२--श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर आठवें सोमवार, ३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२३--श्री प्रतापसिंह--[श्रम मंत्री से सम्बन्धित पांचवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ९२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२४--श्री प्रतापसिंह--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर आठवें सोमवार, ३ मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

बलिया जिले में चकरा स्थित नलकूप में खराबी की शिकायत

*२५--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला में चकरा स्थित नलकूप नम्बर ११ सदैव बिगड़ा रहता है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---जी नहीं ।

*२६--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)---यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इसके ठीक करने के लिये क्या किया गया है और उसके क्या परिणाम हुये हैं ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

बस्ती जिले की खलीलाबाद शुगर मिल को हटाने पर विचार

*२७--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि खलीलाबाद, बस्ती, शुगर मिल को हटाकर कहीं अन्यत्र ले जाये जाने का निश्चय हो चुका है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---नहीं । अभी मामला सरकार के विचाराधीन है ।

गन्ने की उपज तथा पेराई

*२८--श्री जगदीश शरण अग्रवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष सरकार की ओर से किन-किन क्षेत्रों में चीनी मिलें जल्दी चलाने का यत्न हुआ ?

श्री रऊफ जाफरी---इस वर्ष प्रदेश में गन्ने की अधिकता न होने से चीनी मिलों को जल्दी चलाने की बाबत कोई छूट तो दी नहीं गई परन्तु इन्हें जल्दी चलाने के लिये चीनी मिलों के मालिकों से अनुरोध किया गया ।

*२९--श्री जगदीशशरण अग्रवाल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के गन्ने की इस वर्ष की उपज के बारे में क्या अनुमान है और उसकी खपत कब तक होने की आशा है ?

श्री रऊफ जाफरी---इस वर्ष प्रदेश में गन्ने की उपज अनुमानतः लगभग ५९.२४ करोड़ मन है और वह गन्ना जो चीनी मिलों में ले जाया जायगा, अगले मई तक क्रश हो जाने का अन्दाजा किया जाता है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस ५९.२४ करोड़ मन गन्ने का जो अनुमान है इस में से मिलों द्वारा कितना क्रश होगा और खंडसारी कारखानों द्वारा कितना ?

श्री रऊफ जाफरी---इसमें से साढ़े २७ करोड़ मन मिलें क्रश करेंगी ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन मिलों से किन-किन क्षेत्रों में सरकार ने मिलें जल्दी चलाने का अनुरोध किया था ?

श्री रऊफ जाफरी---वह तो सब जगह किया गया था और उसी के नतीजे पर इस साल २३ मिलें १५ नवम्बर से चल गई थीं जबकि पछले साल ५ आने का कन्सेशन देने पर भी केवल २२ मिलें ही चली थीं ।

*३०-३२--श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)---[स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़ जिले की तहसील के खजान्चियों को ५ रुपये की वेतन-वृद्धि न मिलने की शिकायत

*३३---श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि १०० रुपये मासिक से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की जो ५ रुपये वेतन वृद्धि हुई है उसमें तहसीलों के खजांची इससे वंचित कर दिये गये हैं ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं ।

*३४—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—यदि हां, तो क्या सरकार कृपा करके इसके कारणों पर प्रकाश डालेगी ?

श्री धर्मसिंह—यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की तहसील के खजान्चियों को यह ५ रुपए की बढ़ोत्तरी दी गई है या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये सूचना चाहिये ।

आजमगढ़ जिले के गम्भीरबन ताल से नाला निकालने की योजना

*३५—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या आजमगढ़ जिले के गंभीर बन, भैंसाताल, से एक नहर निकालने का निर्णय किया गया है ? यदि हां, तो वह नहर कब तक बनना प्रारम्भ होगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, गम्भीर बन ताल से नहर नहीं बल्कि एक नाला निकालने के बारे में सर्वे किया जा चुका है । इस नाले का कार्य एस्टीमेट स्वीकृत हो जाने पर आरम्भ किया जा सकेगा ।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—क्या यह एस्टीमेट बरसात से पहले तैयार हो जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—एस्टीमेट तो तैयार किया जा रहा है । उसकी स्वीकृति जल्दी ही हो जायगी और काम भी जल्द ही शुरू हो जायगा ।

एटा जिले में खुलने वाले उद्योग

*३६—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से नये उद्योग खोले जा रहे हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—चर्म उद्योग, ताड़ गुड़ उद्योग तथा हथकरघा उद्योग ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये उद्योग किन-किन स्थानों पर खोले जा रहे हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—चर्म उद्योग तो बढ़नी (रामपुर), घनश्याम और बदरिया में हैं । उनके लिये सहकारी समितियां चल रही हैं और उनको अनुदान और लोन्स दोनों दिये गये हैं । इनके अलावा सजावलपुर में अभी जारी नहीं हुआ है । सामान इकट्ठा है । जब वह चालू हो जायगा तो वहां पर ट्रेनिंग का काम शुरू किया जायगा ।

ताड़ गुड़ के लिये राजा का रामपुर, अलीगंज तहसील म ट्रेनिंग दी जा रही है । ट्यूशनल क्लासेज अलीगंज में चल रहे हैं । वहीं उसका प्रोडक्शन सेन्टर भी है ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—यह उद्योग कबतक खुल जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी—माननीय सदस्य यह बतावें कि वे किस उद्योग के लिये पूछ रहे हैं । टैनरी के उद्योग का जहां तक सम्बन्ध है वह तो अलीगंज से बदलकर शीतलपुर में जाने वाली है ।

बरेली–मथुरा सड़क पर न्योली शुगर मिल के निकट बैलगाड़ियों की पार्किंग का प्रबन्ध न होना

*३७—श्री श्री कृष्ण गोयल—क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली-मथुरा रोड पर न्योली शुगर मिल के आस-पास सीजन में बैलगाड़ियों के सड़क पर खड़ी होने से चार पांच घंटे तक यातायात रुका रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका उचित प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री रऊफ काफरी—पिछले वर्षों में अक्सर न्योली शुगर मिल में ब्रेक डाउन हो जाने के कारण बरेली-मथुरा रोड पर बैलगाड़ियों की भीड़ हो जाने से यातायात में कुछ रुकावट हो जाया करती थी परन्तु वर्तमान सीजन में इस मिल द्वारा बैलगाड़ियों की पार्किंग का उचित प्रबन्ध कर दिया गया है ।

श्री श्री कृष्ण गोयल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि न्योली शुगर मिल के सामने उचित पार्किंग का प्रबन्ध न होने के कारण यह रुकावट होती है और इस वर्ष भी अकसर हो जाती है ?

श्री रऊफ काफरी—हां, इस वर्ष भी हो जाती है, यह बात तो सही है लेकिन अकसर नहीं होती और यह कोशिश की जा रही है कि पार्किंग की जमीन न्योली शुगर मिल और बढ़ा दे ताकि दिक्कत न हो ।

बांदा जिले के कर्वी मऊ क्षेत्र में सिंचाई के साधनों की कमी

*३८—श्रीमती सिया दुलारी (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के कर्वी क्षेत्र में सिंचाई के कौन-कौन साधन उपलब्ध किये जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—कर्वी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिये पिछले वर्ष ३ बंधियां बनाई गई थीं और ओहन बांध की नहरें बनाई जा रही हैं ।

इसके अतिरिक्त पैसुनी नदी पर बांध बनाने की योजना का सर्वेक्षण हो रहा है ।

*३९—श्रीमती सियादुलारी (अनुपस्थित)—क्या यह बात सत्य है कि सिंचाई के अल्प साधनों के कारण जिला बांदा में कर्वा-मऊ क्षेत्र में अन्नाभाव बना रहता है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—जी हां, कुछ सीमा तक ।

गाजीपुर जिले की मुहम्मदाबाद तहसील में मंगई नदी का सर्वे

*४०—श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में जो बाढ़ विभाग बलिया के सब-डिवीजन गाजीपुर द्वारा मंगई नदी के लेफ्ट बैंक व राइट बैंक का सर्वे गाजीपुर जिले की मुहम्मदाबाद तहसील में हुआ उसमें कितना रुपया खर्च हुआ ।

श्री रामस्वरूप यादव—सन् १९५५ और ५६ में बाढ़ विभाग बलिया के उप-विभाग गाजीपुर द्वारा मंगई नदी के बायें एवं दायें बैंक के सर्वेक्षण पर कुल व्यय ३१० रुपये १० आना हुआ है ।

*४१—श्री रूम सिंह—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह सर्वे कितने ओवर-सियरों ने किया और प्रत्येक ने सर्वे में कितना कितना व्यय किया, और इस सर्वे में जो संबंधित ओवरसियरों ने मस्टर-रोल बनाये उनमें जिन मजदूरों के नाम दिये गये हैं, क्या सरकार उनकी जांच करायेगी कि वे नाम व उनकी वल्दियत सही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस कार्य में सर्वेक्षण कार्य तीन ओवरसियरों द्वारा किया गया जिसमें से प्रथम ने एक सौ साठ रुपया दस आना, द्वितीय ने साठ रुपया और तृतीय ने नब्बे रुपया व्यय किया। मस्टर रोल में वल्दियत मजदूरों के बताने के हिसाब से लिखी है इस समय इसकी दोबारा जांच करना संभव नहीं है ।

श्री धर्मसिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सर्वे से क्या लाभ हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव--सर्वे तो इस संबंध में कराया जा रहा है कि इससे यहां पर कोई योजना चलायी जा सकती है या नहीं ।

श्री धर्मसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह योजना चलायी गयी या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस संबंध में नोटिस की आवश्यकता है ।

गोंडा जिले में करनैलगंज को बिजली देने का आयोजन

*४२--श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल (जिला गोंडा)--क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि करनैलगंज (गोंडा) में बिजली पहुंचाने का कब तक लक्ष्य है तथा सरकार कितना धन उक्त कार्य के लिये व्यय करेगी ?

श्री धर्मसिंह--आशा की जाती है कि इस नगर का विद्युतीकरण मार्च, १९५८ के अन्त तक हो जायगा। व्यय लगभग ३ लाख रुपया होगा।

गाजीपुर जिले में गंगा के कटाव को रोकने की प्रार्थना

*४३--श्री यमुनासिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में गंगा से कटने वाली जमीन के बचाव के लिये उसने अब तक क्या क्या प्रयत्न किये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री यमुनासिंह--क्या यह सही है कि गाजीपुर छावनी लाइन में इस वर्ष सैकड़ों बीघे जमीन गंगा में टूट कर चली गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव--नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार के पास वहां के किसानों की या जिनका खेत कट कर गंगा में चला गया है उनकी ओर से कोई प्रार्थना-पत्र आया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस वक्त इसकी सूचना नहीं है। सूचना मिलने पर जवाब दिया जा सकता है।

*४४-४६--श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--[स्थगित किये गये ।]

*४७-४८--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--[श्रम मंत्री से संबंधित तेरहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का खर्च

*४९--श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश के विद्युत् गृहों द्वारा उत्पादित विद्युत् का कितना प्रतिशत इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान में व्यय होता है ?

श्री धर्मसिंह--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनुमानतः कितने समय में वह सूचना एकत्र हो जायगी और दी जायगी ?

श्री धर्मसिंह---सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और एक्जिक्यूटिव इंजीनियर को लिख कर भेजा गया है और यह कोशिश की जा रही है कि सूचना जल्दी से जल्दी एकत्र की जा सके।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी मिर्जापुर से संबंधित आय-व्यय

*५०---श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, मिर्जापुर के निर्माण (बिल्डिंग) और सज्जा दोनों श्रमिक आवास व चिकित्सालय पर सरकार का कितना धन व्यय हुआ ?

श्री रऊफ जाफरी---१,१८,५७,७३५ रुपये ।

*५१---श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या सरकार यह बतायेगी कि इस कारखाने की स्थापना (Establishment) पर १९५६-५७ में कितना व्यय हुआ है तथा उपर्युक्त वर्ष में कितने रुपये का सीमेंट इस कारखाने से उत्पादित हुआ है ?

श्री रऊफ जाफरी---फैक्ट्री की स्थापना पर १९५६-५७ में १७,५३,४२४ रुपये व्यय हुआ। उक्त वर्ष में १,९७,४२३ टन अर्थात् १,७९,१६,२४८ रुपये मूल्य के सीमेंट का उत्पादन हुआ।

श्री गंगा प्रसाद सिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १,१८,५७,७३५ रुपये में कितना श्रमिक आवास और अस्पताल पर खर्च हुआ ?

श्री रऊफ जाफरी---लेबर कालोनी पर ११,६८,०४८ रुपया एक हिसाब में खर्च हुआ है और कुछ है जिसका अलग नहीं है। स्टाफ और लेबर के लिये खर्च हुआ है १०,५५,१७० रुपये, अस्पताल के सिलसिले में १,४६,८४२ रुपये खर्च हुये हैं।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह धन जो श्रमिकों के आवास के लिये खर्च किया गया है उससे कितने क्वार्टर्स और चिकित्सालय में कितनी शैय्याओं का प्रबन्ध हुआ ?

श्री रऊफ जाफरी---इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री गेंदासिंह---अब तक कोई बैलेंस शीट इस फैक्ट्री की तैयार हुई है या नहीं ?

श्री रऊफ जाफरी---जी हां, बैलेंस शीट तैयार होती है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष उत्पादन बढ़ने पर भी सीमेंट की कीमत बढ़ गयी है ? इसका क्या कारण है कि उत्पादन व्यय भी बढ़ा और कीमत भी बढ़ी ?

श्री रऊफ जाफरी---सीमेंट की कीमत का जहां तक ताल्लुक है वह तो केंद्रीय सरकार मुकर्रर करती है। वह सब जगह को देख कर हिसाब करके जो कैपिटल व्यय होता है उस लिहाज से मुकर्रर कर देती है।

उत्पादन का खर्च जो है, तो उत्पादन ज्यादा हुआ इसलिये खर्चा ज्यादा हो गया ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि १९५५-५६ में १,७७,५०० टन सीमेंट तैयार हुई और ५६-५७ में.....

श्री अध्यक्ष---यह आप कहां से पढ़ रहे हैं ? जो उत्तर मिला है उसमें तो नहीं है। क्या आप किसी किताब में से पढ़ रहे हैं ?

श्री भगवतीसिंह विशारद---यह तो मैंने याददाश्त के लिये लिख लिया है, वही है जो उत्तर में दिया हुआ है। तो १९५५-५६ में १,७७,५०० टन सीमेंट तैयार हुई और १९५६-५७ में १,९७,४२३ टन...

श्री अध्यक्ष---उत्तर में १९५५-५६ का है ही नहीं, १९५६-५७ का दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न कीजिये।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि १९५५-५६ की अपेक्षा १९५६-५७ में सीमेंट का उत्पादन बढ़ा, लेकिन उसके साथ-साथ उत्पादन व्यय क्यों बढ़ गया ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं, क्योंकि यह प्रश्न का विषय नहीं था।

श्री गेंदासिंह---क्या वित्त मंत्री जी मेहरबानी करके इस बदइन्तजामी की, जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ने के साथ उत्पादन व्यय भी बढ़ा है, कोई जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न पैदा नहीं होता। उन्होंने जवाब दिया कि उत्पादन बढ़ा है, इसलिये खर्चा बढ़ा है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्पादन जिस अनुपात से बढ़ा है उस हिसाब से व्यय बढ़ा है या पर बोरी के हिसाब से व्यय बढ़ा है ?

श्री रऊफ जाफरी---जो व्यय बढ़ा वह दे दिया गया है, बाकी यह हिसाब सदस्य लगा लें। उसमें उत्पादन और व्यय दिया हुआ है, पिछले सालों के आंकड़े उनके पास हैं, उससे हिसाब लगा लें।

बलिया जिले में कठौड़ा ताल से वर्षा के पानी का निकास न होने से क्षति

*५२---श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)---क्या सरकार को ज्ञात है कि कठौड़ा-ताल (बलिया) से वर्षा काल में पानी का समुचित निकास न होने से किसानों की हजारों एकड़ फसल डूब कर नष्ट हो जाती है तथा बहुत से गांव चारों ओर से ताल के पानी से घिर जाते हैं ? यदि हां, तो सरकार जल निकास का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---बलिया जिले में घाघरा नदी के किनारे कठौड़ा ग्राम के निकट बढ़का ताल नाम का एक ताल ५ से ६ वर्ग मील के कैचमेंट का है। एक नाला इस ताल से घाघरा नदी तक है जो उस ताल का पानी घाघरा नदी में गिरा देता है। कुछ वर्षों पूर्व इस ग्राम के निकट घाघरा नदी के किनारे एक रिंग बांध बनाया गया था और इस प्रकार नाले का मार्ग भी बन्द हो गया। बहुत दिनों से वर्षा काल में घाघरा नदी के पानी को रोकने के लिये वे किसान उस रिंग बांध की मरम्मत वर्षा ऋतु के पूर्व ही कर लेते थे और जब घाघरा नदी की धारा नीची हो जाती थी, वे लोग ताल के एकत्रित पानी को बांध काट कर निकाल देते थे और दुबारा कटे हुए स्थान को बन्द कर देते थे।

वर्तमान प्रबन्ध संतोषजनक है क्योंकि रेग्यूलेटर के निर्माण की लागत १.५ लाख रुपये होगी जोकि लागत और लाभ को दृष्टि में रखते हुये आवश्यक नहीं प्रतीत होगा।

श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कठौड़ा ताल के किनारे कितने गांव पड़ते हैं और कितने एकड़ भूमि की फसल का प्रति वर्ष नुकसान होता है ?

श्री रामस्वरूप यादव—कितने गांव पड़ते हैं, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है, लेकिन बाकी यह है कि नुकसान हमेशा नहीं होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसान बांध काट लेते हैं और बन्द नहीं कर पाते हैं तो पानी आ जाता है।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या यह सही है कि जो रिंग बांध बना है, उससे काम नहीं चलता है इसलिये किसानों का कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र आया है कि ऐसा रेग्यूलेटर बना दिया जाय ताकि बरसाती पानी निकल जाय? यदि हां, तो सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने तो निवेदन कर दिया कि रेगुलेटर की मांग आई थी लेकिन वह सरकार की दृष्टि से लाभदायक नहीं है इसलिये उसके बनवाने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बांध के पड़ोस में कितनी जमीन ऐसी है जिसमें किसान रबी की फसल बो पाते हैं और पानी की अधिकता के कारण खरीफ की फसल नहीं बो पाते हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा नहीं है, पानी अधिक नहीं हो पाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि बांध खोल लेते हैं और बन्द नहीं कर पाते हैं, तब कुछ हिस्सा जलमग्न हो जाता है।

*५३—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—[हटा दिया गया।]

रामगंगा विद्युत् योजना के संबंध में जानकारी

*५४—श्री दीनदयालु शास्त्री (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रामगंगा विद्युत् योजना कितने वर्षों में पूर्ण हो जायगी और उससे कितने एकड़ भूमि का सिंचन होगा एवं कितनी बिजली मिलेगी?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—यदि पूर्ण धनराशि की व्यवस्था हो जाय तो तृतीय योजना काल में पूर्ण होने की आशा है। यह योजना पूर्ण होने पर ७ लाख एकड़ नये क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना से ७५,००० किलोवाट जल विद्युत् शक्ति उत्पन्न हो सकेगी।

हरद्वार में सब-ट्रेजरी न खुलना

*५५—श्री दीनदयालु शास्त्री (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरद्वार में उसका सब-ट्रेजरी खोलने का विचार है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह प्रश्न नहीं उठता। सब-ट्रेजरी आम तौर से तहसील हेडक्वार्टर्स पर ही खोली जाती है। चूंकि हरद्वार में इस समय कोई तहसील नहीं है इसलिये वहां सब-ट्रेजरी खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

कोसी कलां, जिला मथुरा में बिजली की दर बढ़ाना

*५६—श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोसी कलां, जिला मथुरा में बिजली का रेट पहली दिसम्बर, १९५७ से ८ आने से बढ़ाकर १२ आने प्रति यूनिट करने का क्या कारण है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--कोसी कलां जिला मथुरा में बिजली कोसी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा दी जाती है। यह कम्पनी कई वर्षों से बराबर घाटे पर चल रही है। एलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) अमेंडमेंट ऐक्ट, १९५६ की धारा २७ के अनुसार बिजली कम्पनियां उचित मुनाफा कमाने के उद्देश्य से अपनी दरें घटाने या बढ़ाने के लिये स्वतंत्र हैं, जब तक उनका मुनाफा निर्धारित सीमा से न बढ़े। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले सरकार कम्पनी की दरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

*५७--श्री त्रिलोकी सिंह (अनुपस्थित)--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सिलसिले में स्थानीय म्युनिसिपल बोर्ड व वहां के नागरिकों ने सरकार के पास क्या दरख्वास्त दी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--म्युनिसिपल बोर्ड तथा नागरिकों ने सरकार से निवेदन किया था कि कम्पनी को रेट न बढ़ाने दिये जायें। नागरिकों ने इस सम्बन्ध में एक जांच कमेटी बैठाने तथा कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करके बिजली का रेट घटाने के लिए भी प्रार्थना की थी।

सपरार नहर में ली गयी जमीन का मुआवजा

*५८--श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम भटपुरा, रोरा, धवाकर, चकारा, मऊरानीपुर तहसील के मौजों की जमीन को काट कर सपरार नहर निकाली गई है ? यदि हां, तो क्या उन ग्रामों के काश्तकारों को उनकी जमीन का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक उसका वितरण किया जावेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, अधिकांश काश्तकारों को मुआवजा दिया जा चुका है और बचे हुये काश्तकारों को दिया जा रहा है।

*५९--श्रीमती बेनीबाई--क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जहां से मिट्टी काट कर सपरार नहर निकाली गयी है वह जमीन गहरी झील हो गयी है और उस जमीन में पानी भरा रहता है जिससे पैदावार को हानि पहुंचती है ? क्या उस पानी को निकलवाने का सरकार इरादा रखती है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, भटपुरा, रोरा व धवाकर ग्रामों में कुछ निचाई हो गई है, अधिकांश भाग में भूमि जोत कर ठीक हो गई है मगर फिर भी कुछ भाग में पानी भर जाता है। इस पानी के निकास के लिये नाली खोदने की आज्ञा दे दी गई है।

श्रीमती बेनीबाई--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बचे हुये किसानों को मुआवजा कब तक दे दिया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--जल्दी ही दे दिया जायगा। हिसाब बन रहा है और जैसे जैसे हिसाब बनता जाता है मुआवजा दे दिया जाता है।

श्रीमती बेनीबाई--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरसात के पूर्व ही पानी के निकास के लिये नाली बना दी जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--हां, ऐसा ही इरादा है कि बरसात शुरू होने से पहले ही यह कार्य समाप्त हो जाय।

श्री गेंदासिंह--यह जमीन कब से सरकार ने ले ली है और मालगुजारी क्या किसानों को देनी पड़ती है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जिन किसानों ने मालगुजारी दे दी है वह मुआवजे के साथ वापस दे दी जायगी।

श्री गेंदासिंह---क्या यह बताना सम्भव होगा कि कितने दिनों से जमीन ले ली गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है । संभवतः १९५३ में कार्य आरम्भ हुआ था, इसके बाद ली गई होगी।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन किसानों को मुआवजा दिया है उनको खाता खतौनी से खारिज करने का कोई हुक्म जारी हुआ है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---वह तो साथ में ही अमलदरामद भी हो जाता है और जहां अमलदरामद हो जाता है वहां मालगुजारी नहीं वसूल हो रही होगी।

आगरे में नोनिहाई के निकट औद्योगिक आस्थान का आयोजन

*६०---श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरे में नोनिहाई के पास कोई उद्योग नगर बसाया जा रहा है ? यदि हां, तो किन किन उद्योगों के लिये ?

श्री रऊफ जाफरी---(क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित उद्योगों के लिये :
१---तेल के इंजिन तथा उनके पुर्जे बनाने के लिये,
२---कृषि संबंधी यंत्रों के बनाने के लिये,
३---रासायनिक उद्योग,
४---चमड़े के सामान बनाने के लिये,
५---टेक्सटाइल उद्योग,
६---लोहे तथा फौलाद उद्योग,
७---अन्य फुटकर उद्योग।

*६१---श्री रामसिंह चौहान वैद्य---इस नगर निर्माण में कितना काम हो चुका है और कितना काम इस वर्ष होने का अनुमान है ?

श्री रऊफ जाफरी---वांछित सूचना संलग्न है ।

*६२---श्री रामसिंह चौहान वैद्य---इस उद्योग नगर में कितने साझीदार हैं और उनसे कितना धन प्राप्त हो चुका है तथा सरकार कितना मुआवजा किसानों को दे चुकी है और कितना धन और लगा रही है ? क्या इसका पूरा विवरण सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी---इस स्टेट में ७८ प्लाट हैं जो विभिन्न उद्योगपतियों को उनकी आवश्यकतानुसार वितरित कर दिये गये हैं। प्लाटों के अलाटमेन्ट लेटर्स ५५ उद्योगपतियों को भेजे गये हैं जिनमें से अब तक केवल ३२ ने आवश्यक अग्रिम धन (Earnest Money) जमा कर दिया है।

औद्योगिक आस्थान आगरा में ५० प्रतिशत प्लाटों का अलाटमेन्ट उद्योगपतियों में किया जा चुका है। इन उद्योगपतियों ने आवश्यक अग्रिम धन (Earnest Money) जमा कर दिया है। भूमि को समतल करने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सड़कों के निर्माण के लिये आवश्यक सामग्री (Materials) के एकत्रीकरण के लिये टेन्डर आमंत्रित किये गये थे, जो अब पूर्ण किये जा चुके हैं। एक ठेकेदार (Contractor) को निर्माण का कार्य सौंप दिया गया है। प्रशासक, नगर प्रशासन विभाग (Administrator, Improvement Trust, Agra)

से अनुरोध किया गया है कि वे उन उद्योगपतियों की फैक्ट्रियों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दें। उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है कि उनकी फैक्ट्रियों का निर्माण नगर प्रशासन विभाग द्वारा हो। प्रशासक, नगर प्रशासन विभाग ने विभिन्न कोटि की फैक्ट्री-इमारतों के निर्माण के लिये टेन्डर आमंत्रित किये हैं, जो कि अब पूर्ण किये जा रहे हैं। निर्माण कार्य के प्रारम्भ होने की शीघ्र ही आशा है।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन फुटकर उद्योगों में कोई दूध और मक्खन का, डेरी का उद्योग भी वहां चलता है ?

श्री रऊफ जाफरी---जो 'अन्य उद्योग' कहा गया तो अभी अलाटमेंट तो हुआ नहीं, लेकिन गालिबन उसमें डेरी का कोई होगा नहीं।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य---जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि किसानों को मुआवजा दिया है तो क्या कुछ किसानों की ऐसी भी दरख्वास्तें आयी हैं कि उनको अभी मुआवजा नहीं मिला है ?

श्री रऊफ जाफरी---इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस उद्योगनगर में कोई उद्योग का ट्रेनिंग सेन्टर भी सरकार का खोलने का विचार है ?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं। यह तो जो लोग कारखाने चलाना चाहते हैं उनके लिये बना है।

बदायूं जिले के सलेमपुर परगने में सिंचाई के अपर्याप्त साधन

*६३---श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले में परगना सलेमपुर का कुल आबपाशी योग्य कितना रकबा है और उसके आबपाशी के क्या साधन हैं ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---जिला बदायूं के सलेमपुर परगना में कुल लगभग ५०,००० एकड़ भूमि सिंचाई योग्य है। इसमें से १०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई नदी, तालाब, झील तथा कच्चे या पक्के कूपों से होती है और ९,००० एकड़ भूमि की सिंचाई १० राजकीय नलकूपों द्वारा होती है। शेष ३१,००० एकड़ भूमि के लिये कोई सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं है।

*६४---श्री हरिश्चन्द्र सिंह (अनुपस्थित)---इस परगना सलेमपुर में कितने ट्यूबवेल बने और कब ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---इस परगना में कुल १० राजकीय नलकूप बने हैं। पांच नलकूप प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५५-५६ में बनाये गये थे और ५ नलकूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५६-५७ में बनाये गए थे।

*६५---श्री हरिश्चन्द्र सिंह (अनुपस्थित)---सरकार अगले चार सालों में कितने और ट्यूबवेल बनाने जा रही है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल १,५०० राजकीय नलकूप सारे उत्तर प्रदेश में बनाये जायंगे। इनका जिलेवार वितरण प्रतिवर्ष आवश्यक व्यय करने की स्वीकृति मिलने पर किया जाता है। अतः अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आगामी चार वर्षों में परगना सलेमपुर में कितने नलकूप और बनाये जायंगे।

*६६-६७—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—[श्रम मंत्री से सम्बन्धित छठवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १०६-१०७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जौनपुर जिले के चौराग्राम में चर्म उद्योग केन्द्र खोलने का विचार

*६८—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जौनपुर जिले की केराकत तहसील, चौरा ग्राम में चर्म उद्योग केन्द्र खोलने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री रऊफ जाफरी—(क) जी हां,

(ख) जल्दी।

श्री रामसमझावन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८ में यह केन्द्र खुल जायगा?

श्री रऊफ जाफरी—वहां फैक्टरी बनाने के लिये सामान इकट्ठा किया जा रहा है और जैसे ही वह इकट्ठा हो गया वह खुल जायगा।

*६९—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—[स्थगित किया गया।]

बिक्री कर विभाग में परिगणित जाति के अधिकारी बढ़ाने की मांग

*७०—श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५६-५७ में कितने सेल्स टैक्स अफसर भर्ती किये गये?

श्री धर्मसिंह—सन् १९५६-५७ में कोई बिक्री-कर अधिकारी भर्ती नहीं किया गया।

*७१—श्री रामजीलाल सहायक—क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेल्स टैक्स विभाग में कितने सेल्स टैक्स अफसर, असिस्टेन्ट सेल्स टैक्स अफसर तथा अन्य कर्मचारी कार्य करते हैं?

श्री धर्मसिंह—मांगी हुई सूचना नीचे दी हुई है:

१—बिक्री कर अधिकारी	६७
२—सहायक बिक्री-कर अधिकारी	१३७
३—अन्य कर्मचारी	१,८९१
कुल ..	२,०९५

*७२—श्री रामजीलाल सहायक—क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सेल्स टैक्स विभाग में परिगणित जातियों का प्रतिनिधित्व १८ प्रतिशत है?

श्री धर्मसिंह—बिक्री-कर विभाग में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व २.२ प्रतिशत है।

श्री रामजीलाल सहायक—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संख्या में परिगणित जाति के बिक्री-कर अधिकारी कितने हैं?

श्री धर्मसिंह—६७ में केवल १ हैं।

श्री रामजीलाल सहायक—क्या सरकार परिगणित जाति के प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिये अभी हाल ही में हुये रिक्रूटमेंट में से परिगणित जाति के बिक्रीकर अधिकारी रख सकेगी?

श्री धर्मसिंह—जी हां, जो अभी रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें से उनके प्रतिनिधित्व के अनुसार ३ अधिकारी लेने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बिक्री-कर अधिकारियों का रिक्रूटमेंट डाइरेक्ट हुआ था या पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये हुआ है या एम्पलायमेंट एक्सचेंज के जरिये से हुआ है?

श्री धर्मसिंह—यह पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होता है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रकार से हरिजनों की भर्ती के लिये डिस्ट्रिक्ट सूचना अधिकारियों को सूचना दी जायगी ताकि वह हरिजनों को भरती करने के लिये सहायता दे सकें?

श्री धर्मसिंह—जहां तक सेल्स टैक्स के अधिकारियों का सम्बन्ध है उसके लिये तो मैंने निवेदन किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होता है, तो जिलों में कोई सूचना भेजने का कारण नहीं मालूम होता है।

*७३-७५—श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—[स्थगित किये गये।]

जमुना हाइडिल योजना पर अनुमानित व्यय

*७६—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमुना हाइडिल योजना में कुल कितनी धनराशि व्यय होगी?

श्री धर्मसिंह—वर्तमान अन्दाजा १९५९.३० लाख रु० है।

*७७—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उस पर कितना धन व्यय होगा और उसके पूरा होने की कब तक सम्भावना है?

श्री धर्मसिंह—५७० लाख रु०।

इस योजना की तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण होने की आशा की जाती है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस योजना पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि व्यय हुई और दूसरी पंचवर्षीय योजना में अभी तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है?

श्री धर्मसिंह—यह तो मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या वित्त मंत्री महोदय बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ५७० लाख रुपया व्यय होगा तो क्या इस योजना का दूसरा चरण, जो इस समय चल रहा है, वह समाप्त हो सकेगा?

श्री धर्मसिंह—जहांतक इस योजना का सम्बन्ध है उसके प्रथम चरण को इसमें नहीं लिया जा रहा है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—मैंने यह प्रश्न किया था कि जो इस योजना का दूसरा चरण इस समय लिया जा रहा है तो क्या वह इस योजना के अन्त तक समाप्त हो जायगा?

श्री धर्मसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि जमुना हाइडल योजना, प्लानिंग कमीशन ने सेकिंड चरण में लेने से इन्कार कर दिया है?

श्री धर्मसिंह--जी हां, जैसा मैंने अर्ज किया कि उन्होंने इन्कार कर दिया है और उसके बहुत से कारण हैं।

श्री राजनारायण--क्या सरकार बतलायेगी कि यह योजना कब से कार्यान्वित हुई ?

श्री धर्मसिंह--प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी चली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी इसमें कुछ कार्य हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार यह बतायेगी कि प्लानिंग कमीशन द्वारा इस योजना पर कार्य शुरू हो जाने के बाद भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसके न मिलाये जाने का क्या कारण है ?

श्री धर्मसिंह--धन की कमी ही कारण है। दूसरा कारण यह भी है कि पंजाब में कुछ नदियों पर बांध बनने की बात थी। यदि वह तय हो जाते हैं तो हमारे यहां जो यह प्रथम चरण में बनते, मुमकिन है कि उसमें ये हमारे पावर स्टेशन डूब जायं। इसलिये स्थगित करने की बात है।

बीड़ी उद्योग से संबंधित सम्पत्ति तथा व्यक्ति

*७८--श्री अर्जुन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार राज्य के बीड़ी मजदूरों की गणना कराने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं।

*७९--श्री अर्जुन पांडेय (अनुपस्थित)--क्या सरकार राज्य में बीड़ी उद्योग में लगी हुई पूंजी और इससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलता है इसका विवरण सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अनुमानतः बीडी उद्योग में ७२,००,००० रुपये की पूंजी लगी है तथा उससे लगभग ३७,००० व्यक्ति रोजी कमाते हैं।

मैनपुरी जिले की नलकूप निर्माण योजना

*८०--श्री अलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में १९५७-५८ व १९५८-५९ में कितने और कहां-कहां ट्यूबवेल बनाने की योजना है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैनपुरी जिले में सन् १९५७-५८ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ९ नलकूप निर्माण किये जावेंगे, उनका तहसीलवार और ग्रामानुसार विवरण निम्नांकित है--

तहसील मैनपुरी--४	
ग्राम ज्योती ..	२
ग्राम मनौना ..	१
ग्राम सोनई ..	१
तहसील शिकोहाबाद--४	
ग्राम खिरौर ..	१
ग्राम मंडोई ..	१
ग्राम कान्तरी ..	१
ग्राम धकनौरा ..	१
तहसील जसराना--१	
ग्राम गोपालपुर ..	१

इस जिले में सन् १९५८-५९ में प्रस्तावित नलकूपों की संख्या तथा स्थान के विषय में अभी निश्चय नहीं हुआ है।

श्री भलिखान सिंह---अध्यक्ष महोदय, पहले तो मुझे यह निवेदन करना है कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं आया है ।

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह ४ नलकूप, जो उनकी योजना है तहसील मैनपुरी में खोलने की, उनमें ज्योति के पास ऐसा एरिया बच जाता है कि जहां पर किसी भी हालत में पानी नहीं जाता, इसकी उनको जानकारी है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---किसी एक गांव के बारे में जानकारी नहीं है । सूचना मिलने पर जानकारी हासिल की जा सकती है ।

मैनपुरी जिले में रजबहा भिठावली का बरसात में कट जाना

*८१---श्री भलिखान सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नहरशाख बेवर के रजबहा भिठावली को बसुरा सुल्तानपुर पर कक नदी वर्षा के समय प्रतिवर्ष काट देती है जिससे हजारों बीघा फसल नष्ट होती है ? सरकार उस कटान को रोकने के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, उस कटाव को रोकने के संबंध में कक नदी का सर्वेक्षण किया जाने वाला है ।

श्री भलिखान सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कटान ३, ४ साल पहले से बराबर कटता था और अब तक इस को रोकने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह स्वाभाविक रूप से नहीं होता था । एक गांव कंचनपुर है उस गांव के लोग उसको काटते थे और दूसरे गांव के लोग रोकते थे । जब यह देखा गया कि वैमनस्य बढ़ रहा है इसलिये विचार किया गया कि चूंकि नदी वहां गोल है, इसलिये उसको ठीक करा दिया जाय ।

श्री भलिखान सिंह---जहां पर यह कटान होता है और नया बम्बा निकला है, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां कोई एक पुराना बांध था ?

श्री रामस्वरूप यादव---पुराना बांध तो रजबहे के साथ-साथ है ।

श्री भलिखान सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह बांध जो था वह बम्बा निकलने के पहले से था और उसके पहले कटान की कोई सूचना नहीं आती थी और फसल नष्ट होती थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---पुरानी बात का ज्ञान इस वक्त नहीं है, लेकिन गांव वाले काट लेते हैं यह मैं बता सकता हूं ।

श्री भलिखान सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये नोटिस दूंगा और आध घंटे की डिबेट का समय लूंगा ।

झांसी जिले के माताटीला बांध में ली गयी जमीन की मालगुजारी तथा मुआवजा

*८२---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी के माताटीला बांध में जो भूमि पानी में डूब गई है और जो भूमि बांध से संबंधित अन्य कामों के लिये ले ली गई है तथा सरकार के कब्जे में है, उस भूमि की मालगुजारी किसानों से वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, जिस भूमि का मुआवजा वितरण हो चुका है और अमल दरामद तहसील के कागजों में हो गया है उसका लगान किसानों से नहीं लिया जाता । बाकी भूमि जिसका अमलदरामद नहीं हुआ उसका लगान अभी तक किसानों से लिया गया है, परन्तु अब भविष्य के लिये आदेश दे दिये गये हैं कि कृषकों से ऐसी भूमि के प्रति कोई लगान न लिया जावे ।

*८३---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध के लिये जिस भूमि पर सरकार ने सन् १९५२-५३ से कब्जा कर लिया है और वह भूमि जो सन् १९५५ से पानी के भराव में आ गई है, जिसका मुआवजा किसानों को आज तक नहीं मिला है परन्तु जिसकी मालगुजारी वे दे रहे हैं, क्या सरकार उक्त किसानों को मुआवजा के अतिरिक्त हरजाना भी देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं। जब किसानों को इस भूमि का मुआवजा वितरण किया जावेगा तो उसके साथ ही उनको वह रकम भी वापस कर दी जावेगी जो उन्होंने लगान के रूप में सिंचाई विभाग द्वारा भूमि लिये जाने के बाद दी है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन किसानों से जमीन का लगान लिया जा रहा है और जमीन सरकार ने कब्जे में ले ली, तो मुआवजा देते वक्त उनको बीच का हर्जाना क्यों नहीं दिया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---जब कि जमीन सरकार ने ले ली है तो मुआवजा किस लिये दिया जायगा। जो लगान ले लिया गया है वह लौटाया जा सकता है।

श्री गेंदासिंह---किसानों के ऊपर मालगुजारी वसूल करते समय जो थर्ड डिग्री मेजर अख्तियार किया गया वह किस से वापस कराया जायगा ?

(प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा---कृषि मंत्री जी ने जो आदेश भेजे हैं कि उनसे मालगुजारी न ली जाय, वे कब भेजे हैं और उनकी जमीन कब ली गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---जमीन सन् १९५५ में ली गई है और आदेश अभी कुछ दिन पहले ही दिये गये हैं। मालगुजारी मुआवजे के साथ वापस कर दी जायगी, इसका जिक्र कई बार सदन में भी कर दिया गया है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---माताटीला बांध में ली गयी जमीन का मुआवजा कब तक दिया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---निश्चित समय बताना सम्भव नहीं, लेकिन जल्दी प्रयत्न किया जायगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा---जिन किसानों से मालगुजारी ले ली गई है एक्वायर करने के बाद भी, उनकी मालगुजारी वापस करने के साथ उसका सूद भी सरकार देगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूद नहीं देगी।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---क्या मंत्री जी को पता है कि माताटीला बांध में लगभग १०,००० एकड़ भूमि का मुआवजा बनना है और जो कर्मचारी वहां लगे हैं वे ३ वर्ष तक भी मुआवजा नहीं बना सकेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, भूमि तो काफी है जिसका मुआवजा देना है, लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि वे ३ वर्ष तक नहीं बना पावेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव---उस भूमि का मुआवजा किस हिसाब से दिया जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---नियम बने हैं जिनके हिसाब से दिया जायगा।

श्री भीखालाल---क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि जिस तारीख से जमीन एक्वायर की जाय उस तारीख से मालगुजारी लेना बन्द हो ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दे दिया गया है ।

श्री सुभद्रा प्रसाद गोस्वामी---क्या कुछ ऐसे गांव भी हैं जिनकी जमीन ले ली गई है और उनका गजट नहीं हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव---नोटिस की आवश्यकता है ।

*८४-८५---श्री श्रीकृष्ण गोयल---[स्थगित किये गये ।]

इटावा जिले की विद्युत योजना

*८६---श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)---क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्तर्गत बड़े-बड़े व्यापारिक कस्बों को कब तक बिजली पंहुचाई जा सकेगी ?

श्री धर्मसिंह---इसका समय निश्चित किया जाना अभी संभव नहीं है ।

श्री मिहरबान सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके पास कोई ऐसी योजना है कि जहां से इटावा को बिजली दी जा सकेगी ?

श्री धर्मसिंह---इस समय जहां पर बिजली दी जा रही है वही योजना है, बाकी और कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---पंचवर्षीय योजना में सरकार का इटावा के कितने कस्बों को बिजली देने का विचार है ?

श्री धर्मसिंह---एक स्कीम है इलैक्ट्रिफिकेशन आफ टाउन्स ऐंड विलेजेज जिसमें २६ में से २२ टाउन्स के करीब इलैक्ट्रिफाइड हो चुके हैं और दूसरी स्कीम है रूरल ऐंड अरबन इलैक्ट्रिफिकेशन की ।

टेहरी-गढ़वाल जिले के लिए उद्योग-धंधे

*८७---श्री सूरत चन्द्र रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला टेहरी-गढ़वाल में सरकार के द्वारा कौन से उद्योग धन्धे शुरू किये जावेंगे और अब तक कौन-कौन से शुरू किये गये हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---(क) चर्म तथा ऊन उद्योग,
(ख) ऊन योजना ।

श्री सूरत चन्द्र रमोला---क्या मंत्रीजी बताने का कष्ट करेंगे कि यह ऊन उद्योग कब शुरू किया गया था और उसमें अब तक कितने स्थानीय आदमियों को एम्प्लायमेंट दिया गया ?

श्री रऊफ जाफरी---एक ट्रेनिंग प्रोडक्शन सेन्टर सन् १९५६-५७ से काम कर रहा है, जिसमें ५ कताई के सेंटर हैं और उनमें करीब १,००० आदमी लगे हुये हैं । ५ कताई सेंटर और खुलने जा रहे हैं जिसमें भी १,००० के करीब आदमी लग जावेंगे । इसके अलावा ५ सेंटर और भी खोलने का विचार किया जा रहा है । इसके अलावा प्रयागगढ़ व नवगांव में बुनाई व सिलाई के सेंटर हैं ।

सहारनपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली

*८८---श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह जिला सहारनपुर के उन गांवों में जो सड़क के बिजली के खम्भों के समीप पड़ते हैं बिजली वितरित करने का प्रबन्ध कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध है और जो लोग मांगते हैं उनको दी भी जाती है ।

श्रीमती शकुन्तला देवी---क्या माननीय वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से गांवों में बिजली के खम्भे लगवाये जा रहे हैं और जिला सहारनपुर में वह किन स्थानों पर उद्योग चलाने के लिये बिजली का प्रबंध कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---जो प्रार्थनापत्र देते हैं उन्हें बिजली दी जाती है और इस क्षेत्र में १० हार्स पावर तक और कुछ केसेज में १५ हार्स पावर तक डिकंट्रोल भी है ।

सहारनपुर जिले की नलकूप योजना

*८९---श्रीमती शकुन्तला देवी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहारनपुर के देहातों में प्रथम पंचवर्षीय योजना में और उसके बाद से अब तक कितने ट्यूबवेल लग चुके हैं तथा सरकार कितने और लगवाने की आयोजना कर रही है ?

श्री राजस्वरूप यादव---सहारनपुर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना में १०५ नलकूप और उसके बाद अब तक १४ नलकूप लग चुके हैं । तथा ४२ और नलकूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगवाने का आयोजन है ।

श्रीमती शकुन्तला देवी---क्या सरकार बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ट्यूबवेल कब तक लग जावेंगे, क्योंकि लोग पानी के लिये बहुत परेशान हैं ?

श्री राजस्वरूप यादव---१५ बनने को थे, १४ बन गये हैं और जल्दी ही पर्याप्त पानी देना शुरू हो जायगा । १९५७-५८ में १० नलकूप हैं जिन पर जल्दी काम शुरू होने वाला है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---सन् १९५६-५७ में बने जिन नलकूपों ने अभी तक पानी देना आरम्भ नहीं किया है, तो क्या यह सही है कि उनको अभी तक पर्याप्त बिजली नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजस्वरूप यादव---खुद कर तैयार हो गये हैं, लेकिन अभी उसमें कुछ समय लगेगा, जल्दी ही शुरू हो जायगा ।

सहारनपुर जिले में हरिजनों के लिए पृथक उद्योग-धंधे न होना

*९०---श्रीमती शकुन्तला देवी---क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहारनपुर में हरिजन मजदूरों के लिये सरकार उद्योग-धन्धे खोल रही है जिससे वह अपनी जीविका प्राप्त कर सकें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रऊफ जाफरी---कोई उद्योग, विशेषकर हरिजनों और मजदूरों के लिये, तो नहीं खोला जा रहा है । सहारनपुर में कितने ही उद्योग हैं उनमें वह भी भाग ले सकते हैं ।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर की सीमेंट का सिधौली भेजा जाना

*९१---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---क्या यह सत्य है कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर से ४६० (चार सौ साठ) बोरी सीमेंट १४-५-५७ को रेलवे रसीद नं० १५०९२ के द्वारा सिधौली (जिला सीतापुर) एन० ई० रेलवे के स्टेशन पर एक्जीक्यूटीव इंजीनियर, प्राविन्शियल डिवीजन को भेजी गई थी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---जी हां, परन्तु १५०९२ रसीद नं० नहीं है वरन् वैगन नम्बर है ।

*९२---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उक्त चार सौ साठ बोरा सीमेंट सिधौली स्टेशन पर २३-५-५७ से आज तक पड़ी हुई है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---जी नहीं ।

नोट---प्रश्न ९० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

हरदोई जिले की नलकूप योजना

*९३--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में सन् १९५३ से अब तक कितने ट्यूबवेल बने हैं तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने और बनेंगे?

श्री रामभर्ति (अनुपस्थित)--हरदोई जिले में अब तक कुल ३१ नलकूप बन चुके हैं और ५ नलकूप इस वर्ष में बनाये जा रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ९ नलकूप और बनाये जाने का प्रस्ताव है।

*९४--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि--क्या सरकार तहसीलवार उक्त ट्यूववेलों की सूची सदन में रखने की कृपा करेगी?

श्री रामभर्ति (अनुपस्थित)--नत्थी संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८४ पर)

टोंस नदी की कथित सिंचाई योजना

*९५--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या टोंस नदी से देहरादून के पास चौहड़पुर स्थान पर सिंचाई तथा विद्युत संबंधी कोई योजना बनाई जा रही है? यदि हां, तो उसकी बिजली तथा पानी से किस-किस जिले को लाभ पहुंचेगा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं।

*९६-९७--श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--[स्थगित किये गये।]

*९८-१००--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--[१० मार्च, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

सिंचाई विभाग का निरीक्षण भवन, गोरखपुर

*१०१--श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग निरीक्षण भवन, गोरखपुर की चहार दीवारी के मुख्य द्वार की दीवाल पर तथा प्रकाश ग्लोब पर एक व्यक्ति का नाम लिखा है? यदि हां, तो क्यों और किसका?

श्री रामभर्ति (अनुपस्थित)--जिस अहाते में अधीक्षक अभियंता का निवास-स्थान है उसी में स्पेशल क्लास निरीक्षण भवन भी स्थित है। इस अहाते के दो मुख्य फाटक हैं। एक फाटक से निरीक्षण भवन की ओर जाने का मार्ग है तथा दूसरे फाटक से अधीक्षक अभियंता के निवास स्थान की ओर का मार्ग है। निरीक्षण भवन की ओर वाले फाटक पर "निरीक्षण भवन" लिखा हुआ है तथा दूसरे फाटक पर अधीक्षक अभियंता से भेंट करने वालों की सुविधा के लिये उनका नाम लिखा हुआ है। प्रकाश ग्लोब पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है।

फैजाबाद जिले के छोटे कस्बों के लिए बिजली की मांग

*१०२--श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)--क्या विद्युत मंत्री कृपा कर यह बतलावेंगे कि फैजाबाद जिले के जलालपुर, टांडा, भदरसा कस्बों को तथा छोटे कस्बों में बिजली देने की सरकारी योजना के अनुसार कब तक बिजली दी जावेगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*१०३—श्री देवीप्रसाद मिश्र—क्या सरकार फैजाबाद जिले के उन गांवों को जिनके पास से सोहवल पावर हाउस से विभिन्न दिशाओं मे जाने वाली बिजली की लाइनें गुजरती हैं, बिजली देने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

वाराणसी जिले में सारनाथ के राजकीय मार्ग पर पुनः बिजली देने की मांग

*१०४—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)—क्या विद्युत मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वाराणसी जिले में सारनाथ के राजकीय मार्ग के किनारे लगाये गये विद्युत प्रकाश को समाप्त करने के संबंध में कोई राजकीय आज्ञा प्रसारित की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सारनाथ को बुद्ध जयन्ती समारोह के अवसर पर अस्थायी रूप से बिजली दी गई थी जो कि समारोह के बाद बन्द कर दी गई।

*१०५—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—क्या विद्युत् मंत्री उसे पुनः चालू करने के निमित्त कोई आदेश प्रसारित करने की कृपा करेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—चूंकि ये लाइसेंसदार के क्षेत्र में हैं, अतः सरकार द्वारा बिजली देने का प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन तथा डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के कार्यालयों में हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के कर्मचारी

*१०६—श्री मुरलीधर कुरील (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४७ से १९५७ तक कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन ने कितने अपर ग्रेड और लोअर ग्रेड के क्लर्क और अफसरों की अलग-अलग नियुक्तियां की हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन में १९४७ से १९५७ तक कुल १११ क्लर्कों तथा १५ अफसरों की नियुक्तियां हुईं।

*१०७—श्री मुरलीधर कुरील—इन प्रत्येक ग्रेड की भरती में कुल अलग-अलग कितने हरिजन और कितने बैकवर्ड क्लास के लोग हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—१११ क्लर्कों में १ हरिजन तथा ६ बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। अफसरों में हरिजन तथा बैकवर्ड क्लास के कोई नहीं हैं।

*१०८—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के कार्यालय में अपर और लोअर ग्रेड क्लर्क और चपरासियों की अलग-अलग कितनी संख्या है और इसमें प्रत्येक श्रेणी में कितने परिगणित व कितने पिछड़ी जाति के लोग हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वांछित सूचना निम्नलिखित है:—

पद	कुल कर्मचारी	परिगणित जाति की संख्या	पिछड़ी जाति की संख्या
अपर ग्रेड क्लर्क ..	२७७	२	३
लोअर ग्रेड क्लर्क	२०४	१	४
चपरासी ..	२५८	०	३१

बाढ़ विभाग, गाजीपुर द्वारा गांवों को ऊंचा करने का काम

*१०९—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४ से १९५७ तक बाढ़ विभाग, गाजीपुर द्वारा कितने ग्रामों का स्तर ऊंचा कर दिया गया है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—१११ ग्रामों को ऊंचा करने का काम पूरा हो चुका है, ७९१ में चल रहा है।

विधायक निवास में बंगले का गिराया जाना

*११०—श्री गनेश चन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास, दारुलशफा ए० व बी० ब्लाक के बीच में जो बंगला गिराया जा रहा है, उसके क्या कारण हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस भवन का कुछ भाग विधायक निवास ब्लाक ए० व बी० के बनाने के संबंध में गिराया गया था। शेष भाग ठीक स्थान पर न होने के कारण तथा इन दोनों निवासों के बीच, दारुलशफ़ा डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़क बनाने के लिये, जिसके बीच में यह शेष भाग पड़ता था, गिराया गया।

जहांगीराबाद, जिला बाराबंकी में कोआपरेटिव आडीटरों की ट्रेनिंग

*१११—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जहांगीराबाद, जिला बाराबंकी में कितने कोआपरेटिव के आडीटरों के लिये ट्रेनिंग सरकार की तरफ से दी जा रही है तथा उनको सरकारी मासिक सहायता कितनी दी जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस समय जहांगीराबाद (जिला बाराबंकी) में स्थित ट्रेनिंग स्कूल में ९५ उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें ४० रु० प्रतिमास प्रति उम्मीदवार छात्रवृत्ति (Stipend) के रूप में सरकारी सहायता दी जाती है। इसके अलावा उन्हें छात्रावास में (मुफ्त) रहने की सुविधा तथा पूर्ण शिक्षण काल में ६० रु० प्रति उम्मीदवार एकमुश्त मार्ग व्यय (Fixed travelling allowance) की सहायता भी उपलब्ध है।

*११२—श्री ऊदल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जहांगीराबाद में जिस मकान में ट्रेनिंग दी जा रही है वह किसका है और उसका मासिक किराया सरकार को कितना देना पड़ता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जहांगीराबाद (जिला बाराबंकी) में स्थित ट्रेनिंग स्कूल और छात्रावास की मालिक स्टेट जहांगीराबाद है, जिसका मासिक किराया सरकार द्वारा १००० रु० दिया जा रहा है।

उन्नाव जिले की सफीपुर तहसील में कथित नलकूप

*११३—श्री भगवतीसिंह विशारद तथा श्री शिवगोपाल तिवारी (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले की सफीपुर तहसील में गत पंचवर्षीय योजना में कितने नलकूप बनवाये गये ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—उन्नाव जिले की सफीपुर तहसील में गत पंचवर्षीय योजना में कोई राजकीय नलकूप नहीं बनवाया गया।

*११४--श्री भगवतीसिंह विशारद तथा श्री शिवगोपाल तिवारी--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन समस्त नलकूपों में कुल कितना रुपया व्यय किया गया और उनसे कुल कितने एकड़ कृषि की सिंचाई प्रति वर्ष होती है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--प्रश्न ही नहीं उठता।

आजमगढ़ जिले में कुछ गांवों के सुधार के लिए श्री रामसुन्दर पाण्डेय का प्रार्थना-पत्र

*११५--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३० अप्रैल, सन् १९५७ का प्रश्नकर्त्ता का भेजा हुआ कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें माउर-बोझ, धवरियासाथ, परदहा, तराई व जीरपुर, दढ़वलपटराव, सिसवा, खैरा मुहम्मदपुर, फतेहपुर तालरतोय तथा वरुहा गांव सभाओं के अधिकारियों एवं ग्रामीणों द्वारा पानी की निकासी, गांवों को ऊंचा करने एवं नहर में पुल बनाने की मांग की गई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)--जी हां, एक पत्र दिनांक ३०-४-५७ को माननीय सदस्य श्री राम सुन्दर पांडेय से प्राप्त हुआ था जिसके साथ निम्नलिखित ९ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे।

१--श्री देवकी तिवारी
२--श्री मुहम्मद दाऊद
३--श्री फाग यादव
४--श्री बांके सिंह
५--श्री बसन्त यादव
६--श्री चन्द्रवली राय
७--श्री राम बजन
८--श्री दासी
९--श्री रघुनन्दन चौहान

इनमें से क्रम संख्या १,७,८ के विषय में अभी जांच पड़ताल हो रही है।

क्रम संख्या २ व ३--

इन प्रार्थना-पत्रों की संबंधित अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल कराई गई है परन्तु अभी तक पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी ;

क्रम संख्या ४--

यह प्रार्थना-पत्र ग्राम धवरियासाथ घाट के स्तर को ऊंचा कराने के बारे में है, धनाभाव के कारण यह ग्राम इस समय आजमगढ़ जिले के ग्रामों के स्तर को ऊंचा करने की योजना के अन्तर्गत नहीं रखा गया।

क्रम संख्या ७--

इस प्रार्थना-पत्र में फरई ताल से एक नाला बनाने की प्रार्थना की गई है। एक नाला जिसका नाम चंवर ताल है की अनुमानित लागत लगभग २२,१५१ रु० होगी, इसके बन जाने पर फरई ताल का पानी बह कर निकल जावेगा।

क्रम संख्या ५--

पाराथीतरेदीह जुरेदीहताल तहसील घोसी में एक नाला बनवाना चाहते हैं। इस नाले का सर्वेक्षण हो गया है, जिला नियोजन समिति द्वारा स्वीकृत नालों के निर्माण के उपरान्त इस नाले के निर्माण को प्रवरता दी जावेगी। जिला नियोजन समिति ने इस नाले के निर्माण को महत्व नहीं दिया।

क्रम संख्या ९---

यह प्रार्थना-पत्र घोरी घाट नहर पर २१ मील पर एक पुल बनाने के संबंध में था । वहां पर पहले ही से २ पुल एक २०:६:० और २१:२ मील पर बने हुये हैं और तीसरा उन पुलों के निकट बनाना उचित नहीं समझा जाता ।

*११६---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उक्त गांवों की आबादी एवं खेती में वर्षा का पानी गत वर्ष एकत्र हुआ था तथा उससे अधिक हानि हुई थी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---हां, गत वर्ष अति वृष्टि के फलस्वरूप इस जिले में घोसी तहसील के निम्नांकित गांवों में फसलों को जो क्षति पहुंची तथा छट बी गयी उसका विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८५ पर)

कानपुर जिले में सिचाई सम्बन्धी काम

*११७---श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में गत पांच वर्षों में सिंचाई के संबंध में कौन-कौन नये कार्य हुये---(अ) कितनी नई माइनरें निकलीं, (ब) माइनरें कितनी बढ़ाई गईं, (स) उपर्युक्त निर्माण में कितना व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---कानपुर जिले में निम्नलिखित नये कार्य हुये:---

(१) घाटमपुर राजवहे के ६१ पुलों का पुनर्निर्माण हुआ ।

(२) बिभाना नाला drain का निर्माण हुआ ।

(३) फतेहपुर ब्रांच के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ ।

(४) प्रतापपुर माइनर, नरिहा माइनर तथा बिधाई माइनर का निर्माण हुआ । इनकी सम्मिलित लम्बाई ७ मील ४ फर्लांग है ।

(५) गुच्चूपुर माइनर २ मील बढ़ाई गई व गुजेला माइनर १ मील २ फर्लांग बढ़ाई जा रही है ।

उपर्युक्त सारे कार्य पर कुल ५,२६,४०० रुपया व्यय हुआ ।

*११८---श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत---(अ) नई सिंचाई योजना, (ब) नई निकाली जाने वाली अथवा बढ़ाई जाने वाली माइनरें तथा (स) उन पर होने वाला व्यय क्या होगा ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)---कानपुर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सिंचाई योजना पर काम हुआ अथवा भविष्य में स्वीकृति होने पर होगा ।

<u>योजनायें जिन पर काम हो चुका या हो रहा है :</u>

नाम	लम्बाई	अधिकृत क्षेत्र एकड़
१---प्रतापपुर माइनर	३ मील २ फर्लांग	१,५५२
२---नरिहा माइनर	१ मील २ फर्लांग	८६५
३---बिधाइ माइनर	३ मील	१,२४६

४—गुच्चूपुर माइनर २ मील ४ फर्लांग बढ़ाई जा चुकी है।
५—गुजेला माइनर १ मील २ फर्लांग बढ़ाई जा रही है।
६—कुडंवा नाला बनाया जा रहा है।
७—तिलसहरी नाला बनाया जा रहा है।

प्रस्तावित योजनायें जो अभी विचाराधीन हैं:

८—१४० मील लम्बी चैनल्स (इटावा डिवीजन के अन्तर्गत)।
९—कत गांव माइनर।
१०—केलई माइनर।
११—अनवा माइनर।
१२—सिकन्दरा राजवहे को बढ़ाया जाना।
१३—पंका माइनर।
१४—अंत माइनर।
१५—काशीपुर माइनर।
१६—सोभान माइनर।
१७—तिलकपुर माइनर।
१८—गंगा पुर माइनर।
१९—जगराज पुर माइनर।
२०—धरमंगत पुर माइनर।
२१—गौरी माइनर।
२२—मवाई माधो राजवहा।
२३—किशोरा राजवहा।
२४—शिओली राजवहा का बढ़ाया जाना।
२५—अकबरपुर राजवहा का बढ़ाया जाना।
२६—जौहर राजवहा।
२७—रसूलाबाद राजवहा।
२८—रेओना पलेवा चैनल का बढ़ाया जाना।
२९—विभाना नाला।
३०—कुर्मी खेरा नाला।
३१—पुरानी नहरों को चौड़ा करना।
३२—मंसुरा माइनर का बढ़ाया जाना।
३३—केसर वाल माइनर का बढ़ाया जाना।
३४—रायपुर माइनर का बढ़ाया जाना।
३५—हरवसपुर नाला।
३६—करसुई नाला।
३७—इनके अतिरिक्त १३ माइनरें बनाने का और प्रस्ताव है।
३८—अनेकों कुलाबों का बढ़ाया जाना।
३९—इटावा ब्रांच का पुनर्निर्माण।

(ब) उपरोक्त कथन से ज्ञात होगा कि:

(१) ३ नई माइनरें बनाई जा चुकी हैं।
(२) २५ नई माइनरें, तथा
(३) ४ राजवहों को बनाये जाने का प्रस्ताव है।
(४) १ माइनर बढ़ाई जा चुकी है।
(५) १ माइनर बढ़ाई जा रही है।
(६) ३ माइनरें बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।

(७) ३ पुराने राजवहे बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।
(८) इटावा ब्रांच के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव है।
(९) इटावा डिवीजन में १४० मील लम्बी चैनल्स बनाने, और
(१०) कानपुर डिवीजन में एक पलेवा चैनल के बढ़ाये जाने के भी प्रस्ताव हैं।

(स) उपर्युक्त सारे कार्यों पर लगभग ७० लाख रुपये व्यय होगा यदि यह सब काम जो प्रस्तावित हैं स्वीकृत हो जावें।

गोरखपुर जिले में नारायणी व रोहिण नदियों में बाढ़ का धोबा नाले से सम्बन्ध

*११९—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को पता है कि अगस्त, १९५७ के प्रथम पखवारे में गोरखपुर जिले में नारायणी रोहिण और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ का कारण धोवहा नाले का बन्ध है जो धोबहा नाले की विशाल जलराशि को अवरुद्ध करता है?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—रोहणी और नारायणी नदियों में अधिक बाढ़ आने का कारण धोबा नाला पर १९५७ की वर्षा के पूर्व बनाये गये बांध पर लेशमात्र भी उत्तरदायित्व नहीं है। गत वर्षा में रोहणी और नारायणी नदियों में अधिक बाढ़ इन नदियों के क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण आई तथा धोबा बांध के निर्माण का नारायणी तथा रोहणी नदियों में बांध से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है।

*१२०—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार को पता है कि धोबहा बन्ध से अवरुद्ध २०० फीट से अधिक चौड़ाई में जाने वाली विशाल जलराशि को नारायणी नदी में गिराने के लिये केवल ४० फीट चौड़ी नहर बनी है जिसमें फाटक न लगा होने के कारण पानी बाढ़ के समय नदी में जाने के बजाय नदी का ही पानी नाले में आता है और इसी कारण गत वर्षा में भयंकर बाढ़ आई थी और भविष्य में फिर आ सकती है?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—धोबा नाला के पानी को नारायणी नदी में गिराने के लिये ४० फुट चौडा कटाव बनाया गया था जिसने बिना किसी विशेष क्षति के गत वर्ष अधिकतम बाढ़ में भी सफलता पूर्वक कार्य किया। यह सत्य है कि मानसून के आरम्भ में जब कि नारायणी नदी बाढ़ पर नहीं होती है उस समय नारायणी नदी का पानी धोबा कट में उल्टा बहता है चुंकि यह पानी धोबा नाला के पेट में ही रहता है इस पानी से स्वयं धोबानाला में खड़ी हुई, फसल की कोई विशेष हानि नहीं होती है। दुर्भाग्यवश गत वर्ष जब कि धोबा नाला में अधिकतम बाढ़ आई हुई थी कुछ किसानों ने नवनिर्मित बांध को काट दिया इसके फलस्वरूप धोबा बांध के तलहटी में लगी हुई फसल को अवश्य हानि हुई तथा मुख्य नारायणी नहर के किनारों एवं उस पर बने पक्के कार्यों पर अधिक क्षति पहुंची थी।

**१२१—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार उपर्युक्त आवश्यकता महसूस करते हुये तथा बाढ़ के कारण और प्रभाव दोनों का ही प्रत्यक्ष निरीक्षण करने तथा तत्काल भविष्य की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कोई उपाय सजेस्ट करने के लिये विशेषज्ञ मण्डल मौके पर भेजने के प्रश्न पर विचार करेगी और यदि भेजा हो, तो उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेगी?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—अब चूंकि धोबा बांध के निर्माण कार्य को मुख्य अभियन्ता (प) सिंचाई विभाग एवं सिंचाई कार्य मंडल गोरखपुर के अधिकारियों ने भली-भांति जांच कर लिया है, इस कार्य के लिये कोई विशेष कमीशन भेजने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, न ही किसी कमीशन को भेजने का विचार है। इस सम्बन्ध में यह बता देना उचित

होगा कि चूंकि गत वर्षा ऋतु में नारायणी नदी के पानी के धोबा में पहुंचने के मार्ग में कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं तथा इससे भविष्य में धोबा में जो पानी जायेगा उसका अनुमान सम्भव नहीं हो रहा है, इस कारण नारायणी नहर के १ मील ३ फर्लांग पर धोबा नाला के पानी को निकालने के लिये एक साइफन बनाने का निश्चय किया गया है ।

गांव पंचायतों द्वारा गांवों को ऊंचा करने का कार्य

*१२२—श्रीमती गैंदा देवी (जिला बस्ती)—क्या यह सही है कि गत वर्ष सरकार ने गांव ऊंचा करने, कुओं की मरम्मत, पुल तथा बांध आदि बनाने का ठेका गांव पंचायतों को देने का आदेश बाढ़ विभाग के जिला अधिकारी को दिया था ? यदि हां, तो इसके अनुसार किस-किस जिले में कितने गांव पंचायतों को कितने रुपये का काम दिया गया और व्यक्तिगत ठेकेदारों को कितना-कितना ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—जी हां, गत वर्ष सरकार ने विशेषकर ग्रामों को ऊंचा करने का ठेका जहां संभव हो सका गांव पंचायतों को देने का आदेश बाढ़ विभाग के कुछ अधिकारियों को दिया था।

निम्नलिखित जिलों में गांव पंचायतों द्वारा गांवों को ऊंचा करने का कार्य दिया गया था। इसकी सूची अगले पृष्ठ पर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८६ पर)

आगरा जिले की किरावली तहसील के कुछ गांवों से पानी के निकास की योजना

*१२३—स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले की तहसील किरावली के कितने और कौन से गांव अतिवृष्टि से पीड़ित हैं? इस अवस्था में इन गांवों को कितने वर्ष हो चुके ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—तहसील किरावली, जिला आगरा में २३ गांवों में अति वर्षा के कारण बाढ़ का पानी राजस्थान से आता है जिनकी सूची निम्नलिखित है :

अतिवृष्टि गांव

१—पाली कराही
२—नगला कराही
३—कराही
४—मोमापुर
५—नगला दले
६—नगला सराही
७—नगला मानसिंह
८—नगला लोधा
९—नगला बनारा
१०—नगला देवकर
११—बसुरी काजी
१२—मई बुजुर्ग
१३—नगला मई बुजुर्ग
१४—नगला बजारा नं० २
१५—नगला जारूआ
१६—सुमेरा
१७—महमदपुर
१८—सुपेरा
१९—पहुंची
२०—थिरावली
२१—नगला जग्गू
२२—नगला चमार
२३—नगला देव

यह गांव जब भी कभी अधिक वर्षा होती है पीड़ित होते हैं।

*१२४—स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या सरकार ने इन गांवों के वर्षा के पानी के भराव को निकालने के लिये कोई व्यवस्था कर दी है ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांव ऐसे हैं जहां ऐसी व्यवस्था हो चुकी है और कौन-कौन से गांव शेष हैं जहां व्यवस्था की जाने वाली है और कब तक ?

श्री राममूर्ति—तहसील किरावली के गांव जो बाढ़ से पीड़ित है और जिनकी पानी के निकास की योजनायें उपस्थित है उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८७ पर)

पांच वर्ष से अधिक पुराने औद्योगिक ऋण

*१२५—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या उद्योग मन्त्री कृपया ऐसे दिये गय औद्योगिक ऋणों की सूची सदन की मेज पर रक्खेंगे जो पांच वर्ष से अधिक पुराने हैं और जिनकी वसूलयाबी नहीं हो रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील में सिंचाई योजनायें

*१२६—श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला गोंडा, तहसील बलरामपुर, के अन्तर्गत जहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है, वहां पर सिंचाई की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर और कब तक ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—तहसील बलरामपुर जिला गोंडा में निम्नलिखित सिंचाई योजनाएं निर्माणाधीन एवं खोजबीन के अन्तर्गत हैं:—

निर्माणाधीन:—

१—गिरगिटही बांध और ३२ मील लम्बी नहरें।

२—खैरमन बांध और २५ मील लम्बी नहरें।

खोजबीन के अन्तर्गत:—

बांधों के नाम	लम्बी नहरें
	मील
१—नवानगर	२५
२—भगवानपुर	२२
३—नेवलगढ़	६
४—जलजलवा	७
५—चित्तौरगढ़	४०
६—पकरी	१०

७—जलकुन्डी नहरें जो कि नेपाल स्थित जलकुन्डी बांध से ली जावेंगी ।

बदायूं जिले के सिंचाई विभाग में पिछड़े व परिगणित जातियों के कर्मचारी

*१२७—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् १९५६ में और ३० जून, १९५७ तक बदायूं जिले में कितने ट्यूबवेल आपरेटर, अमीन तथा हलकारे भरती किये गये ? उनमें क्रमशः पिछड़े व परिगणित जातियों के लोगों की संख्या क्या है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—इस अवधि में ४ अमीन, ३० नलकूप चालक, तथा ५ हलकारे भर्ती किये गये। इनमें परिगणित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या इस प्रकार है :—

	परिगणित	पिछड़े वर्ग
अमीन	..	..
नलकूप चालक	५	२
हलकार	१	२

रायबरेली जिले के देउराहार भू-भाग के लिए सिंचाई के साधन न होना

*१२८—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार को ज्ञात है कि रायबरेली जिले में थाना सरेनी के अन्तर्गत ग्राम दुधवन में एक छः सौ बीघा के ऊपर का उपजाऊ चक जिसका नाम देउराहार है, असिंचित पड़ा रहता है अर्थात् सिंचाई का कोई साधन नहीं है ? क्या सरकार उपरोक्त भूमि की सिंचाई हेतु नहर या ट्यूबवेल का प्रबन्ध करने का विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—इस क्षेत्र में नहर या ट्यूबवेल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में नहर विभाग द्वारा ली गयी भूमि का मुआवजा

*१२९—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील फरेन्दा, जिला गोरखपुर, में नहरों तथा नहर क्वार्टरों के लिये ली गई जमीनों का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा कब तक यह चुकता किया जायगा ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—तहसील फरेन्दा, जिला गोरखपुर, में नहरों के निर्माण के लिये १३,०२९ एकड़ भूमि ली गई थी। इस भूमि के मुआवजे के कागजात तैयार किये जा चुके हैं और चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक मुआवजे की अदायगी हो जाने की आशा है। नहर के क्वार्टरों के लिये ली गई भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है।

हाथरस तथा सिकन्दराराऊ तहसीलों में नालों की खुदाई रुकना

*१३०—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि तहसील हाथरस तथा सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) के नालों की खुदाई क्यों रोक दी गयी है ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—नालों की खुदाई का काम भूमि प्राप्त न होने के कारण रोक दिया गया है। भूमि प्राप्त होने पर कार्य आरम्भ किया जावेगा। भूमि प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

हाथरस में नवीन उद्योगों की योजना

*१३१—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हाथरस में नवीन उद्योगों में कितने व्यक्तियों को काम देने की योजना है और वह किन-किन छोटे तथा किन-किन बड़े उद्योगों के द्वारा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सूचना एकत्र की जा रही है।

*१३२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस-सिकन्दराराऊ के बीच जो ईख गन्ने का क्षेत्र है वहां एक चीनी मिल खोलने पर वे विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से यह कार्य आरम्भ हो सकेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री टीकाराम पुजारी—[मुख्य मन्त्री से सम्बन्धित छठवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १ क अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

खीरी जिले में गन्ना उत्पादकों का चीनी मिलों पर बकाया

२—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि किसानों का कितना रुपया खीरी जिले में ऐसा है जोकि गन्ना मिल या सोसाइटियों पर अब तक बाक़ी है और दिया नहीं गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—विभिन्न चीनी मिलों द्वारा खीरी जिले के किसानों के गन्ने की कीमत की अदायगी जो बाकी है वह इस प्रकार है :

सीजन	रुपया
१—१९५६–५७	७८,७४९
२—१९५७–५८	७,६५,९१६
(३१ जनवरी तक)	

सोसाइटियों द्वारा गन्ने के मूल्य का कोई रुपया दिया जाना शेष नहीं है ।

३—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसानों के जमा रुपये पर उतना सूद किसानों को दिया जाता है जितना किसानों से लिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सोसाइटियों द्वारा किसानों से पेशगी नकद रुपया जमा नहीं कराया जाता है अतएव सूद दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य में नलकूप

४—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१ दिसम्बर, १९४५ को उत्तर प्रदेश में कुल कितने नलकूप थे और ३१ दिसम्बर, १९५७ ई० को कितने नलकूप हो गये हैं ?

श्री राममूर्ति (अनुपस्थित)—३१ दिसम्बर, १९४५ को उत्तर प्रदेश में कुल १,६८७ नलकूप थे और ३१ दिसम्बर, १९५७ को ५,८४३ नलकूप हो गये थे ।

साप्ताहिक कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब माननीय मुख्य मंत्री इस सप्ताह में क्या क्या कार्य होगा, इसकी सूचना सदन को देंगे ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, अभी आज और कल बजट पर सामान्य विवाद चलेगा । उसके बाद २६ और २७ से जब वोटिंग आन डिमान्ड्स चलेगा तो पहला ग्रुप माननीय वित्त मंत्री जी का है जो दो दिन रहेगा ।

श्री अध्यक्ष—यानी तारीख २५–२६ को होने वाले आइटम्स २६–२७ को होंगे । आप माननीय सदस्यों को ब्योरा बता दें ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२६–२७ को माननीय वित्त मंत्री जी के विभाग रहेंगे जिनका ब्योरा इस प्रकार है :

Group 1—(२६ तथा २७ फरवरी)

Charges on account or other taxes and duties.
Superannuation Allowances and Pensions.
Commuted Value of Pensions.
Loans and Advances bearing interest

Swayyatta Shasan Mantri (स्वायत्त शासन मन्त्री)

Gaon Sabhas and Panchayats.
Grant-in-aid of Civil Works.
Miscellaneous Charges.

Group II—(२८ फरवरी, १ तथा ३ मार्च)

Nyaya Mantri (न्याय मन्त्री)

Forest.
Administration of Justice.
Extraordinary Charges.
Schemes of State Trading.

Krishi Mantri(कृषि मन्त्री)

Medical.
Public Health.
Agricultural Development, Engineering and Research.
Veterinary.
Capital outlay on Agricultural Schemes.

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, ग्राम तौर से मालगुजारी विभाग पहले लिया जाता था, इस वर्ष वह क्यों नहीं लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—नियमों के हिसाब से यह नेता विरोधीदल से बातचीत करके तय होता है। पहले आप अपने नेता से पूछ लीजिये।

राजावीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—श्रीमन्, होली की छुट्टियां ५ तारीख से होंगी। ३–४ तारीख खाली है। इस तरह से दो दिन के लिये यहां आयेंगे। अगर सरकार उचित समझे तो ३–४ की भी छुट्टी कर दी जाय तो जो दो दिन के लिये आना पड़ेगा और उसके जरिये जो असुविधा होगी, वह बच जायगी।

श्री अध्यक्ष—आप इस तरह से सदन में सरकार से बातचीत न करें। इसके लिये मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। इसके लिय आप सदन के बाहर बातचीत कर सकते हैं।

१९५८–५९ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

***श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)**—श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि प्रस्तुत बजट के प्रस्तुत करने की जो प्रणाली है, वह प्रणाली दोषपूर्ण है तथा संविधान के कायदे के भी खिलाफ है, इसके अतिरिक्त समाजवादी समाज को बनाने का जो हमारा ध्येय है उसको भी वह पूरा नहीं करती।

श्रीमन्, जो बजट मैन्युअल है, जिसके अनुसार हमारा कैपिटल एक्सपेंडीचर होता है, वह मेरे पास मौजूद है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कांस्टीट्यूशन के अनुसार अभी तक उसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है। वह जून, ४८ तक करेक्ट किया हुआ है। इसी बजट मैनुअल के अनुसार यह बजट बना हुआ है। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि अभी तक कन्सालीडेटेड फंड ऐक्ट और रूल्स भी नहीं बने हैं। संविधान की धारा २८३ के अनुसार यह आवश्यक है कि यह रूल्स और ऐक्ट बनाये जायें जिनके अनुसार यह तय हो कि कंसालिडेटेड फंड का पेमेंट आफ मनी किस प्रकार से होगा, विड्रावल किस प्रकार से होगा। साथ ही साथ नियमानुसार पब्लिक एकाउन्ट फंड की कोई परिभाषा नहीं की गयी है। श्रीमन्, आश्चर्य की बात तो यह है कि सन् १९५० में कांस्टीट्यूशन लागू हुआ, लेकिन सन् १९५८ तक कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक एकाउन्ट फंड का कोई नियम उसके अनुसार नहीं बनाया गया है। आज भी हमारा बजट मैनुअल जो चल रहा है, वह कांस्टीट्यूशन के अनुसार नहीं है। इसलिए जब हमारा बजट मैनुअल पुराना ही है जिसके अनुसार यह बजट बनाया गया है तो संविधान के अनुसार यह बजट भी नहीं बनाया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
†२१ फरवरी, १९५८ की कार्यवाही से।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दूसरी बात यह है, श्रीमन्, कि हमारा बजट जो है वह इंगलैंड के बजट की नकल है, लेकिन इंगलैंड में प्लानिंग के तरीके की कोई चीज नहीं है। जैसे हमारे यहां प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात थी और आज सेकेंड पंचवर्षीय योजना की बात है, इस तरह की कोई चीज वहां नहीं है। हमारे यहां तो पहले से यह मालूम रहता है कि अगले साल यह योजना लागू होने वाली है और प्लान के रिसोर्सेज भी मालूम होते हैं। इसलिए एक ऐसे मुल्क की बजट प्रणाली की नकल करना जहां प्लानिंग नाम की कोई चीज न हो, हमारे लिए उचित नहीं है और हमारा जो प्लान ह उसकी मर्यादा के भी विरुद्ध है।

तीसरी बात यह है कि इस बजट प्रणाली को चलाने से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि उसकी एस्टिमटिंग ठीक नहीं हो पाती है। श्रीमन्, आप देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में बजट एस्टिमेट था कि २७ करोड़ ६१ लाख रुपये का घाटा होगा, लेकिन सरप्लस हुआ ४ करोड़ ७४ लाख रुपये का। इसका अर्थ यह है कि ३२ करोड़ रुपये की बजटिंग गलत रही। तो यह क्यों रहा? इसका कारण यह है कि हमारे बजट बनाने का तरीका गलत है। एक दूसरी मिसाल भी मैं देता हूं कि सन् १९५५-५६ और १९५६-५७ में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की ओर से १ करोड़ ७३ लाख रुपया रखा गया था। दूसरी ओर एस्टिमेट लगाया गया था कि ९८ लाख रुपये की आमदनी होगी, और इधर २९२ लाख रुपये का घाटा हो गया। यानी ३९० लाख रुपये की गलत एस्टिमेटिंग हुई और यह सब गलत बजट प्रणाली के कारण ही हुआ। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि आप ब्रिटेन की बजट प्रणाली को चालू रखने के बदले स्वीडेन की बजट प्रणाली को लागू करें जहां प्लानिंग चल रही है। श्रीमन्, वहां पर यह होता है कि सब राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि लिये जाते हैं और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी लिये जाते हैं और उन लोगों की एक बजट कमेटी बनायी जाती है। तो मेरा सुझाव है कि यहां भी बजट कमेटी बनायी जाय और हमारे प्रदेश में यह नयी प्रणाली चालू की जाय। अगर स्वीडेन वाली यह प्रणाली लागू हो तो यह ज्यादा प्रजातांत्रिक प्रणाली होगी और इस तरह से हम अधिक जनमत की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ मेरी यह भी मांग है कि हमारे राज्य में आडिटिंग और एकाउंटिंग का काम भी अलग-अलग होना चाहिये। श्रीमन्, यहां होता यह है कि ए० जी० के आफिस में ही एकाउंटिंग का काम होता है और उन्हीं के यहां आडिटिंग का काम भी होता है। अगर आज हम पी० डब्ल्यू० डी० इंजीनियर से पूछें कि एक पुलिया के बनाने में कितना खर्च हुआ है तो वह नहीं बतला सकेगा। वह यही कहेगा कि ए० जी० जानें। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि एकाउंटिंग और आडिटिंग विभाग को अलग अलग होना चाहिये।

साथ ही साथ फाइनेन्शियल ईयर को भी बदला जाय। १ अप्रैल से जो हमारे यहां बजट ईयर शुरू होता है, वह हिन्दुस्तान के हालात के बिलकुल खिलाफ है। इसलिये हमारे यहां बजट ईयर नवम्बर या अक्तूबर से यानी रेनी सीजन के बाद शुरू होना चाहिये।

इसके साथ ही साथ जो राज्य का वर्तमान बजट है वह यह साबित करता है कि हमारा राज्य कितना अधिक कर्जदार हो गया है। कर्ज बढ़ता ही जाता है। आप देखें कि हमारे प्रदेश में कुल कर्ज कितना बढ़ गया है। यह कर्ज सन् १९४७ में कुल मिलाकर ४० करोड़ का था, जो अब बढ़कर वर्तमान बजट में २८ करोड़ होने जा रहा है। इसके माने यह हुये कि यह कर्ज १२ साल के भीतर ८ गुना हो गया और इस साल हम कर्ज का ब्याज और रिपेमेंट आफ लोन्स की मद में साढ़े २७ करोड़ रुपया दे रहे हैं। ८ करोड़ रिपेमेंट आफ सेन्ट्रल लोन्स में जायगा, ४ करोड़ ३१ लाख रुपया सेन्ट्रल लोन का ब्याज जायगा, ६ करोड़ १४ लाख सिन्किंग फंड में, १ करोड़ १२ लाख अपने राज्य का जो कर्ज हैं उस में जायगा। इस तरह से जिस राज्य में बजट का एक चौथाई रुपया ब्याज में देना पड़े उसकी आर्थिक दशा का आप अन्दाजा लगा सकते हैं। कुल रेवेन्यू रिसीट है १०८ करोड़ की और उसमें से साढ़े २७ करोड़ रुपया

चला जायगा रिपेमेंट आफ लोन्स में और उसके ब्याज में, जबकि प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि राज्यों को अपना कर्ज नहीं बढ़ाना चाहिये। आप देखेंगे कि कुल ६५ लाख का सिन्किन्ग फंड है, जबकि इसके लिये हमें केपिटल एक्सपेंडीचर से रकम मिलनी चाहिये, उसकी हमें इजाजत नहीं दी गई। तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का लोन जो ५-६ करोड़ की रकम है लम्प-सम में अदा करना पड़ता है, वह हम कैसे अदा कर पायेंगे? सिन्किन्ग फंड नहीं है तो कहां से अदा कर पायेंगे? साढ़े ८ करोड़ में से कुल ६७ लाख रुपया कैपिटल से दिया जा रहा है और इसके ऊपर भी हमें ब्याज देना होगा, यानी कर्ज लेकर कर्ज की अदायगी होगी। यह किसी तरह भी उचित नहीं है। २ बार ब्याज इस तरह से हम देंगे। उस कर्ज की अदायगी के लिए केन्द्र से हम और कर्ज ले रहे हैं, इसलिए यह कर्ज एक डेंजर सिगनल है, एक चेतावनी है, इसको हमें रोकना चाहिए।

इसके अलावा हमारे राज्य की जो कार्मशियल अन्डरटेकिंग्स हैं वह सब नुकसान में चल रही हैं। टयूबवेल्स का सवाल है, मैं समझता हूं उनकी फौरन जांच होनी चाहिए, क्योंकि सन् १९५१–५२ में उनमें १२ लाख रुपये से अधिक का घाटा हुआ, जो अब बढ़कर १ करोड़ ६८ लाख का नेट लास हो गया है।

दूसरी तरफ हमारी स्टेट ट्रेडिंग स्कीम्स हैं। अकेले गेहूं में सन् १९५४–५५ में १ करोड़ ४१ लाख रुपये का घाटा हुआ।

राज्य की नहरों को आप देखें, उनमें भी ५१–५२ में १ करोड़ ५८ लाख की आय थी, लेकिन इस बजट साल में उनमें भी १७ लाख ३१ हजार का घाटा है।

इसी तरह से हाइडेल स्कीम्स की आय भी १२ करोड़ से घट कर ४ लाख रह गयी। इस तरह से कार्मशियल अन्डरटेकिंग्स में बराबर घाटा बढ़ रहा है। इसके अलावा बजट में कोई प्रोफारमा अकाउन्ट्स नहीं दिये हुए हैं। चुर्क सीमेंट फैक्टरी के कोई प्रोफारमा अकाउन्ट्स नहीं दिखाये गये। गवर्नमेंट प्रिसीजन इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी भले ही मुनाफे में चल रही हो, लेकिन उसके भी कोई प्रोफारमा अकाउन्ट्स हमारे सामने नहीं रखे गये। क्यों यह चीजें हमारे सामने नहीं लायी जातीं? मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म्स का हिसाब अप्रोप्रियेशन में तो दिखाया जाता है, लेकिन राज्य की विधान सभा के सामने वहां के प्रोफारमा अकाउन्ट्स नहीं रखे जाते। शारदा हाइडेल स्कीम के और तराई स्टेट फार्म आदि के भी कोई अकाउन्ट्स नहीं दिये गये हैं। जब तक हमारे सामने सारी स्टेट की कार्मशियल अन्डरटेकिंग्स की तस्वीर नहीं आती, बजट इन्कम्पलीट है।

साथ ही साथ एक बजट डेफीशिएंसी यह है कि हमें यह नहीं पता चलता कि सिंकिंग फन्ड अकाउन्ट कितना है। अगर मैं पूछूं कि हमें १९६० में एक लोन का रिपेमेंट करना है तो इस बजट में कहां लिखा है कि सिंकिंग फन्ड में इतना रुपया दिया गया है? इसका कहीं पता नहीं चलता है। सिंकिंग फन्ड दो तरह का होता है—डेप्रिसिएशन सिंकिंग फन्ड और लिक्वीडेशन सिंकिंग फन्ड। दोनों का बैलेंस कितना है और कितना रुपया दिया गया है, यह हमारे बजट में नहीं है। साथ ही साथ राज्य सरकार की इनवेस्टमेंट पालिसी भी खतरे से खाली नहीं है। यहां पर मैं मूंधड़ा कांड जिसका बहुत जिक्र किया गया नहीं शामिल करना चाहता, लकिन हमारी राज्य सरकार का जो इनवेस्टमेंट कारखानों में रहा है वह भी गलत रहा है।

इन्डियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली, में राज्य सरकार ने ३० हजार, ३५ शेयर खरीदे हुए हैं और यह कम्पनी बन्द है। क्यों नहीं चलती है? कोई जांच हुई? सरकार ने अपना इनवेस्टमेंट वापस लेने के लिए क्या कोशिश की? रामपुर इन्जीनियरिंग लिमिटेड में ६९ हजार शेयर हैं। यह भी बन्द है। रामपुर मेज प्राडक्ट्स लिमिटेड में १२ हजार शेयर खरीदे हुए हैं। बन्द पड़ी है। माडर्न मेटल इन्डस्ट्रीज, रामपुर, में २ हजार शेयर्स राज्य सरकार के हैं। यह बन्द पड़ी है। डान मैच कम्पनी, रामपुर में २ हजार ५ सौ शेयर्स खरीदे

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हुए हैं। यह बन्द पड़ी हुई है। इसी तरह सादूल टेक्सटाइल्स, बीकानेर, इन्डियन एयरक्रैफ्ट कारपोरेशन, दिल्ली, आदि २७ फैक्टरियां हैं जिनमें ६२ लाख रुपया इन्वेस्टेड है। केवल रेजिन ऐन्ड टरपेन्टाइन फैक्टरी, बरेली और कोआपरेटिव बैंक को छोड़ कर कहीं भी राज्य सरकार को आमदनी नहीं हो रही है और ६१ लाख से ज्यादा रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने कब यह रुपया इन्वेस्ट किया? अगर पहले की सरकारों ने किया तो जिन कारखानों में इन्वेस्टमेंट हैं उनकी हालत सुधारने के लिए, इस कैपिटल का ब्याज भी प्राप्त करने की क्या कोशिश की गयी? जहां पर एप्रोप्रिएशन एकाउन्ट रिपोर्ट में मार्केट वैल्यू शेयर्स हैं वहां पर लिखा हुआ है—नाट नोन, नाट नोन। आज की मार्केट वैल्यू क्या है, पता नहीं है।

मैं पूछना चाहता हूं कि रामपुर के नवाब साहब से क्यों इन्वेस्टमेंट को प्राप्त किया गया, क्यों शेयर्स ट्रांस्फर करवाये गये जब कि हम चला नहीं सकते। कोई कारण नहीं था कि राज्य सरकार इतना बोझा अपने ऊपर लेती।

इसी प्रकार, श्रीमन्, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारे बजट में काटी जा रही है, इसका भी प्रमाण है। श्रीमन्, आप को याद होगा जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना बन रही थी उस समय कहा गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग-प्रधान होगी। कहां प्रायरिटी है उद्योग को? इसमें इन्डस्ट्री पर पिछले सालों के मुकाबिले में और सालों के मुकाबले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रायरिटी दी जानी चाहिए, लकिन इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट को प्रायरिटी नहीं दी गयी है। यह बजट सेकेंड फाइव इयर प्लान की प्रायरिटीज को रिफलेक्ट नहीं करता है। मैं नहीं जानता कि इसके लिए कौन, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। मैं दोनों को जिम्मेदार मानता हूं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के आंकड़े देना चाहता हूं जिससे स्पष्ट होगा कि कितना रुपया यू० पी० को उद्योग के लिए मिला है फारेन एक्सचेंज के सम्बन्ध में।

	करोड़ रुपया
मदरास	३४.६
बम्बई	२८.३
बंगाल	२०.६
पंजाब	१०.४१
मध्य प्रदेश	१०.२३
आंध्र	५.२३

उत्तर प्रदेश को कुल १२ लाख रुपया मिला और वह भी प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में कुछ भी नहीं। ये माननीय मुख्य मन्त्री जी के आंकड़े हैं फारेन् एक्सचेंज के बारे में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिये गये हैं। अगर इसके लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है तो क्यों उत्तर प्रदेश के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? यह राज्य सरकार क्यों अपने कर्त्तव्य में असफल है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना को प्लानिंग कमीशन से स्वीकार करवाया तो या तो प्लानिंग कमीशन ने हमारे राज्य को अन्धकार में रखा या प्लानिंग कमीशन ने जो वायदा किया उसे पूरा नहीं किया, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इन्डस्ट्रीज जो कि सेकेंड फाइव इयर प्लैन की प्रायरिटी बतायी गयी थी उसको हमारे राज्य का बजट रेफ्लेक्ट नहीं करता। इसके साथ ही साथ, श्रीमन्, आप यह देखें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहा जाता था कि हमारी नेशनल इन्कम बढ़ेगी। माननीय विरोधी दल के नेता ने कुछ पर कैपिटा इन्कम के आंकड़े दिये। राज्य सरकार ने जो फिगर्स दी हैं वह कांस्टेंट प्राइसेज के आधार पर दी हैं। पिछले दो सालों से राज्य सरकार ने अपनी स्टेटिस्टिक्स सम्बन्धी नीति को बदल दिया है। पहले करेंट प्राइसेज के आधार पर फिगर्स दी जाती थीं जो कि सेन्ट्रल

गवर्नमेंट भी करती थी और प्रत्येक सरकार करती है। लेकिन हमारे राज्य की सरकार कांस्टेंट प्राइसेज के आधार पर नेशनल इन्कम को असेस करती है। यह एक नई बात है। करेंट प्राइसेज के आधार पर हमारी परकैपिटा इन्कम रूरल एरियाज में कुल १५० रुपये है जब कि पिछले वर्ष माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि पर कैपिटा एक्सपेंडीचर हमारे राज्य में बढ़ गया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने मेरे एक सवाल के जवाब में बताया था कि सन् १९५४-५५ में राज्य में पर कैपिटा एक्सपेंडीचर एक साल में १४८.९० और १९५७ में वह बढ़ करके जुलाई में १८४ रुपया हो गया यानी पर कैपिटा एक्सपेंडीचर में ३५ रुपये की वृद्धि दो ढाई साल के अन्दर हुई। पर कैपिटा इन्कम घटी हो और पर कैपिटा एक्सपेंडीचर बढ़ गया हो तो इस से हम अन्दाज लगा सकते हैं कि इस बजट में नेशनल इन्कम की बात स्पष्ट नहीं है।

इसके साथ ही साथ, श्रीमन्, अरबन एरियाज में कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स बनता है—कानपुर में—और वह सारे राज्य की अरबन एरियाज का प्रमाण माना जाता है। तो सन् १९४६ में यह इन्डेक्स ३२९ प्वाइन्ट था। सन् १९५५ में यह ३७१ हो गया, यानी ४२ प्वाइन्ट का इन्क्रीज हुआ। सन् १९५६ के जो आंकड़े मौजूद हैं उनमें यह प्राइस इन्डेक्स बढ़कर के ४२४ हो गया। यानी एक साल के अन्दर ५३ प्वाइन्ट का इन्क्रीज हो गया और माननीय विरोधी दल के नेता बता रहे हैं कि दिसम्बर में वह ५०० हो गया। तो सन् १९४६ में ३२९ प्वाइन्ट और सन् १९५६ के दिसम्बर में वह ५०० हो गया। इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स की क्या हालत है। इससे भी हमारे राज्य की स्थिति स्पष्ट होती है।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में फाइनेंस कमीशन ने जो रिमार्क्स किये हैं, जो सबसे ताजा आंकड़े दिये हैं वह मैं रखना चाहता हूं। सोशल सर्विसेज के सम्बन्ध में हमारा यू० पी० पिछले वर्ष सबसे कम खर्च कर रहा था। माननीय राजनारायण जी ने जो आंकड़े दिये उसके बाद के जो आंकड़े फाइनेंस कमीशन ने दिए हैं उनके अनुसर ३.२ हमारा राज्य खर्च कर रहा है जबकि दूसरे राज्य उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं। आन्ध्र ४.२ रुपया, आसाम ८.१ रुपया, बिहार ४.७ रुपया, बाम्बे ७.१, हैदराबाद ४.५, मध्य-भारत ९.१, मध्य प्रदेश ४.१—यह १९५५-५६ के आंकड़े मैं दे रहा हूं—मद्रास ५.२, मैसूर ६.८, उड़ीसा ३.४, पेप्सू ७.५, पंजाब ४.८, राजस्थान ४.६, सौराष्ट्र ९.९, ट्रावनकोर कोचीन ८.०, वेस्ट बंगाल ७.३ और उत्तर प्रदेश ३.२। तो इस फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार भी जो उसके अपेंडिक्स में रिपोर्ट लिखी है उसके अनुसार भी सोशल सर्विसेज पर सब से कम यू० पी० का खर्चा है और ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर एक्सपेंडीचर फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में बढ़ा है। २.३ था सन् १९५२ में और वह २.७ हो गया सन् १९५६ में। ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर खर्च बढ़ा और सोशल सर्विसेज पर १९५२ के मुकाबिले में नाममात्र को बढ़ा, लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले में सबसे कम हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की हमारी इच्छाओं को इस बजट द्वारा पूर्ण न कर सकने का यह सबसे बड़ा प्रमाण है।

इसके साथ-साथ, श्रीमन्, मुझे यह भी शिकायत है कि फाइनेंस कमीशन ने कुछ सिफारिशें की थीं, अन्य राज्यों के लिये भी की थीं, साथ ही, यहां के लिये भी की थीं। उन सिफारिशों में से एक यह थी कि राज्यों में एक नैचुरल कैलेमिटीज फंड बनाया जाय जिसमें ५० लाख रुपया प्रतिवर्ष क्रेडिट किया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि इस बजट में उसके लिये क्यों नहीं कोई प्राविधान किया गया जबकि स्वयं वित्तमंत्री जी पूर्वी जिलों के बुखदर्द की इतनी कथा सुनाते हैं।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—५५ लाख रुपये फेमिन रिलीफ फंड में मौजूद हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---फेमिन रिलीफ फंड है, लेकिन उसमें कोई रुपया इस वर्ष क्रेडिट नहीं हुआ। इसका आपको पता नहीं है। अगर हो तो दिखाइये। किसी भी प्रकार के क्रेडिट का कोई प्राविधान इस वर्ष के फेमिन रिलीफ फंड में नहीं हैं। साथ ही, अगर फेमिन रिलीफ फंड है तो आप स्वयं मानते हैं कि इस सूबे में फेमिन है। अगर इस सूबे में फेमिन न होता तो रुपया क्यों मौजूद रहता ?

श्री चरणसिंह---जी हां, २५ साल से फेमिन ही होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अब इसमें एक और इमीडियेट रिलीफ की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही है। चार सौ रुपये तक तनख्वाह पाने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका आधा महंगाई भत्ता उनकी तनख्वाह में मिला दिया जायगा। इसको इमीडियेट रिलीफ कहा गया। यह इमीडियेट रिलीफ है या इमीडियेट रिलीफ को रोकने वाला है ? इससे जो १ पैसा या २ पैसा रुपया उनका जमा होता था वह भी नहीं हो पावेगा। हां, जब वे रिटायर हो जावेंगे तब शायद इससे कुछ रिलीफ हो, लेकिन यह मिनिस्टीरियल स्टाफ के लिये इमीडियेट रिलीफ नहीं है और वह बात बिल्कुल सही नहीं है।

इस प्रकार जो तरीका इंगलैण्ड में कंजरवेटिव प्रकार के बजट बनाने का है उसको यहां लागू किया गया है और उसी के सारे दोष इस वर्तमान बजट में विद्यमान हैं। वह प्रणाली एक सोशलिस्ट प्रकार के बजट बनाने के लिये समुचित प्रणाली नहीं है। इस प्रणाली से सोशलिस्ट बजट बनाने की बात उसी प्रकार है जैसे कि राइफल से राकेट छोड़ने की कल्पना। अभी जैसे कैनिवाल में राकेट छोड़ने का प्रयत्न किया गया। तीन बार राकेट्स छोड़े जा चुके हैं किन्तु क्या हुआ है ? उसी प्रकार इस प्रणाली से सोशलिस्ट बजट बनाने की परिकल्पना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बजट की परिकल्पना मृगमरीचिका ही रहेगी।

इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी से और उनकी सरकार से अपील करूंगा कि राज्य के बढ़ते हुये खर्च को रोकने की कोशिश करें, राज्य के कैपिटल एक्सपेन्डीचर और रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर को और जो ब्याज देने की बात है उसको रोकें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुरूप अगर इस बजट को बनाना है तो उसी के अनुकूल इस बजट को संशोधित करने का कष्ट करें।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, जिस समय विरोधी दल के नेता, माननीय त्रिलोकी सिंह जी, बोल रहे थे मैं उनके भाषण को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। विरोधी दल सरकार बनाने की क्षमता रखता है, किन्तु उनके भाषण से मुझे बड़ी निराशा हुई। हम समझते थे कि वे सरकार की कुछ नीतियों और कुछ योजनाओं के ऊपर प्रकाश डालेंगे। उनके सारे भाषण का सार था कि सरकार की ओर से जो आंकड़े प्रसारित किये गये हैं वे गलत हैं। इसके सिवाय, और कोई बात मेरी समझ में नहीं आयी।

श्रीमन्, विरोधी दल की तरफ से अक्सर सरकार के ऊपर इस बात का दोषारोपण होता है कि यह सरकार प्रान्त में समाजवादी सरकार कायम नहीं कर रही है। हमारे आदरणीय मित्र राजनारायण सिंह जी बहुधा इस समाजवादी व्यवस्था की इस सदन में चर्चा किया करते हैं। अभी हमारे मित्र नारायणदत्त जी ने भी यह कहा कि यह बजट समाजवादी प्लानिंग का बजट नहीं हो सकता। हमारे मित्र राजनारायण सिंह जी की समाजवादी व्यवस्था की जो परिभाषा है वह यह है कि प्रान्त की जितनी जमीन है उसका बटवारा हो जाय। बावजूद इसके कि वह इस बात को जानते हैं कि प्रान्त की कितनी आबादी है और कितनी जमीन है और बटवारे से कितना जमीन का हिस्सा एक काश्तकार के पास जायगा, मगर फिर भी वह इस बात पर समय समय पर जोर दिया करते हैं कि जमीन का बटवारा कर दिया जाय, इससे समाजवादी व्यवस्था यहां कायम हो जायगी। मुझे एक बात याद आती है कि एक समाजवादी राकफ़ेलर के यहां, जो दुनिया का बहुत बड़ा धनी था, जा पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम्हारे पास इतना रुपया हो, इसलिए तुम इसको बांट दो। राकफ़ेलर ने कहा,

अच्छी बात है, आप बैठ जाइये, हिसाब कर लीजिये। हिसाब करने से जो उसके पास धन था उसमें से एक आदमी के हिस्से में २ फ़ार्दिंग या २ पैसे आये। राकफ़ेलर ने कहा कि ये २ पैसे आप ले जाइये, इसके बाद जो दूसरे आवेंगे उनसे हम निपट लेंगे। तो यह व्यवस्था जो हमारे राजनारायण जी चाहते हैं, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि इससे समाजवादी व्यवस्था इस प्रान्त में कायम नहीं हो सकती। समाजवादी व्यवस्था तभी कायम होगी जब उसमें जनता का सहयोग होगा परन्तु इसमें समय लगेगा।

अभी हम सरकार की तरफ से पार्लियामेंटरी डेलीगेशन में गये हुए थे। दिल्ली में सोशल सर्विसेज इन कामनवेल्थ पर भाषण हो रहा था और वहां पर १२–१५ प्रकार की पेंशनों का जिक्र आया, मिसाल के लिए ओल्ड एज पेंशन, ब्लाइंड पेंशन, विडो पेंशन, अनएम्प्लायमेंट इन्श्योरेंस, डाइवोर्स पेंशन, चिल्ड्रेन्स एजूकेशन सप्लीमेंटरी पेंशन, सिकनेस इंश्योरेंस, इसी तरह की बहुत-सी पेंशनों का जिक्र आया। मैंने समझा कि बड़ा अच्छा देश है। बाद को जब उनसे पूंछा कि आप इतनी पेंशन कैसे दे पाते हैं तो उन्होंने कहा—वे न्यूजीलैण्ड के सदस्य थे—कि हमारे देश में आमदनी का साढ़े सात परसेंट प्रत्येक व्यक्ति को सरकार को देना पड़ता है टैक्सेज को छोड़ करके। इस वास्ते हम इतनी पेंशनें दे पाते हैं। मैं माननीय राजनारायण जी से यह पूंछना चाहता हूं कि क्या इस प्रान्त की जनता अपनी आमदनी का साढ़े सात परसेंट देने के लिए तैयार होगी। जिस समय सरकार इस चीज को इन्फोर्स करने के लिए चलेगी तो माननीय राजनारायण जी पहले व्यक्ति होंगे जो जनता को भड़कावेंगे कि सरकार तुम्हारे खून को चूसती है। तो कैसे समाजवादी व्यवस्था आ सकती है, यह मैं उनसे पूछना चाहता हूं।

जो सरकार की नीति इधर रही है उससे स्पष्ट है कि सरकार समाजवादी व्यवस्था लाना चाहती है और उस ओर जा रही है। आपने देखा कि देशी रियासतें खत्म हुईं, जमींदार इस प्रदेश में खत्म हुए, एक्सपेंडीचर टैक्स लगाया गया है, मृत्यु कर लगाया गया है, वैल्थ टैक्स लग गया है। सारे टैक्स इस बात के द्योतक हैं कि सरकार समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहती है और उस ओर जा रही है।

मैं एक बात और माननीय मित्र को बता देना चाहता हूं कि समाजवादी व्यवस्था को अगर सरकार चाहे भी तो रोक नहीं सकती है। हवा पश्चिम से बही हुई है और उसका असर एशिया के सारे देशों में हो रहा है, किसी के रोकने से रुक नहीं सकता। परन्तु हमारा यह एक छोटा-सा प्रान्त है, अगर इसमें समाजवादी व्यवस्था कायम भी हो जाय और दूसरे प्रदेशों में समाजवादी व्यवस्था न कायम हो तो यह समाजवादी व्यवस्था कै बरस तक चलेगी ?

आप देखते हैं कि आज रूस चाहता है कि सारी दुनिया में कम्युनिज्म की नीति फैल जाय, अमेरिका चाहता है कि सारी दुनिया में कैपीटलिज्म की प्रवृत्ति हो जाय। आज संसार में दो विचारधाराओं का द्वन्द चल रहा है। इसलिये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब सारे देश में कोई व्यवस्था कायम होगी तो यह प्रान्त उससे अलग नहीं रह सकता है। यह भी उसमें शामिल होगा और यह भी उसी तरफ धीरे-धीरे जा रहा है।

मुझे एक बात से बड़ी निराशा हुई। मैंने बजट का भी अध्ययन बड़े गौर से किया है और माननीय नेता विरोधी दल की बात को भी बड़े ध्यान से सुना है। हमारी सरकार की शिक्षा की नीति क्या है? आंकड़ों के देखने से मालूम होता है कि लिटरेसी सारे भारतवर्ष में हमारे प्रदेश में सब से कम है। हमने देखा है कि सीलोन में यूनिवर्सिटी एजूकेशन फ्री है। एक छोटा सा देश है जिसकी ८० लाख की आबादी है और १० हजार विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं। वहां सारा एजूकेशन निःशुल्क है। हमारी सरकार ने जो इस तरफ कदम उठाया है कि सातवीं क्लास तक शिक्षा निःशुल्क की है। यदि इस रफ्तार से हम चलेंगे तो १९६० तक हमारे यहां फ्री ऐन्ड कम्पलसरी एजूकेशन १४ साल तक के बच्चों के लिये नहीं होगी, [illegible] आशा दिखाई नहीं पड़ती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि

[श्री बेचनराम गुप्त]

कुछ वर्षों के लिये यूनिवर्सिटी एजूकेशन बिल्कुल बन्द कर दी जाय और बेसिक एजूकेशन और प्राइमरी एजूकेशन पर ज्यादा जोर दिया जाय।

जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी शिक्षा मंत्री थे उस समय प्राइमरी एजूकेशन पर बहुत जोर दिया गया था, गांव-गांव में एक आन्दोलन था और ऐसा मालूम होता था कि कोई व्यक्ति निरक्षर नहीं रह जायगा और इसका बड़ा भारी असर पड़ता था। लेकिन हमें दुख है कि शायद वह ड्राइव अब बन्द हो गया है और अब उसमें शक्ति नहीं रही है। सरकार की यह नीति समझ में नहीं आती है। सरकार क्वालिटी चाहती है या क्वांटिटी चाहती है? सरकार की यह हौच पौच नीति चल रही है।

हमारे विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि हमारे यहां इंडस्ट्रीज कम हुई हैं। उनके कहने का मतलब यह है और उन्होंने उदाहरण भी दिये हैं कि हमारे सूबे में चीनी की कुछ मिलें बन्द हो गई हैं और कुछ कपड़े की मिलें बन्द हो गई हैं। मैं यह निवेदन करूं कि सारे भारतवर्ष में शुगर की इंडस्ट्री सब से ज्यादा हमारे प्रदेश में है तो किसी प्रकार से कोई मिल बन्द हो जाय या कपड़े की मिल बन्द हो जाय तो यह नहीं कहा जा सकता है कि हमारे प्रान्त की इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ रही है। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश में इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं, घटी नहीं हैं। अगर वह यह बात कहते कि अहमदाबाद, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास आदि स्थानों से हमारा प्रदेश पीछे है तब तो उनकी बात सही थी, उनके पीछे हमारा प्रदेश जरूर है। सरकार की ऐसी नीति रही है जिससे हमारे यहां की इंडस्ट्रीज को बहुत धक्का पहुंचा है। पहली तो यह है कि हमारे यहां के इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बहुत ज्यादा हैं और इंडस्ट्रीज के लिये सस्ते दामों पर बिजली मिलना बहुत जरूरी है और बगैर उसके इंडस्ट्रीज चल नहीं सकती हैं। सब से पहली बात यह है कि हमारे यहां बिजली बहुत कम है। रिहन्द डैम बन रहा है, उसके बाद शायद अधिक प्रगति होगी। मगर मौजूदा हालत में कुछ आशा नहीं की जा सकती है।

दूसरी चीज है सेल्स टैक्स। मैं देखता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी हर साल सेल्स टैक्स में कोई न कोई अमेंडमेंट लाते हैं बिला इसके सोचे हुये कि उसका इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा। इस प्रान्त में होजरी की इंडस्ट्री करीब-करीब खत्म हो गयी है। बंगाल के मुकाबले में यहां का माल महंगा पड़ने लगा है। इस वास्ते वह इंडस्ट्री लगभग समाप्त हो चुकी है। आयल इंडस्ट्री का भी यही हाल है। आयल सीड्स इस प्रान्त में बहुत अधिक पैदा होते हैं मगर बहुतेरी तेल की मिलें बन्द हो गयी हैं। उसका भी यही कारण है कि हमारी सरकार की इलेक्ट्रिसिटी और सेल्स टैक्स के बारे में जो नीति है उससे इन दो इंडस्ट्रीज को धक्का पहुंचा है।

हमारे मित्र त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि अपराधों की संख्या बढ़ गयी है और इतनी बढ़ गयी है कि जेल में नये-नये बैरक बनवाने की जरूरत पड़ गयी। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य जरा यू० एन० ओ० की अपराधों के बारे में रिपोर्ट को देखने का थोड़ा कष्ट करें। आज दुनिया में सब जगह अपराधों की संख्या बढ़ी हुई है और इस प्रान्त का मुकाबला अगर बिहार और मध्य प्रदेश से करें तो आप देखेंगे कि हमारे यहां अपराधों की संख्या कम ही है। जो जेल में बैरकें बनवाने की बात है यह तो केवल इसलिये है कि कुछ कच्ची बैरकें गिर गयीं, खपरा उन पर रहा नहीं, तो उनको पक्का करने की जरूरत पड़ गयी।

श्रीमन्, मैं ५ मिनट और चाहता था।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। मैं समझता हूं, अधिक समय सब को नहीं दिया जा सकता। मैं २ मिनट से अधिक नहीं दूंगा।

श्री बेचनराम गुप्त—बहुत अच्छा।

माननीय राजनारायण जी ने अपने भाषण में कहा कि इस प्रान्त में ४० करोड़ रुपये का गबन है। वे सन् ५५–५६ की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से ये फीगर्स ले आये। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये आंकड़े ऐसे हैं कि जिनमें कभी रसीद देर में आती है, कभी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देर में आता है, कभी तखमीने में वृद्धि हो जाती है। ये उसी प्रकार के आंकड़े हैं जिनकी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में बैठ करके हम लोग जांच करते हैं। उसमें लिखा है—

"इन अत्यधिक आपत्तियों को, जिनका निराकरण नहीं हुआ है प्रभावपूर्ण रूप से जल्दी निबटाने के लिये राज्य सरकार के साथ-साथ जुलाई, १९५७ में एक विशेष आन्दोलन जारी किया गया।"

श्री राजनारायण—४६ करोड़ तक का है।

श्री बेचनराम गुप्त—वे आकड़े, श्रीमन् इस प्रकार हैं—

सिंचाई में	..	..	..	१९,४९,१०,०७९
विद्युत्	..	..	..	१३,८६,९०,८३९
सार्वजनिक निर्माण कार्य	..	..	..	५,५९,४५,९५३
पूंजी की लागत	..	..	..	८१,७६,८९३
कृषि ..	..	..	..	५६,४०,२९६
उद्योग ..	..	..	..	७८,४०,९१०

इन सब को जोड़ कर माननीय मित्र कहते हैं कि ४५,४६ करोड़ रुपये का गबन इस प्रान्त में हो गया। उनका यह कहना बिल्कुल निराधार है। ये सारी चीजें पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में आती हैं, उन पर जांच होती है।

श्रीमन्, एक मिनट और।

श्री अध्यक्ष—हां, हां, कहिये।

श्री बेचनराम गुप्त—दूसरी बात यह है कि एक माननीय मित्र जो नये आये हैं कोलअसला से, उन्होंने कहा कि भदोही विद्युत्-गृह में गबन हुआ। मैं वहीं का रहने वाला हूं, मुझे तो नहीं मालूम। मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि वहां गबन हुआ। तो उन्होंने कहा कि समाचार-पत्र में पढ़ा था कि मेजरमेंट बुक गायब हो गयी है। तो ऐसे समाचार के आधार पर इतनी बड़ी बात कह देना जो बिल्कुल निराधार हो मैं समझता हूं कि उपयुक्त नहीं है। वहां कोई गबन नहीं हुआ है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट हम लोगों के सामने सरकार ने रखा उसके विषय में हम लोगों को यह आशा थी कि अपनी आर्थिक नीति और सामाजिक नीति के ऊपर सरकार कुछ प्रकाश डालेगी, परन्तु दुख का विषय है कि बजट में केवल सरकार ने अपने खोखलेपन पर प्रकाश डाला है और अपनी नीति पर प्रकाश नहीं डाला है। माननीय वित्त मंत्री ने भाषण करते हुये कहा कि हमारा लक्ष्य सोशलिस्टिक पैटर्न का समाज बनाने का है। श्रीमन्, यहां पर प्रश्न यह उठता है कि अगर हम यह मान लें कि सरकार ने प्राथमिकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करने का प्रयास किया तो उसका फल भी हमको देखना चाहिये। उधर से माननीय सदस्य खड़े होते हैं और जब आंकड़े उनके अनुरूप होते हैं तो उन आंकड़ों को वह आंख मूंदकर मान लेते हैं, लेकिन जैसा माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने बताया वे आंकड़े परस्पर विरोधी हैं और सरकार के प्रगति के मार्ग में बाधक हैं और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाते। यदि सरकार के स्पष्ट स्वरूप का समर्थन करते हैं तो उधर से माननीय सदस्य खड़े होकर कहते हैं कि आंकड़ों को छोड़ दें और आदमी को देखें। हम आदमी को भी देखने के लिये तैयार हैं, लेकिन आखिर इतने बड़े राज्य की सामाजिक उन्नति को नापने का कुछ तो मापदंड होना चाहिये।

[राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे]

इसलिये मैं समझता हूं कि आंकड़ों को ही आज के युग में मापदंड मानना पड़ेगा। यदि उस मापदंड से हम तोलें तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार अपने लक्ष्य की ओर प्रगति नहीं कर रही है, बल्कि उस लक्ष्य से पीछे जा रही है।

श्रीमन्, सोशलिस्टिक पैटर्न की बात कही जाती है तो उसके अन्दर यह ध्वनि निकलती है कि समाज सोशलिस्टिक पैटर्न का तब होगा जब "सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सन्तु निरामया" की बात हो। समाज के रखरखाव की रचना की जाय और उस रचना में आवश्यकता यह भी हो जाती है कि आदमी बेकार न हो। तो प्रश्न यह उठता है कि उस बेकारी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या किया। श्रीमन्, मुझे कुछ तकलीफ है इसलिये मैं बैठकर बोलने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठकर बोल सकते हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन्, मगर बेकारी को दूर करने के लिये प्रयास, माननीय अर्थ मंत्री की स्पीच में और उनके बजट में कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। यहां अपनी प्रशंसा करते हैं कि साहू जैन ने सोडा ऐश फैक्ट्री खोली, और यह प्रशंसा करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने फैक्ट्री खोली, लेकिन प्रदेश की बेकारी को दूर करने के लिये सामाजिक सेक्टर के अन्दर क्या पग उठाया गया, तो कहना पड़ेगा कि कोई नहीं। दूसरे के प्रयास को अपनी सफलता कहना, मैं समझता हूं कि यह सरकार की नीति ठीक नहीं है। यह तो, श्रीमन्, वैसे ही होगा जैसे दूसरे के पंख लगाकर आदमी हंस बनना चाहे तो वह बन नहीं सकता।

श्रीमन्, इतना ही नहीं बल्कि यह सरकार पब्लिक सेक्टर में भारत सरकार से एक भी फैक्ट्री इस प्रांत के अन्दर नहीं लगवा सकी। भारत सरकार ने जितनी भी फैक्ट्री पब्लिक सेक्टर में दी है वह भी सब भिन्न-भिन्न राज्यों में गईं और यहां तक कि एलेक्ट्रिसिटी गुड्स की फैक्ट्री जो दी गई वह भी भोपाल में चली गई। हमारी सरकार कहती है कि हमारे यहां जनरल एलेक्ट्रिसिटी कम्पनी यहां पर अपनी फैक्ट्री खोलेगी। तो कारण क्या है? इसका एक ही अर्थ निकलता है और वह यह कि इस सरकार के अन्दर इतनी योग्यता और क्षमता नहीं है कि वह भारत सरकार को यह विश्वास दिला सके कि जो भी फैक्ट्री इस प्रांत को मिलेगी उसको वह सफलतापूर्वक चला सकेगी, यानी अपने रिसोर्सेज को हमने ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं किया। उसी का यह परिणाम है कि भारत सरकार को यह विश्वास नहीं रहा कि उत्तर प्रदेशीय सरकार उस तरह के कार्य को ठीक प्रकार से कर सकेगी। मैं इसलिये कहता हूं कि रिसोर्सेज को ठीक से खर्च न करने से इस बजट में बारबार डेफिसिट बजट आता है। शुरू में तो हम डेफिसिट देखते हैं लेकिन जब सप्लीमेंटरी बजट आता है तो कहते हैं कि इतना सरप्लस हो गया। सरप्लस किस मद में होता है? इस विधान सभा से तो पास कराया जाता है कि इतना इस मद में होगा और इतना इस मद में, लेकिन जितना हम पास करते हैं उतना यह खर्च नहीं करते हैं और अन्त में कहते हैं कि इतना खर्च करने से बच गया था फिर लैप्स हो जाता है। तो यह कौन सा सदुपयोग है अपने रिसोर्सेज का? जो आप पास करते हैं उसको भी खर्च नहीं कर पाते और फिर अपनी उस बचत के लिये प्रशंसा करें कि हमने इतनी इकानामी की, आप इस तरह से प्रशंसा के पात्र नहीं होते।

श्रीमन्, जितने भी इस बजट के अन्दर नये खर्चे दिखाई देते हैं उसमें बहुत से ऐसे हैं कि जो प्लान्ड आइटम में नहीं हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण एक यही है कि इस निर्माण के पीछे एक ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर है। ब्यूराक्रैट्स को जब ध्यान में आया कि कुछ करना है तो उसी समय उन्होंने एक चीज रख दी और फिर कुछ नहीं। एस्टीमेट्स भी बनाये और पता नहीं वह कितनी बार रिवाइज होते हैं!

एक बार यहां से पास कराये जाते हैं और फिर उसका बार-बार रिवीजन होता है। तो इससे क्या विश्वास होगा कि यह जो प्लान है उसका भी एस्टीमेट ठीक होगा?

खटीमा का एक एस्टीमेट बना और यदि मेरा ध्यान ठीक है तो वह ३ करोड़ का था और फिर रिवाइज होते-होते भगवान जाने कहां तक चला गया! फिर खटीमा के बनते देर नहीं और टूटते देर नहीं। बिजली का सफलता से निर्माण भी नहीं हो पाया कि वह टूट गया। तो, श्रीमन्, विश्वास कैसे हो? हमारे वित्त मंत्री जी कोआपरेशन मांगते हैं। वह कहते हैं कि लघु बचत योजना में हमारे साथ कोआपरेट करो। प्रश्न यह है कि कोआपरेशन कैसे हो। कोआपरेशन के लिये आवश्यक है कि विश्वास हो, लोगों के अन्दर यह विश्वास हो कि जो हमारा पैसा लिया जायगा उसका सदुपयोग होगा और उसको ठीक से खर्च किया जायगा। श्रीमन्, इसके लिये यह भी आवश्यक है कि लोगों के पास पैसा बचे। आपके प्रान्त के मुख्य मंत्री ने २६ दिसम्बर को एक प्रश्न का उत्तर देते समय स्वयं स्वीकार किया था कि गांव के लोगों की आमदनी सन् १९५५-५६ में १८६ रु० पर कैपिटा आकर पड़ी। यह आमदनी जिस समय प्लानिंग नहीं थी सन् १९४८ में, उस समय की आमदनी से कम थी। उस समय की आमदनी १९१ रुपये थी। अब, श्रीमन्, एक ओर तो आमदनी घटती जाती है, लोगों के पास पैसा नहीं कि स्माल सेविंग्स में इनवेस्ट कर सकें और दूसरी ओर लोगों के मन में अविश्वास होता है कि आप जो पैसा लेंगे उसका सदुपयोग भी करेंगे या नहीं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण वित्त मंत्री जी की बजट स्पीच में है। उन्होंने स्वयं कहा है कि स्माल सेविंग्स में १३ करोड़ या १२ करोड़ इकट्ठा हुआ जब कि टार्गेट २१ करोड़ का था। इस बार ९ करोड़ का टार्गेट है। तो इस प्रकार जनता में स्वयं अविश्वास दिखाई पड़ता है और जब वह अपनी असफलता स्वयं स्वीकार करती है तो यह सोचना पड़ेगा कि जनता के इस अविश्वास को दूर कैसे किया जाय।

मैं आपके द्वारा यह भी बतलाना चाहता हूं कि इस स्माल सेविंग्स का खेल क्या है। यह तो ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर का मेथेड है, लोगों के ऊपर दबाव डालकर लोगों से सेविंग्स करायी जाती है। किसी को बन्दूक का लाइसेंस चाहिये तो कहा जाता है कि २०० रुपया जमा करो तो लाइसेंस मिलेगा। सस्ते गल्ले की दूकान की जरूरत है तो सेविंग्स करने की बहुत जरूरत है वरना दूकान नहीं मिलेगी। मार्च, अप्रैल का महीना आता है तो लोग कहते हैं कि ठीक है, जमा करवो, फिर विदड्रा कर लेंगे। इसके बाद, श्रीमन्, आप देखिये कि १९५१-५२ में १०७·५६ लाख रुपया जमा हुआ, ९४·७३ लाख रुपया विदड्रा हुआ, नेट बचा १२·८३ लाख रुपया। १९५२-५३ में ११३.३५ लाख रुपया जमा हुआ, विदड्रा हुआ ९५·५२ लाख रुपया और कुल बचा १७·८३ लाख रुपया। इसी तरह से १९५३-५४ में करीब ११७ लाख रुपया जमा हुआ, १०३ लाख के करीब विदड्रा हुआ, बचा १४ लाख। इसी तरह से १९५४-५५ में १३४ लाख जमा हुआ, ११० लाख विदड्राल, बचत २४ लाख। १९५५-५६ में १५८ लाख जमा हुआ, १२१ लाख विदड्राल, बचत ३७ लाख। १९५६-५७ में १७० लाख जमा, १४४ लाख विदड्राल, बचत २६ लाख। तो इस तरह से आप देखें कि जो कुछ जमा हुआ उसका अधिक भाग निकल गया, विदड्रा कर लिया गया। कारण यही है कि जनता को विश्वास नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है कि वह अपनी बचत आपके पास रखी रहने दे।

यह कहते हैं कि प्लान्ड प्रोडक्शन में लगे हुये हैं। आपके १६१ लाख के असेट्स हैं। अब आप यह सोचिये कि ३४९ करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट है और १६१ लाख के आपके असेट्स हैं। २ प्रतिशत के सूद में भी कमी है। इस प्रकार का तमाशा देखकर क्या कोई सरकार के ऊपर विश्वास करेगा?

अब स्टेट ट्रेडिंग को ले लीजिये। ट्यूबवेल्स की बात तो मैं दुहराऊंगा नहीं। रोडवेज को आप देखिये। इसमें सरकार की मोनोपली है, इसमें कोई कम्पटीशन नहीं है।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

इसमें भी सरकार के लाभ का प्रतिशत घटता जा रहा है। १९५६–५७ में १२·०५ था, १९५७–५८ में ८·६३ और १९५८–५९ का २·१ है। अब इस असफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर कोई कैसे विश्वास करे ?

अब कृषि के बारे में लीजिये। सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी तभी हो सकता है जब कि लोग भूखे न रहें और भूखे तभी नहीं रहेंगे जब कि अन्न का उत्पादन बड़ी मात्रा में होगा। कब तक हम अन्न बाहर लेते रहेंगे ? अन्न के उत्पादन के आंकड़ों को देखा जाय तो मालूम होगा कि सन् १९५०–५१ में हमने ११·४६ मिलियन टन पैदा किया और १९५५–५६ में ११·३५ मिलियन टन पैदा किया। इस प्रकार से ४ वर्ष में .११ मिलियन टन कम अनाज पैदा किया। सन् ४८ में, जब कि फूड की कोई प्लानिंग नहीं थी, जितना अन्न पैदा होता था उसको भी यदि हम बेस मान लें और उस समय के आंकड़ों और आज के आंकड़ों को भी मिलायें तो मैं पूछूगां कि आपकी योजना बनती है विकास की वृष्टि से अथवा ह्रास की वृष्टि से। और अगर सरकार ने गल्ला बढ़ाने की वृष्टि से योजना बनायी थी तो सरकार उसमें असफल रही। यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण ऐसा हुआ। प्राकृतिक प्रकोप १–२ साल में तो हो सकता है, लेकिन क्या ५ साल तक वह चलता ही रहा ? ऐसा कहना गलत होगा।

इसी प्रकार से, श्रीमन्, यह तो सर्वमान्य है कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान राज्य के उत्थान के लिये यह आवश्यक है कि उसको इन्डस्ट्रियलाइज किया जाय और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी के लिये यह आवश्यक है कि उद्योगों की वृद्धि पब्लिक सेक्टर में हो। लेकिन यह सरकार ऐलान तो करती है सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का और उद्योग की वृद्धि करती है प्राइवेट सेक्टर में। नतीजा यह हो रहा है, कि प्रान्त के अन्दर कुछ उद्योगपति ही धनीमानी हो रहे हैं। जो धनी हैं वे अधिक धनी बनते जा रहे हैं, जो निर्धन हैं उनकी आमदनी और भी घटती जा रही है। श्रीमन्, इसका परिणाम यह होता है कि आमदनी का अनइक्वल डिस्ट्रिब्यूशन होता जाता है।

श्रीमन्, एक प्रश्न यह उठता है कि सोशलिस्टिक पैटर्न की यह घोषणा करते हैं, उसके पीछे एक प्राईसिंग पालिसी होनी चाहिये, वह हमारी सरकार की नहीं रही है। क्योंकि श्रीमन्, दो प्रकार की प्राईसिंग पालिसी दुनिया के देशों में चल रही है। पूंजीवादी देशों में यह होता है कि कैपिटल इनवेस्टमेंट में जितना उत्पादन पर खर्च करते हैं उसको जोड़कर और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा कर चीजों की प्राइस निर्धारित करते हैं। श्रीमन्, समाजवादी देशों के अन्दर एक दूसरी आर्थिक विचारधारा भी चल रही है, जहां पहले जितना इनवेस्ट कर दिया, उसको वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि उसका डेप्रिसिएशन चार्जेज और जितना उत्पादन पर खर्च हो, उसको जोड़ कर प्राइस फिक्स होनी चाहिये।

अब प्रश्न यह उठता है कि समाजवादी राज्यों के अन्दर उत्पादन सस्ता होना चाहिये और उत्पादन बढ़ना भी चाहिये और कीमत भी सस्ती होनी चाहिये। लेकिन इस सरकार की कोई पालिसी नहीं है। पूंजीवादी देशों में चीजों के दाम सस्ता करने के पीछे कम्पटीशन रहता है। उसका परिणाम यह होता है कि चीजें सस्ती होती हैं। हमारे यहां, श्रीमन्, ऐसा कोई कम्पटीशन नहीं है। यहां तक कि जो स्टेट अन्डरटेकिंग्स हैं जिसके अन्दर सरकार की मोनोपली है, वहां के उत्पादित सामान भी बाजार में सब प्रकार से लोगों को मंहगे पड़ेंगे। एक उदाहरण देकर मैं समझाऊं तो शायद ज्यादा स्पष्ट हो जायगा, मान लीजिये १० लाख रुपया किसी अंडरटेकिंग में इनवेस्ट किया गया है जिसमें ५ लाख यूनिट सामान तैयार किया गया और उसमें ५ लाख रुपया खर्च हुआ। तो इसके माने यह हुए कि १ रुपया कास्ट प्राइस हुआ और १० लाख रुपये को वापस भी लेना है

चार वर्ष में, तो ढाई और एक साढ़े तीन रुपया एक यूनिट पर जाकर खर्च पड़ा। तो इसके आधार पर वहां प्राइस तय किया जाता है। दूसरी तरफ जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनके लिये तो १० लाख रुपया जो इनवेस्ट हो चुका है उसके वापस लेने की आवश्यकता ही नहीं है। थोड़ा-सा डेप्रिसियेशन चार्ज लगा लिया और उसको एक रुपया ऐक्चुअल कास्ट में जोड़ दिया तो करीब सवा रुपया फी यूनिट पड़ा।

श्रीमन्, नारा तो लगाया जाता है समाजवाद का, लेकिन व्यवहार उसके बिलकुल विपरीत है। सरकारी अंडरटेकिंग्स में निर्मित सामान सस्ते होते हैं, लेकिन यहां पर उसका लाभ कंज्यूमर्स को नहीं है। कैपिटलिज्म में तो यह होता है कि कम्पटीशन के जरिये चीजों का दाम कम किया जाता है, जिस से कंज्यूमर्स को लाभ रहता है; और समाजवादी विचारधारा के अनुसार प्राइस कास्ट के अलावा कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज वगैरह जोड़कर चीजों का दाम निर्धारित कर लिया जाता है, लेकिन सरकार दोनों में से थोड़ी-थोड़ी चीजें लेकर काम करती है जिससे बुराई ही सामने आती है, किसी की भलाई सामने नहीं आती। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह प्राइस फिक्स करने के लिये एक कमीशन नियुक्त करे जो सब प्रकार की बातों पर विचार करे और उसके आधार पर निर्मित सामानों की प्राइस फिक्स करे। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने तो कई कमीशन का निर्माण किया है, लेकिन इस सरकार ने एक भी कमीशन का निर्माण आज तक नहीं किया है। मैं चाहूंगा कि इस ओर सरकार विचार करे जिस से जो सामग्री उत्पादित हो वह कंज्यूमर्स को सस्ती मिले।

श्रीमन्, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल उठता है वहां यह भी प्रश्न उठता है कि क्या सोशलिस्टिक पैटर्न में इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की आवश्यकता है। यदि है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की तरफ सरकार ने क्या पग उठाया। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी लाने के लिये आवश्यकता यह होती है कि श्रमिकों को अपने भाग्य का निर्णय करने के लिये सरकार को मैनेजमेंट में अधिकार देना चाहिये। मैं समझता हूं कि कई महीने पहले भारत सरकार की एक रिपोर्ट श्रमिकों को कुछ अधिकार दिलाने के सम्बन्ध में आयी है, मैं पूछता हूं कि इस सरकार ने उसके लिये अपनी तरफ से क्या प्रयास किया है। प्राइवेट मिलों की बात तो छोड़ दें, लेकिन चुर्क सीमेंट फैक्टरी में इसे लागू करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रयास किया है? क्या सरकार ने उनको चुर्क में किसी प्रकार का कोई अधिकार दिया है? क्या उसने कोई और पग इस प्रकार का उठाया? इसी तरह से प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी में क्या कोई पग इस प्रकार का उठाया गया? क्या वहां पर प्राफिट्स में शेयरिंग का कोई स्टेप लिया गया? आज यह सिद्धान्त माना जाता है कि फैक्टरीज में मालिकों के अलावा निर्माताओं को भी लाभ में हिस्सा मिले, क्या आपने उसके अनुसार कोई पग उठाया? कोई कदम इस प्रकार का नहीं उठाया गया।

आज दुनियां में जो अपने को सबसे आगे कहने वाले देश हैं, चाहे वह पूंजीवादी हों या समाजवादी हों, उन्होंने श्रमिकों को ट्रिपिल बेनिफिट देने के सिद्धान्त को माना है, कलेक्टिव बार्गेनिंग और प्राविडेंट फंड-कम-इन्श्योरेन्स की सुविधायें वे देते हैं, आपने भी इस दिशा में अपने यहां कुछ किया है। अमरीका तक में यह अधिकार श्रमिकों को मिलता है। आपने भी कलेक्टिव बार्गेनिंग के सिद्धान्त को मानकर कोई पग उठाया? यही नहीं वरन् ट्रिपिल बेनिफिट के किसी अंग की तरफ कोई पग नहीं उठाया गया है और केवल शुगर कोटेड शब्दों में भुलावा देने की ही कोशिश की गई है। केवल "अहं वदामि एवं वदामिनो" से ही काम नहीं चलता, आपकी घोषणा में और आपकी करनी में महान अन्तर है, यह कहने के लिये हम मजबूर हैं।

वास्तव में अगर देखा जाय तो इस सरकार का स्वयं समाजवादी पैटर्न का समाज बनाने का जो लक्ष्य है उस ओर नहीं है। कुटीर उद्योगों और बड़े उद्योगों के बीच एक

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

समन्वय लाने का कोई प्रयत्न यहां नहीं हुआ और न मैन पावर और मशीन पावर का कोई बन्धन फिक्स्ड रूप से बांधने का प्रयास हुआ है। छोटे कारखाने बनाने का भी इस प्रदेश में कोई प्रयत्न नहीं हुआ है। इस प्रकार की गलत आर्थिक निति का यह परिणाम है कि देश में बेकारी बढ़ रही है और लोगों को एम्प्लायमेंट नहीं मिल रहा है। जो हमारे यहां के पढ़े लिखे लोग हैं उनके एम्प्लायमेंट के प्रश्न को और भी जटिल बना दिया गया है। रिटायरमेंट की एज को ५५ से बढ़ाकर ५८ कर दिया गया है। क्यों किया, इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है। परन्तु इसका भीषण परिणाम होगा, जो लोग ५५ साल की अवस्था में पेन्शन पाते वह अब ३ साल तक और सर्विस में रहेंगे। अधिकारी बढ़ते जाते हैं और काम का डुप्लीकेशन बहुत बढ़ा हुआ है, एक-एक काम को दो और अधिक आदमी करते हैं जिसके कारण से सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च बहुत बढ़ता जाता है जिसे टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। यहां पर सरकार का एक सूचना विभाग मौजूद है परन्तु आप बजट में देखेंगे कि कृषि विभाग के पास भी अपना पब्लिसिटी विभाग है, हर विभाग के पास एक पब्लिसिटी विभाग है, इस प्रकार के डुपलीकेशन की क्या आवश्यकता है। क्यों नहीं सूचना विभाग के द्वारा ही सब विभागों की पब्लिसिटी का कार्य कराया जाता है। आप करोड़ों रुपया जब कि सूचना विभाग पर खर्च करते हैं तो वह इस काम को सब विभागों की ओर से कर सकता है। इस डुपलिकेशन के कारण सारी अर्थ व्यवस्था एक्स्ट्रावेगेन्ट और टापहैवी होती जाती है।

मैंने स्टेटिस्टिक्स विभाग से कुछ आंकड़े मांगे, उन्होंने कृपा करके वह आंकड़े मेरे पास भेजे और वह मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि इस राज्य में ५० से ३०० रुपया तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर ३०० से ३,००० रुपया तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर १९५३ से ५६ तक कितना व्यय हुआ है इसकी फिगर्स दे दें। वह आंकड़े मेरे पास हैं। सन् ५३--५४ में ५० से ३०० तक वेतन पाने वालों पर स्टेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का १५·११ प्रतिशत व्यय हुआ, जब कि ३०० से ३,००० रु० वेतन वालों पर हुआ ३·२५ प्रतिशत। सन् ५४-५५ में ५० से ३०० तक पाने वालों पर हुआ १४·७७ और ३०० से ३,००० रु० वालों पर ३.३० प्रतिशत और सन् ५५-५६ में ५० से ३०० रु० तक पाने वालों पर हुआ, १५·७२ प्रतिशत और ३०० से ३,००० रु० तक वालों पर ३·३७ प्रतिशत व्यय हुआ। अन्त में उन्होंने लिखा है कि १९५६-५७ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। इन आंकड़ों को यदि जोड़ लें तो प्रकट हो जाता है कि इस टापहैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन पर राज्य की सारी आय का २० प्रतिशत व्यय हो जाता है। १०८ करोड़ का बजट है। उसका २० प्रतिशत या मोटे तौर से २२ करोड़ केवल सरकारी अधिकारियों की तनख्वाह के अन्दर चला जाता है। आनरेरिया, कंटिंजेंसी, और मंहगाई का भत्ता छोड़ दीजिये, तो २२ करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों पर खर्च करते हैं। यह टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो क्या है? अगर इस ऐडमिनिस्ट्रेशन में इकानामी की गयी होती तो मेरा विश्वास है कि इसके अन्दर सात, आठ करोड़ रुपया जरूर बच जाता। अगर वह रुपया छोटे उद्योग में लगाया होता तो जो पूंजी का डिफ्युजन हुआ उससे बेकारी कम हुई होती, प्रोडक्शन का यूनिट बढ़ा होता। लेकिन इस ओर सरकार ने कुछ नहीं किया।

एक दूसरा उदाहरण ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी का लूं, श्रीमन्, १९५४-५५ में, फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, आंध्र के अन्दर पुलिस पर १·३ खर्च किया गया और उत्तर प्रदेश में १.२ खर्च किया। बम्बई जो इस प्रदेश से बड़ा है, जिसके रिसोर्सेज हम से ज्यादा हैं उसका खर्च पुलिस के ऊपर २·६ है। इसी प्रकार जितनी इनकी सर्विसेज हैं अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में देखें तो उत्तर प्रदेश ने ·५ खर्च किया जब कि इनके बराबर कुर्ग जैसे राज्य ने ·५ खर्च किया। सोशल सर्विसेज के बारे में कहा जा चुका है इसलिये मैं उसको दोहराने का प्रयास नहीं करूंगा।

१९५५-५६ में सोशल सर्विसेज में उत्तर प्रदेश ने ३·२ खर्च किया ।

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि दस मिनट और दे दिये जायं तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि पांच मिनट काफी होंगे ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मैं पांच मिनट में कहने की कोशिश करूंगा ।

तो इनका सारा खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर बढ़ता जा रहा है, यह टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन का परिणाम है । वास्तव में जो पैसा प्लांड यूनिट आइटम्स में लगना चाहिये, जिससे प्रान्त का उत्थान हो सके, प्रोडक्शन बढ़ सके, बेकारी दूर हो सके किन्तु उस ओर कोई प्रयास नहीं किया गया ।

अगर हम शिक्षा की ओर दृष्टिपात करें तो इस सेक्टर के अन्दर पंजाब जैसे प्रान्त में बसवें क्लास तक शिक्षा निःशुल्क है, लेकिन उत्तर प्रदेश में दरजा छः तक ही फ्री एजूकेशन है । यह प्रान्त पंजाब से बड़ा , रिसोर्सेज इसके उससे ज्यादा हैं, लेकिन फ्री एजूकेशन में उससे पीछे है । इनका शिक्षा का दृष्टिकोण बड़ा विचित्र है । प्राइमरी शिक्षा के मास्टरों की स्थिति सुधारने की दृष्टि से इस बजट में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है । मास्टरों के वेतनों में जो असमानता है, सरकारी स्कूलों के मास्टरों की तनख्वाह ज्यादा और प्राइवेट स्कूलों के मास्टरों की कम, उस असमानता को दूर करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया । इस प्रान्त के ९० प्रतिशत लड़के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन शिक्षा का जितना बजट है गवर्नमेंट स्कूलों से केवल दो प्रतिशत ही ज्यादा प्राइवेट स्कूलों पर खर्च किया जा रहा है। जब कि इसमें ९१ प्रतिशत लड़के पढ़ते हैं तो केवल दो प्रतिशत ज्यादा और गवर्नमेंट स्कूल जिनमें केवल ९ प्रतिशत लड़के पढ़ते हैं उनको आधा के लगभग पैसा देना, इस प्रकार का दुर्लक्ष्य क्यों ? क्या गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने वाल सौभाग्यशाली हैं और ज्यादा टैक्स देते हैं और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले दुर्भाग्यशाली हैं और कम टैक्स देते हैं ? जो कम टैक्स देते हैं उनके बच्चों पर पैसा कम खर्च हो और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर ज्यादा खर्च हो, यह दो आंख से देखने की सरकार की जो नीति है वह गलत है ।

इस प्रान्त में निरक्षरता को दूर करने के लिये, प्रान्त को साक्षर बनाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये, उसके बारे में भी बजट में कोई वर्णन नहीं है । और तो श्रीमन्, जाने दें, इस बजट में केवल लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के घाटे को पूरा करने की बात को छोड़कर और कोई चर्चा दूसरी जगहों की नहीं है । अभी आप सुन चुके हैं इतना छोटा सा सीलोन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री, इस प्रदेश से छोटा पंजाब टेन्थ क्लास तक एजुकेशन फ्री । हम साइज में बड़े , रिसोर्सेज में बड़े पर काम में सबसे छोटे । यह जो समाज के अन्दर डेफ और डम्ब विद्यार्थी हैं, जो अपाहिज विद्यार्थी हैं उनकी जिम्मेदारी भी शिक्षा विभाग ने अपने ऊपर नहीं ली । उनकी जिम्मेदारी सोशल सर्विसेज पर डाल दी । सोशल सर्विसेज पर आप सबसे कम खर्च करते हैं । उनके ऊपर कितना खर्च किया गया इसका कहीं वर्णन नहीं है । इस प्रकार की दुर्लक्ष्यपूर्ण नीति समाज के लिये घातक है, इससे समाज का उत्थान नहीं हो सकता ।

किसी विभाग की ओर आप देखें, ला विभाग को देखें । इसी सरकार के ही आंकड़े इस बात के स्पष्ट द्योतक हैं कि मुकदमे कितने बकाया रहते हैं । मुकदमे दायर होते हैं और फैसला होने तक आधे से ज्यादा पड़े रहते हैं । यह जो पड़े रहते हैं इसका नतीजा यह होता है कि 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ।'

श्रीमन्, पुलिस के बारे में बड़ी चर्चा होती है । पुलिस का खर्चा बढ़ता है, पुलिस के अधिकारी बढ़ते हैं, कांस्टेबिल बढ़ते हैं । परन्तु उसके साथ-साथ क्राइम भी बढ़ता जा रहा है । श्रीमन्, यदि आप पांच मिनट के लिये आज्ञा दें तो मैं इसके आंकड़े सुना दूं । हीनस क्राइम्स २५ हजार सन् ५४ में थे और ४६ हजार सन् ५६ में हो गये । आर्डिनरी क्राइम्स की संख्या

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

३८,८८२ थी और सन् १९५६ में वह ४२,०९३ हो गई । इतना तो क्राइम बढ़ा । रिपोर्ट वह लिखाते हैं पुलिस के अन्दर । पुलिस ने इन्वेस्टीगेट जो किये, मैं पिछले आंकड़े छोड़ देता हूं, केवल ५६ के आंकड़े देता हूं, २४ हजार पुलिस ने इन्वेस्टीगेट किये और उसमें से प्रासीक्यूट करती है केवल ८ हजार । यानी हीनस क्राइम्स जो इन्वेस्टीगेट किये गये उनके एक तिहाई प्रासीक्यूट किये जाते हैं और जो प्रासीक्यूट होते हैं उनके आधे केवल ४ हजार कन्विक्टेड होते हैं । तो २५ हजार मामलों में केवल ४ हजार में सजा होती है, लेस दैन वन सिक्स्थ (Less than one-sixth) । इसी प्रकार राबरी, डकैती आदि को देखें, एक ही बात पायेंगे । योजनापूर्ण इस प्रान्त में किसी चीज की वृद्धि हुई है तो पुलिस की अकर्मण्यता में और इसके परिणामस्वरूप क्राइम और बढ़ा है । मैं श्रीमन् से पांच मिनट और चाहूंगा ....

श्री अध्यक्ष—आप का समय अब इसके बाद दो मिनट में खत्म हो जायगा । मैं अधिक समय नहीं दे सकूंगा ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन्, मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इसके साथ साथ एक इकोनामी और एफिश्येंसी कमेटी का निर्माण करे जो बराबर इस बात के ऊपर ध्यान दे कि प्रान्त का राज्य संचालन एफिश्येंटली हो और इकोनामिकली हो । इस प्रकार का वेस्टेज न हो । इस राज्य के बजट के लिये तो मुझे शेक्सपीयर का एक पद याद आता है—इट इज ए टेल टोल्ड बाई ए मिनिस्टर फुल आफ सारो ऐंड फ्यूरी सिगनीफाइंग नथिंग (It is a tale told by a minister full of sorrow and fury signifying nothing) ।

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और २-२० पर फिर बैठेंगे ।

(इस समय १ बज कर १९ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी सरकार का बजट उसके एक साल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारनामों का एक आईना होता है जो वह सदन के सामने पेश करती है । इस बजट के जरिये यह बतलाया गया है कि इस साल क्या-क्या काम सरकार की तरफ से होंगे । यह भी दावा है कि सोशलिस्टिक पैटर्न के कयाम के लिये यह बजट एक कदम हमको और आगे बढ़ायेगा । यह बात सही है । जब हम बजट पर नजर डालते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें देखते हैं जो हमें सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ ले जाती हैं । इसमें बूढ़े लोगों के लिये जो पेंशन का बंदोबस्त किया गया था वह जारी रहेगा । तालिबइल्मों को पढ़ाई के जमाने में भी ट्रेनिंग के लिये मौके दिये जायेंगे । रिहंद जैसी बड़ी स्कीम जो हमारी हुकूमत की कोशिशों से फाइव ईयर प्लान में शामिल हो गई है उसका काम भी जारी रहेगा । यह तमाम बेशुमार बातें हैं जो हमें सोशलिस्टिक पैटर्न की ओर ले जाती हैं ।

इस बजट का तखमीना १ अरब ४६ करोड़ रुपये का है । इसमें कैपिटल और रेवेन्यू एकाउंट्स, दोनों, शामिल हैं । मुझे याद है कि सन् १९३७ ई० में जब पहली असेम्बली आयी थी उस वक्त यहां का बजट साढ़े १२ करोड़ रुपये का था, यानी तब से अब १० या ११ गुना बढ़ गया । जाहिर है यह सब रुपया इसी सूबे और इसी सूबे के बसने वालों की भलाई पर सर्फ किया जा रहा है । मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इतने रुपयों के खर्च होने के बाद भी इस सूबे की प्रास्पेरिटी नहीं बढ़ेगी । हां, एक बात सही है कि यह सातवां मुसलसल बजट है जिसमें रेवेन्यू रिजर्व फंड से रुपया निकलेगा और इस से घाटे को पूरा किया जायगा । इसी तरह से किया जाता रहा है । मुझे इस से इस बात का अंदेशा होने लगता है कि इस तरीके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से इंतजाम करके कब तक हम अपने बजट को चलायेंगे और रेवेन्यू रिजर्व फंड जो बराबर घटता चला जा रहा है वह कब तक चलेगा । एक दिन जल्द ऐसा आ सकता है जब इसमें रकम बाकी नहीं रहेगी जिससे हम अपने घाटे को पूरा कर सकें। हुकूमत को इस तरफ खास तौर से तवज्जह देने की जरूरत है ।

इस बजट में साढ़े ४ करोड़ रुपये का घाटा है । मैं घाटे के बजट से घबराने वाला नहीं । मैं समझता हूं कि जो हुकूमत घाटे का बजट पेश करे उससे हमें यह यकीन आ सकता है कि बावजूद सरमाये की कमी के हुकूमत जो कदम अपने सूबे और मुल्क को ऊंचा उठाने और तरक्की देने के लिये मुनासिब समझती है उसमें कोई कमी रखना नहीं चाहती । रुपये की कमी से कोई काम रुके, ऐसा उसका इरादा नहीं है और यह बहुत मुबारक चीज है ।

अगर इस बजट को जरा गौर से देखें तो मालूम पड़ेगा कि यह प्लानिंग का बजट है । प्लानिंग की तस्वीर जो साल-ब-साल हमारे सामने आती है, इस बजट में भी उसे दोहरायी गई है । गो बजट की तकरीर जो माननीय वित्त मंत्री ने की वह उतनी कलरफुल नहीं थी जितनी पिछले सालों में, लेकिन फिर भी वह एक विजिनेसलाइक तकरीर थी । उसके जरिये से उन्होंने बहुत सादगी और सफाई के साथ वह तमाम वाकयात हमारे सामने रख दिये हैं जिनके मातहत हम बजट पर विचार कर सकते हैं । मेरे पास इतना वक्त नहीं है और न मैं आंकड़ों की तरफ जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस सिलसिले में कुछ बातें हैं जिन्हें मैं माननीय मंत्री के सामने पेश करूंगा ।

मैंने यह देखा है कि इस बजट पर बहुत से एतराज हुये हैं जिनमें से बाज बाज तो बेबुनियाद हैं, बाज नाकाबिले अमल हैं और बाज ऐसे हैं जिनको सुनकर कुछ ताज्जुब भी होता है । मेरे काबिल दोस्त नारायणदत्त जी तिवारी ने अभी अपनी तकरीर में एक सुझाव यह दिया था कि बजट बजाय अप्रैल के नवम्बर से तैयार होना चाहिये । मगर मैं उनको याद दिलाऊंगा कि दुनिया के मौजूदा हालात में जब कि हम सारी दुनिया के एक पार्ट एंड पार्सल हैं और जब दुनिया खिंच कर एक जगह आ गयी है, सारी दुनिया के अकाउंट्स अगर अप्रैल से शुरू होकर मार्च में खत्म होते हैं, अगर हमारे एकाउंट्स फरवरी से जनवरी तक रखे जायें तो इससे बड़ा घाटा होगा । हम कोशिश करते रहें पहले कि हम छुट्टी जो इतवार की देते हैं उसको इतवार को न देकर किसी और दिन दें, लेकिन जो बैंकिंग का सिस्टम दुनिया का है उसको देखते हुये हमें इतवार को छुट्टी देना लाजिमी है और अगर कोई दूसरी छुट्टी भी दें तो हमें हफ्ते में दो दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी । इस लिहाज से मैं समझता हूं कि यह सुझाव मुमकिन नहीं मालूम होता ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में सबसे ज्यादा जो रकम रखी गयी है वह प्लानिंग के लिये है । प्लानिंग पर अलहदा भी रुपया रखा गया है और मुख्तलिफ विभागों में भी प्लानिंग में रुपया खर्च करने की स्कीम है । प्लानिंग पर जो रुपया हम सर्फ कर रहे हैं, जाहिर है कि उसका कोई शुमार नहीं, काफी रुपया हम सर्फ कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि प्लानिंग पर जो रुपया हम सर्फ करते हैं उसका उतना नफा हम उठा पा रहे हैं या नहीं । प्लानिंग के जरिये से काफी रुपया हम ब्लाक्स पर, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पर सर्फ कर रहे हैं । मुझे ऐसा लगता है कि जो रुपया हम सर्फ कर रहे हैं और जिससे इस सूबे में हमने काफी तरक्की भी हासिल की है, अगर उसे हम पंचायतों पर सर्फ करना शुरू कर दें तो ज्यादा कामयाबी हासिल हो सकती है । प्लानिंग का जो हमारा तरीका है वह अमेरिकन सिस्टम पर है । हम उसी सिस्टम पर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिये कि ब्लाक्स के पास काफी रुपया है और वह खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर पंचायतों की तरफ नजर डालें तो हम देखेंगे कि हमारे प्राचीन इंस्टीट्यूशंस बिलकुल स्टार्व हो रहे हैं । एक पंचायत की आमदनी २५० रुपया से ज्यादा नहीं होती, उसमें से १२० रुपया तो सेक्रेटरी की तनख्वाह पर सर्फ करना पड़ता है और १० रुपया पत्रिका वगैरह का खर्चा, इस तरह से उसके पास ५०–६० रुपये रह जाते हैं । उससे वह क्या काम कर सकती है ? अगर हम प्लानिंग ब्लाक से हट कर पंचायतों पर ज्यादा जोर दें और उनको एक मजबूत यूनिट

[श्री सुल्तान आलम खां]

बनाने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि हमको ज्यादा कामयाबी हासिल हो सकती है । इसमें शक नहीं कि हम फारेन एक्सचेंज की वजह से बड़ी हद तक दूसरों के मुहताज हैं, दूसरों की इमदाद पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी इसके यह माने नहीं हैं कि जब हम निजाम बनाने वाले हैं, जो सिस्टम बनाने वाले हैं वह अमेरिकन हों । वह वहां से जुदा हो सकता है और जिसके ऊपर हमारे सूबे और मुल्क की हमारी कल्चर और सिविलाइजेशन की बुनियाद रहती है । अगर उस पंचायत को यूनिट मान कर चलने की कोशिश करें तो ज्यादा कामयाबी हो सकती है ।

प्लानिंग के बाद और दूसरी चीजें जिनसे कि इस मुल्क और इस सूबे की तरक्की वाबस्ता है वह यहां की इंडस्ट्री और ऐग्रीकल्चर हैं । मैं इंडस्ट्री का कायल हूं और मैं जानता हूं कि आज-कल के जमाने में किसी मुल्क की इकानामी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि वह मुल्क इंडस्ट्रियलाइज न हो जाय । लेकिन हमारी एक मखसूस हालत है । जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री ने अभी हाल की एक तकरीर में फरमाया कि यह सही है कि हम इंडस्ट्री पर ज्यादा जोर देंगे और इस प्लान में इंडस्ट्री पर खासतौर सेज्यादा जोर दिया गया है, लेकिन हम ऐग्रीकल्चर को किसी हालत से भूल नहीं सकते । खास तौर से इसलिये कि इंडस्ट्री से जो रुपया हम हासिल करेंगे वह रुपया वही होगा जो हम एग्रीकल्चर के प्राफिट से हासिल करके और उससे बचत करके इंडस्ट्री पर लगायेंगे । इसी तरीके से हम ऐग्रीकल्चर के प्राफिट से रुपया हासिल करके इंडस्ट्री पर सर्फ कर सकते हैं और मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज कर सकते हैं । लेकिन ऐग्रीकल्चर उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसका जो बेसिक सैक्टर इर्रिगेशन है उसकी तरफ हमारा खास ध्यान न हो ।

अभी इर्रिगेशन के मुताल्लिक बहुत से सुझाव आये हैं, बहुत से ऐतराज भी हुये हैं । लेकिन मैं एक बुनियादी बात सोचता हूं और वह यह है कि इर्रिगेशन और ऐग्रीकल्चर का चोली दामन का साथ होना चाहिये । इससे मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि ऐग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और इर्रिगेशन मिनिस्ट्री जो इस वक्त अलग-अलग हैं वह काम ठीक नहीं कर रही हैं । वह तो बड़ी मेहनत से काम कर रही हैं और उन पर हमें पूरा-पूरा भरोसा है । लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर ऐग्रीकल्चर और इर्रिगेशन इन दोनों में आपस में कोआपरेशन और कोआर्डीनेशन बिल्कुल नहीं है । इस वास्ते मैं माननीय मंत्री जी की खिदमत में निहायत अदब के साथ यह सुझाव पेश करूंगा । अगर वह चाहते हैं कि ऐग्रीकल्चर जो सूबे की बैक बोन है और नेशनल ऐक्टीविटीज का एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट आइटम है उसको सही माने में तरक्की दी जाय तो ऐग्रीकल्चर और इर्रिगेशन के पोर्टफोलियोज को एक करना चाहिये और दोनों में जहां तक कोआपरेशन और कोआर्डीनेशन मुमकिन हो सके वह करना चाहिये ।

यह भी सही है कि ऐग्रीकल्चर के सिलसिले में हमने ऐक्सटेंसिव कल्टीवेशन पर जोर दिया है और उसके नतायज भी हमारे सामने आये हैं । लेकिन हम समझते हैं कि अब वह वक्त आ गया है कि ऐक्सटेंसिव कल्टीवेशन के मामले में हम सैचूरेशन प्वाइंट की हद तक पहुंच चुके हैं । अब जब तक कि हम इंटेंसिव कल्टीवेशन की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारे मसायल हल नहीं हो सकते हैं ।

जनाबवाला, मैं एक चीज और गवर्नमेंट की नोटिस में लाना चाहता हूं । जहां तक इस सूबे के अंदर प्रायोरिटीज का सवाल है उसके मुताल्लिक मुझे कुछ अर्ज करना है । हमें अगर अपने सूबे को आगे बढ़ाना है और प्लान्ड इकानोमी के मातहत चलना है तो हमें प्रायोरिटीज मुकर्रर करनी पड़ेगी और मैं समझता हूं कि जो हमने प्रायोरिटीज मुकर्रर की हैं They are not the last words on the subject । इसमें हेर फेर की गुंजायश हो सकती है और हमें चाहिये कि इनको बेहतर बनायें । मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करूं कि हमारे सूबे में कई साल से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है । हमने रोड्स को नेशनेलाइज कर दिया है । यह ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर हम हाउसिंग प्राबलम को लेकर कोई

इंतजाम कर सकते तो सूबे का ज्यादा भला हुआ होता और उससे औसत तबके के लोगों को जो मकान की मुसीबत से परेशान रहते हैं, कुछ सुकून मिलता। मैं आपसे ज्यादा वक्त की ख्वाहिश कर सकता हूं अगर आप इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष--अभी तो आपके दो मिनट हैं ही। कितने मिनट और चाहियें, पांच मिनट ?

श्री सुल्तान आलम खां--दस मिनट दे दें तो बहुत अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष--नहीं, पांच मिनट ले लीजिये।

श्री सुल्तान आलम खां--बहुत अच्छा। जनाबवाला, यहां तकरीरों के दौरान में यह बात सामने आई और हमने पढ़ीं कि हमारे यहां का प्रोडक्शन कम हुआ। इसकी कुछ वजह तो नेचुरल कैलेमिटीज हैं जिसके ऊपर न किसी की कोई कुदरत है और न किसी का असर है। लेकिन यह भी अजीब बात है कि जहां तक प्रोडक्शन की मिकदार का ताल्लुक है वह बढ़ी है, लेकिन पर कैपिटा कमी वाकई हुई है। इसकी वजह क्या है ? प्रोडक्शन का जहां तक ताल्लुक है, उसमें तो बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन पर कैपिटा में कमी क्यों हुई ? इसकी वजह एक ही है कि हमारे सूबे के अन्दर, हमारे मुल्क के अन्दर, आबादी की रफ्तार बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। जितना प्रोडक्शन हमारा होता है उससे ज्यादा हमारी आबादी बढ़ जाती है। श्रीमन्, मुझे अंदेशा है, अगर यही हालत जारी रही तो ऐसा वक्त आयेगा कि बावजूद इसके कि हम सारा फारेन ऐक्सचेंज खर्च करके बाहर से गल्ला मंगायें तब भी पूरा नहीं होगा। पूरब के लोग कहा ही करते हैं कि गल्ला कम होता है। मैं समझता हूं कि आबादी के बढ़ने की यही रफ्तार रही तो फिर पूरब पश्चिम का कोई सवाल नहीं रह जायगा और इस सूबे की मुश्किलात हल नहीं होंगी, बल्कि बढ़ती चली जायंगी।

इसलिये मैं सरकार की तवज्जह खासतौर पर इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जहां तक फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल का ताल्लुक है उसकी तरफ खास तवज्जह करे। एक जमाना था जब फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल के आइडिया को लोग रिडीक्यूल किया करते थे। उसके बाद उस पर कुछ सीरियसली सोचना शुरू कर दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि आज वह वक्त आ गया है कि इस मामले पर हमें पूरी तवज्जह देनी है और हमें इस सिलसिले में बहुत कुछ आगे बढ़ना है और अगर हम आगे नहीं बढ़े तो वक्त आगे बढ़ जायगा और हम बहुत पीछे रह जायेंगे।

जब प्रोडक्शन को हम देखते हैं तो एक चीज और हमारे सामने आती है कि जहां तक गल्ले का ताल्लुक है उसकी पैदावार तो घटती जाती है, लेकिन कैश क्राप्स, जैसे शूगर केन बढ़ती चली जाती हैं। यह बड़ी अच्छी बात है कि शूगर-केन की मिकदार बढ़ जाय। इससे काश्तकारों की जेब में ज्यादा पैसे आयेंगे, लेकिन जहां तक खाने-पीने का ताल्लुक है, उसकी प्रायोरिटी पहले है। अगर खाने-पीने का मामला हल न हो सका तो इसके माने यह हैं कि बावजूद इसके कि हमारे पास बहुत से पैसे कैश क्राप में आये फिर भी हम मुसीबत के मुसीबत में ही रहेंगे और कभी हमारी बेहतरी नहीं हो सकती। इस सिलसिले में सिवाय इसके और कुछ हो नहीं सकता कि गवर्नमेन्ट क्राप प्लानिंग की तरफ तवज्जह दे। मैं जानता हूं और इस मुश्किल से वाकिफ हूं कि क्राप प्लानिंग के मुताल्लिक कोई कानून हम यहां बैठ कर बनायें, लेकिन अगर हम इस मामले में परसुएशन और ऐडवाइस के सिलसिले में आगे कदम बढ़ायें तो मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ इससे नतीजा निकल सकता है।

ऐग्रीकल्चर चूंकि हमारे सूबे की वह चीज है जिस पर इस सूबे के लोगों के रहन-सहन का दारोमदार है, लिहाजा मैं इस सिलसिले में एक बात और हुकूमत के पेशे नजर करना चाहता हूं और वह यह है कि ऐग्रीकल्चर के लिये तो सूबे में बहुत कुछ किया गया है, लेकिन उसी का एक अंग है हार्टिकल्चर उसके मुताल्लिक हम अब तक वह सब नहीं कर सके जो करना चाहिये था जहां तक हमारी फूड प्राब्लम का ताल्लुक है हार्टिकल्चर उस सिलसिले में एक बड़ी

[श्री सुल्तान आलम खां—]

हद तक मदद कर सकता है, लेकिन अभी तक वह पार्ट ऐंड पार्सल है ऐग्रीकल्चर का। अगर हार्टिकल्चर का एक डायरेक्टोरेट कायम किया जाय और उसको भी हम पायलट प्रोजेक्ट स्कीम्स निकालें तो मैं समझता हूं कि इससे हमारा काम बहुत कुछ हल हो सकता है और गल्ले की कमी को पूरा करने में भी बड़ी मदद मिलेगी।

इसके बाद मैं चन्द अल्फाज स्टेट एक्साइज और खासतौर पर प्राहिबिशन के मुताल्लिक कहना चाहता हूं। हमारे सूबे में बरसों से प्राहिबिशन चल रहा है, लेकिन जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, न आगे बढ़ता है न पीछे हटता है। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि जब हमें प्लानिंग करना है, हमें सेंटीमेंट्स से जरा हट कर इस तमाम स्कीम को फिर से देखना है, उसे रिवाइज करना है कि कहां तक प्राहिबिशन कामयाब हुआ और उसको कहां तक हम चलायें तो यह सूबे के लिये मुफीद होगा। अगर हम इस नतीजे पर पहुंचें कि इसके चलाने से कुछ ज्यादा फायदा हमें नहीं मालूम होता तो फिर बेहतर है कि जो रुपया हम उस पर खर्च करते हैं वह किसी दूसरे फायदेमंद काम में लगायें। मैं प्राहिबिशन के सपोर्टर्स में से हूं, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि प्राहिबिशन जिस तरीके से चल रहा है उससे इस सूबे के लोगों के इखलाक पर, जुर्मों की कमी पर कोई असर नहीं पड़ा। इसलिये इसको जरूरत है कि उस पर खासतौर से तवज्जह दी जाय।

यह सही है कि हमारे सूबे में हर तरफ शिकायत है कि हमारे मारल वैल्यूज, हमारी डिसिप्लिन, हमारी एफिशियेन्सी गिरती चली जा रही है और उसकी जगह पर करप्शन बढ़ता जा रहा है। बाज लोग कहते हैं कि वेस्टेज होता है और वेस्टेज होता भी है। तो मैं अर्ज करूंगा कि गवर्नमेन्ट को खासतौर पर इस मामले में अपना दिल मजबूत करना चाहिये और दिल मजबूत करने के साथ-साथ उसे इसको विगरसली एन्फोर्स करने की कोशिश करनी चाहिये। मैं जानता हूं कि उनके रास्ते में मुश्किलात होंगी और उनके ऊपर बहुत से दबाव डाले जायेंगे और उनके पीछे हम जैसे बेउसूल आदमी उनको सही रास्ते से हटाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अब वह वक्त आ गया है कि जब उन्हें अपनी जगह पर पहाड़ की तरह मजबूत हो जाना चाहिये। जहां तक मारल वैल्यूज, एफिशेन्सी और डिसिप्लिन का ताल्लुक है उसमें कोई भी रियायत नहीं होनी चाहिये और ऐडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत हाथ से चलाने की कोशिश करनी चाहिये।

अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन को वैसे ही चलायेंगे तो भी शिकायत आयेंगी और अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती के साथ चलायेंगे तब भी शिकायत आयेंगी, लेकिन एक ऐसे स्टेज पर जबकि सब तरफ से यहां पर यह मांग होती है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन को ठीक तरह से चलाया जाय, तो हमें सख्ती के साथ ऐडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की कोशिश करनी चाहिये जिससे मजबूती के साथ डिसिप्लिन को एन्फोर्स किया जा सके। इस तरह हमारे यहां जो यह करप्शन की कहानी है उसमें बहुत हद तक कमी आ जायगी।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय पूंजीवादी विकास का रास्ता पकड़ा है। उसी का चित्र वित्त मंत्री जी के पिछले भाषणों से इस सदन में बराबर मिलता रहा है। यह भाषण भी उसी का परिचायक है। किसी भी दशा में पूंजीवादी राष्ट्रीय विकास का अपना विशेष चरित्र होता है। मुट्ठी भर आदमियोंकी आमदनी बढ़ती जाती है, उनके ऊपर टैक्स का बोझ कम होता जाता है और उनकी ऐशोइशरत में वृद्धि होती है और विकास और निर्माण के कार्य का अधिकांश भाग उनके पाकेट में जाता है। इस प्रकार वैषम्य बढ़ता है। दूसरी ओर जनता का बहुत बड़ा हिस्सा इससे वंचित रह जाता है। उस पर टैक्स का बोझ बढ़ता है। उसकी हालत दिनोदिन गिरती जाती है और वह विकास के नाम पर विनाश का शिकार होती है। यह संसार के पूंजीवादी विकास पथ पर अग्रसर होने वाले देशों का इतिहास हमें बतलाता है। अर्ध विकसित और अविकसित, नव स्वतंत्र और

अर्ध स्वतंत्र, जो एशिया और अफ्रीका के देश हैं उनका भी यह रास्ता उसी प्रकार का सिद्ध हुआ है। इसमें सन्देह नहीं है कि यह बजट भाषण छोटा है। ३८ और ३२ पृष्ठ के भाषण सुनने के बाद यह १८ पृष्ठ का भाषण इस साल हमको सुनने को मिला है। यह इकानामी है। इसके लिये वित्त मंत्री जी को बधाई है।

बैड बजटिंग के बारे में यह एक नमूना है। ५६–५७ में करीब ९.५५ करोड़ रुपये के घाटे की आशा थी, लेकिन बाद में उसमें १२ लाख की बचत हो गई। सन् ५७–५८ में ११.६७ करोड़ घाटे की उम्मीद थी, लेकिन बाद में आमदनी बढ़ी और खर्चा कम हुआ। इस तरह से इसमें ४.०७ करोड़ रुपये के घाटे की आशा रह गई है। कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर एक साल के बाद हम लोग फिर अगर इस सदन में बैठे—मुझे आशा है कि हम बैठेंगे—तो माननीय वित्त मंत्री जी फिर जब बजट भाषण पढ़ेंगे तो यह सुनने को मिलेगा कि इस साल जो ४ करोड़ रुपये के घाटे की बात कही गई है वह बचत में परिणत हो गई।

इसी के साथ विकास के कार्यों पर जो खर्चा इस सदन में मंजूर किया गया उसमें भी बचत हुई। सन् १९५६–५७ में, शिक्षा पर, जनस्वास्थ्य पर, पशु-चिकित्सा आदि कल्याणकारी कामों पर कुल मिलाकर ४.८८ करोड़ की बचत हुई। अगर ५७–५८ के बजट को देखा जाय तो उसमें भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि १.५७ करोड़ रुपये की बचत की आशा है। अगर इसमें पूंजी व्यय की कमी ४.७५ करोड़ और ३.१५ करोड़ क्रमशः ५६–५७ और ५७–५८ को जोड़ा जाय तो कुल मिलाकर १४.३५ लाख की टोटल बचत हो जाती है। यह बैड बजटिंग का बहुत बड़ा ज्वलन्त उदाहरण है। इसके साथ-साथ इस बात का भी प्रमाण है कि विकास की योजनाओं पर जहां पर अधिक रुपया खर्च होने की जरूरत है, जिसके नाम पर टैक्स बढ़ाया गया है, जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा है, उसका रुपया भी बचता चला जाता है। यह अकर्मण्यता के कारण बचत हुई है।

यह बजट दूसरी पंचवर्षीय योजना के तीसरे साल पेश हुआ है। यह बजट भाषण और उसकी बातें दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को पूरा नहीं करतीं। उसके दो मुख्य उद्देश्य थे जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि कृषि पदार्थों और खाद्यान्नों में हमारा देश और प्रदेश आत्मनिर्भर हो जाय। उसी प्रकार इस योजना के दो मुख्य लक्ष्य हैं एक औद्योगीकरण और दूसरा एम्प्लायमेन्ट पोटेंशियलिटीज को बढ़ाना। लेकिन मेरा अपना विचार है कि पिछले दो सालों में जिस गति से इन लक्ष्यों की ओर बढ़ा जा रहा है वह निराशाजनक है। यह बजट उन आशाओं को पूरा नहीं करता।

आप औद्योगीकरण को देखिये। साढ़े १८ करोड़ के लगभग रकम इस चालू पंचवर्षीय योजना में कल कारखानों के लिये रखी गई है। इसमें से ४ करोड़ ७७ लाख रुपया बड़े स्केल के कल कारखानों के लिये है। इसमें से २ करोड़ रुपया चुर्क सीमेंट फैक्टरी के विस्तार के लिये है और १३ लाख रुपया प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी के विस्तार के लिये रखा गया है। तो कुल मिला कर २ करोड़ ६४ लाख रुपया ही बचता है जो कि नये कल कारखानों के लिये इस्तेमाल हो सकता है। पिछले दो सालों में एक भी पब्लिक सेक्टर में कल कारखाना हमारे प्रदेश में नहीं खुला। यह इस बात का प्रमाण है कि औद्योगीकरण की ओर और वह भी पब्लिक सेक्टर में जो उसका मुख्य उद्देश्य घोषित किया गया है, उस ओर सरकार इस पंचवर्षीय योजना में नहीं बढ़ रही है। अगर देखा जाय तो केवल २६,००० रुपया प्रति दिन यह सरकार बड़े स्केल के कल कारखानों के लिये खर्च कर रही है। यह उपहास है।

अब प्राइवेट सेक्टर को लीजिये। प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दिया गया है। साढ़े ३ करोड़ रुपया हमारे प्रदेश के अनेक पूंजीपतियों को दिया गया जिसमें अकेले शांती जैन को डेढ़ करोड़ रुपया सोडा ऐश फैक्टरी के लिये दिया गया। अभी अल्मूनियम कारखाना बिरला ग्रुप को दे दिया गया और पता नहीं कि अभी कौन-कौन रहस्य सरकार के पेट में भरे पड़े हैं जिनका उद्घाटन कभी न कभी तो होगा ही। तो पब्लिक सेक्टर को पीछे करना उद्देश्य को पीछे करना होता

[श्री झारखंडे राय]

हैं और प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाना पूंजी के एकाधिकार को बढ़ाना है। प्राइवेट सेक्टर भी अगर हम देखें तो एक संकट की बेला से गुजर रहा है। कपड़े की मिलें, चीनी की मिलें, तेल की मिलें, हमारे प्रदेश के अनेक भागों में बंद पड़ी हैं जिनकी चर्चा यहां सदन के अनेक सदस्यों ने की है और मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। शुगर इंडस्ट्री की अगर हम बात देखें तो हमारे देश की १५८ शुगर फैक्टरीज में से १२१ के मुनाफे की जांच जब की गई जिनका कंट्रोल ११० कंपनियों द्वारा होता है तो पता लगा कि १९३७ में उनका मुनाफा ९.६७ करोड़ रुपया था। १९५४ में वह बढ़ कर ७५.६६ करोड़ रुपया हो गया और इन फैक्टरीज में से ७१ हमारे प्रान्त में हैं। हम बड़ी आसानी से इस बात का अनुमान कर सकते हैं कि हमारे प्रदेश के इन मिल मालिकों ने कितना मुनाफा कमाया होगा। और यह मुनाफा उनका जो सेस ड्यूटी और इनवेंटरीज पर जो उनका खर्च का एस्टीमेट था वह सब छोड़ कर हुआ। इतने मुनाफे के बाद भी शुगर फैक्टरीज का जो तथा कथित क्राइसिस है हमारे प्रदेश में वह दूर नहीं हुआ। खुद सरकार की पूंजीवादी नीति के कारण किसानों का २० करोड़ से ज्यादा रुपया पूंजीपतियों की जेब में चला गया। केवल इस नीति के कारण गन्ने का दाम १ रुपये १२ आने के बजाय १ रुपया ५ आने कर दिया गया और चीनी का भाव यथावत्।

सरकार इस बात की शिकायत करती है और बराबर यहां भी कहा गया कि केन्द्र हमारे प्रदेश के प्रति उदासीन है। केन्द्र हमारे देश के दूसरे अनडेवलप्ड और अन्डर डेवेलप्ड प्रान्तों, जैसे आसाम और केरल के प्रति भी उदासीन है। लेकिन यू० पी० की सरकार अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के बहाने के रूप में इस बात को इस्तेमाल करती है जबकि उसकी स्वयं की नीति पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने की नहीं है और न प्राइवेट सेक्टर को नियंत्रित करने की है।

१९५५ में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय सूबा कमेटी की एक सब-कमेटी ने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की थी कि दूसरी योजना में प्रान्तीय सरकार २१ लाख आदमियों को काम दिलाने जा रही है। मैं मंत्री जी से इस बात की सफाई चाहूंगा कि १९५६-५७ के उनके बजट भाषण में क्यों यह कहा गया कि १० लाख आदमियों को काम दिलावेंगे। यह कौन सा माया जाल है, मैं जानना चाहूंगा। सारे भारत में और हमारे प्रदेश में खासतौर से बेकारी बढ़ी है और बढ़ रही है। जितने लोग बेकार हैं वे सभी एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में नाम नहीं लिखा पाते हैं और बहुत से उसका नाम भी नहीं जानते हैं। जो भी आंकड़े हमको मिले हैं उनके अनुसार मार्च, १९५१ में ३.३९ लाख आदमी बेकार थे, १९५३ में ५.२२ लाख बेकार थे और १९५५ में ६.९२ लाख बेकार हो गये। उसके बाद भी पिछले दो ढाई वर्षों में बेकारी बढ़ी ही है। मैं आशा करता था कि माननीय वित्त मंत्री हमको बतायेंगे कि कितने लोगों को वह काम दिला सकें हैं। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि हमारे प्रदेश में और जगहों से बेकारी अधिक बढ़ी है। सन् १९५३ में ४५,८२९ आदमियों को काम दिलाया गया, जो जिन्होंने नाम लिखाया उसका २६ फीसदी है। सन् १९५४ में ३५,४८१ को काम मिला जो २२% है, और १९५५ में २९,४६७ को काम मिला जो कि कुल का १८ फीसदी है। इस तरह से क्रमशः जिनको काम मिला है उनकी संख्या घटती गई है। बेकारी अधिक होने से परसेंटेज गिरता जा रहा है। मुझे आशा थी कि हमारे राष्ट्र की इस भयावह समस्या के लिये कुछ न कुछ मंत्री जी कहेंगे, लेकिन पूरा बजट भाषण इस विषय में चुप है।

माननीय वित्त मंत्री जी तथा कुछ भाइयों ने भी बड़ा संतोष प्रकट किया है कि नया टैक्स कोई नहीं लगाया है। लेकिन यह एक नकारात्मक संतोष है। यह जनता को कुछ राहत का परिचायक नहीं है। साथ ही, मुझे एक बात का डर है कि मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि रुपये की जरूरत अवश्य है, उससे बचा नहीं जा सकता है, इसलिये मुझे सन्देह है कि कहीं यह बात नया टैक्स लगाने की सूचना न देती हो। मैं इसकी सफाई मंत्री जी से चाहूंगा।

ए०आई०सी०सी० की एक सब-कमेटी ने श्री गुलजारी लाल नन्दा के नेतृत्व में टैक्सों के बारे में प्लानिंग कमीशन को जो सिफारिश भेजी थी उसमें उन्होंने टैक्सों के बारे में एक नीति निर्धारित की थी जो मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं :—

"Tax-burden should fall primarily on those whose capacity to pay is greater and whose income increases as a result of the programmes of development which are undertaken."

इस सिफारिश पर सरकार ने अमल नहीं किया। आज टैक्स उन पर लगते हैं जिनकी आय कम है या जो विकास योजनाओं से कम लाभ उठा पाते हैं। टैक्स उन पर कम लगते हैं जिनकी आय अधिक है और जो विकास योजनाओं से अधिक लाभ उठाते हैं। इसका सरकार के पास क्या उत्तर है ?

पिछले १४ साल से सरकारी कर्मचारी, निम्नवेतन वाले अथवा मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की मांग है कि उनका मंहगाई भत्ता बढ़ाकर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर किया जाय। इस असमानता को दूर किया जाय। इसके बारे में वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में लिप सिम्पेथी अवश्य दिखाई है, लेकिन ठोस रूप में कोई कदम नहीं उठाया है। ए० आई० टी० यू० सी०, आई० एन० टी० यू० सी०, यू० टी० यू० सी०, एच० एम० एस० आदि सभी केन्द्रीय राष्ट्रीय संगठनों की यूनियनों की मांग रही है कि मजदूरों की और कर्मचारियों की २५ फीसदी वेतनवृद्धि होनी चाहिये। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया है; फिर इन्टेरिम बढ़ती की तो चर्चा करना ही एक तरह से पाप जैसा होगा। हम देखते हैं कि रहन-सहन का खर्चा बढ़ता जाता है। अगर जीवन के खर्चे कम होते तो दूसरी बात थी, लेकिन जब खर्च बढ़ता है तो जरूरी हो जाता है कि इन कम वेतन वालों का मंहगाई भत्ता भी बढ़ाया जावे और उनकी मांगें पूरी की जावें। आपकी आज्ञा से मैं कानपुर में श्रमिक उपभोक्ता के सूचनांक से बताना चाहता हूं कि रहन-सहन का खर्चा सन् १९५५ में जहां ३७१ था, वह सन् १९५६ में ४२४ और सन् १९५७ में नवम्बर तक औसत ४४५ हो गया। अपने ३ लाख निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये सरकार ने इस बजट में राहत के लिये कुछ भी पेश नहीं किया है। बहुत सी कमेटियां, जैसे निम्बकर कमेटी, खेर कमेटी, यू०पी० पे कमेटी और एक और कमेटी सरकार ने वेतनों के बारे में बैठाई थी। पत्रकारों के लिये भी पे कमीशन नियुक्त हुआ। इन सबकी सिफारिशें अधिकांश में कोल्ड स्टोरेज में डाल दी गईं। पत्रकारों के बारे में सिफारिशें इस झमेले में पड़ी हुई हैं कि मालूम नहीं कि उनमें से कुछ निकलेगा या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि पिछली सिफारिशों के अनुरूप उनका भी अन्त हो।

वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बात को बड़े गर्व से घोषित किया था कि कृषि के बारे में हमारा प्रदेश, एक मानी में समस्त देश, खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर हो गया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि वे अपने गलत दावे को वापिस लें। झूंठ तो मैं नहीं कहता, उनका यह जो असत्य भाषण है, जिससे इधर के बैठने वालों को भी भ्रम हुआ है, उसकी असत्यता और गलती को स्वीकार करें और अपने उस वक्तव्य को वापस लें। अपनी गलती और भूल को महात्मा गांधी ने भी मानना बताया है। उस भाषण में कई बार इस बात का दावा किया गया है कि हमारा देश खाद्य समस्या में आत्मनिर्भर हो गया है, बड़ी सफलता मिली है। लेकिन उसके बाद जो वर्ष गुजरे हैं, उनसे यह सदन परिचित है। इस वर्ष के भाषण में इसका भी दावा किया गया कि आशा से अधिक सफलता मिली है। मैं कहता हूं कि उनका यह दावा भी गलत और झूठ है।

श्री उपाध्यक्ष—आप 'झूठ' शब्द का बार-बार प्रयोग कर रहे हैं।

श्री झारखंडे राय—मैं उसको वापस लेता हूं। असत्य समझ लीजिये, निराधार समझ लीजिये, भ्रामक समझ लीजिये, फर्जी समझ लीजिये। नीचे के कर्मचारियों द्वारा जो भ्रामक और फर्जी आंकड़े आते हैं, उन पर सरकार विश्वास करती है और मुझे तो शक होता है कि सरकार भी कुछ इस तरह के आंकड़े भेजने का इशारा करती है, जिनके द्वारा यह चीजें पैदा होती हैं। इस तरह की गलत चीजें कह कर और गलत बयानी करके सदन को गुमराह किया जाता है, जिससे ग़लत नतीजा निकलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह भूल, वह ग़लती खुल जाती है।

हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बात को भी माना है कि इस साल खाद्य पदार्थों की पैदावार बढ़ी है। माननीय वित्त मंत्री जी इस बात को बतायें कि सरकार के नये प्रयासों के फलस्वरूप कितनी, और प्राकृतिक अनुकूलताओं से कितनी वृद्धि हुई है। जब तक इन दोनों बातों को हमारे सामने नहीं रखा जायगा, तब तक आंकड़ों का जाल हमेशा हमें अपने में उलझा कर रखेगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि सन् ५६–५७ और ५७–५८ में एक ओर तो आप अन्न के उत्पादन की बढ़ती की बात कहते हैं और दूसरी ओर उन्हीं वर्षों के बारे में यह भी कहते हैं कि जहां तक किसानों का सम्बन्ध है, नेचर द्वारा आने वाली कठिनाइयों ने किसानों को सताया है। इन्हीं आपदाओं के कारण पूर्व में भुखमरी फैली। इससे भी सब लोग परिचित हैं, लेकिन इन्हीं वर्षों में सरकार की रिपोर्ट में खाद्यान्न बढ़ा है। यह एक ऐसा मायाजाल है जिसकी सफाई वित्त मंत्री जी को करनी चाहिये, नहीं तो एक दिन इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा।

भूमि सुधारों के बारे में हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल जी ने भी प्रान्तीय सरकारों के बारे में कहा है कि उनकी भूमिसुधार नीति बड़ी धीमी गति से चल रही है। एग्रीकल्चर कमीशन जो चीन गया था उसने यह राय दी है कि हमें कोआपरेटिव फार्मिंग की ओर तेजी से बढ़ना होगा। इसके अतिरिक्त सिंचाई रेट के बारे में श्री अजित प्रसाद जैन ने २६–११–५७ को पार्लियामेंट में कबूल किया है :—

"The country was not getting the benefit of the various irrigation schemes already implemented because of the high water rates and that there were serious shortcomings even in the agricultural policy of the Government."

तो मैं चाहूंगा और आपके द्वारा इस सदन से अपील करूंगा कि क्रान्तिकारी भूमि सुधार के मामले में जो माननीय माल मंत्री का प्रतिगामी प्रतिरोध है उसको चकनाचूर कर दिया जाय वरना सरकार को इसका बुरा फल भुगतना पड़ेगा। अगर हदबन्दी की बात की जाती है तो माननीय माल मंत्री जी उसके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं और माननीय माल मंत्री द्वारा उसका सख्त विरोध किया जाता है। अगर भूमि बटवारे की बात की जाती है तो वे तमाम आंकड़े के अम्बार लाकर इस सदन में पेश कर देते हैं और कहते हैं कि भूमि की समस्या तो हल हो चुकी है। श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं केवल बस्ती जिले के तीन भूतपूर्व ताल्लुकेदारों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बस्ती जिले में बांसी राज जो पहले कहा जाता था उसके पास आज भी १६,००० बीघे जमीन है, क्या सरकार इस जमीन की सीलिंग नहीं कर सकती है? ढैकहरी के तीन चौधरियों के पास २२,००० बीघे जमींन है, क्या इसकी सीलिंग नहीं हो सकती है? शोहरतगढ़ राज्य के पास ७,००० बीघे जमीन है, क्या सरकार उसे नहीं ले सकती है? मैं यह नहीं कहता हूं कि केवल सीलिंग कर देने से और खेतिहर मजदूरों और गरीब किसानों में, जिनमें हरिजन ही सब से ज्यादा हैं, अतिरिक्त भूमि के वितरण से बेकारी की समस्या का और भूमि समस्या का समाधान हो जायगा, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि बेकारी की समस्या और क्रान्तिकारी भूमि समस्या के हल का यह एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम होगा। जहां तक नैनीताल तराई में पर्सनल

फार्म्स हैं, वह कहां का समाजवाद है? उग्र डेमोक्रेटिक रिफार्म्स में भी इस तरह की चीजें देखने में नहीं आतीं।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मुझे आशा है कि आप थोड़ा सा टाइम मुझे और दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—५ मिनट में और दे सकता हूं। सवा तीन बजे खतम कर दें।

श्री झारखंडे राय—श्रीमन्, बलिया में सेंट्रल मंत्रिमंडल के खाद्य मंत्री श्री जैन जी गये थे तो उन्होंने इस बात का बड़ा रोना रोया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू तक इस बात को कहते हैं कि कृषि विकास के लिये जो योजना है, उसमें बीज फार्म्स, बीज गोदाम, हरी खाद या और दूसरी खादों की उपेक्षा की जाती है। उनका मतलब सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से ही था, कि इस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिये।

जहां तक उन्नत बीज की बात कही जाती है, श्रीमन्, कृषि विकास के नाम पर जो बीज दिये जाते हैं, उस सम्बन्ध में पूर्वी अंचल में अनेक जगह वितरित "बलिया बार्ली" की एक बड़ी दर्द भरी कहानी है। इस सम्बन्ध में मैं केवल एक उदाहरण आजमगढ़ जिले का देता हूं। वहां दोहरीघाट के एक विकास केन्द्र पर १५० मन जौ के उन्नत बीज बांटे गये, जिनमें से अधिकांश बीज सूख गये। इससे ३६,००० रु० की हानि हुई और आसपास के जिलों में जो बीज बांटे गये थे उनकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन वहां भी ऐसी ही हानि हुई होगी। मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसे आंकड़े इकट्ठा करे और उस तरफ छूट या राहत दे।

खाद्य समस्या कितनी प्रमुख है, यह इसी से प्रतीत होता है कि हमारे देश में जितना खाद्यान्न मंगाया जाता है उसके लिये हमारे देश को केवल किराये के रूप में ७० करोड़ रुपया देना पड़ता है। पहले हमें आशा थी कि केवल ८० लाख टन खाद्यान्न मंगाना पड़ेगा, लेकिन सबसे बाद का जो आंकड़ा है, उससे मालूम होता है कि १ करोड़ २० लाख टन खाद्यान्न बाहर से मंगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमारे यहां की भोजन समस्या हल हो पायेगी। दूसरे प्लान में ३० प्रतिशत खाद्यान्न बढ़ाने का टारगेट रखा गया था, लेकिन मेहता कमेटी ने चेतावनी दी है कि प्रान्तीय सरकारों का जितना टारगेट है उसके ६६ प्रतिशत से अधिक वे अपने यहां खाद्यान्न नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस गम्भीर स्थिति में मैं चाहूंगा कि भूमि-सुधार का जो क्रान्तिकारी कदम है उधर भी हम बढ़ें, वरना प्रदेश की बहुत बड़ी हानि होगी।

दुर्भिक्ष की बात भी कही गई। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि हमारे सूबे के पड़ोसी सूबे बिहार में जहां १७ जिलों में २ करोड़ १२ लाख के करीब लोग खाद्यान्न की कमी से पीड़ित थे, वहां उनके लिये ९,८९६ सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गईं जब कि हमारे यहां उसके मुकाबले में १४ जिलों में, जहां तक मुझे याद है, कुल मिला कर २,१०० से अधिक दुकानें नहीं खुलीं। यह सरकार की हाफ–हार्टेड या आधे दिल की कोशिश है उस अंचल के लिये जहां कि भुखमरी कई सालों से व्याप्त है।

चकबन्दी के विषय में भी मैं केवल इतना ही कहूंगा कि, श्रीमन्, केवल आप के ही जिले में चकबन्दी से जो झगड़े खड़े हुये हैं उनमें १,५०० किसानों पर दफा १०७ के केस चल रहे हैं और आप को मालूम होगा कि ४ लाख के करीब किसानों की तरफ से अधिकारियों को घूस दिया गया और १२ लाख रुपये के करीब मुकदमों में खर्च हो चुका है और दफा १२४-ए तक के केस पुलिस ने लोगों पर चलाये हैं। हम चाहते हैं कि इस बात पर माननीय माल मंत्री जी और सरकार की हठवादिता समाप्त हो और इस बात पर विचार होना चाहिये कि चकबन्दी को समाप्त करके कलेक्टिव और कोआपरेटिव फार्मिंग का एक्सपेरीमेंट किया जाय। क्या यह जरूरी है कि एक बार जो चीज दिमाग में आ गई, एक बार गलत साबित होने पर भी उसी पर स्टिक किया जाय?

[श्री झारखंडे राय]

समाजवाद की भी चर्चा सदन में काफी हो चुकी है। मैं इस सम्बन्ध में केवल एक बात बताऊंगा और अपने इस महान् देश की तुलना चीन से करना चाहता हूं जो हमारे देश से २ साल बाद आजाद हुआ है। वहां की जो तस्वीर हमें आज दिखाई देती है उससे पता चलता है कि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में ३ गुने से १५ गुने तक उत्पादन बढ़ा है। वहां की आय का ७० प्रतिशत स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज से, १५ प्रतिशत प्राइवेट इंडस्ट्रीज से और १५ प्रतिशत टैक्स आदि अन्य तरीकों से आता है जब कि अगर हम इस सूबे को देखें तो यहां .१३४ प्रतिशत स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज से आता है और ९९.८६ प्रतिशत अन्य तरीकों से आता है। यदि हम इस रफ्तार से समाजवाद की ओर बढ़ें तो मेरा विश्वास है कि शायद ४,००० वर्ष में यहां समाजवाद हो जायगा। यह जो गति है बहुत तेज है! अब लाल बत्ती जल गई, अन्त में मैं. . .

श्री उपाध्यक्ष---यह तो आपका प्यारा रंग है।

श्री झारखंडे राय---जहां तक नेशनल आय का सम्बन्ध है, मैं इतना ही कहूंगा कि यहां की देहाती जनता का मापदंड नीचे गिरा है। जबकि देश के दूसरे देहाती क्षेत्रों में उसका औसत २२० रुपया है तो हमारे यहां २०१ रुपया वार्षिक औसत है, यानी १७ रुपया मासिक या ९ आना रोजाना। इस गति से हम बढ़ रहे हैं।

अन्त में मैं यह और कहूंगा कि हमारे समाज का जो सब से दलित और पीड़ित हरिजन वर्ग है उसकी आज ३ मुख्य समस्यायें हैं---जमीन, मकान और पानी। इनका समाधान होना चाहिये। मैं चाहूंगा कि यह सरकार कुछ तो ऐसा काम करे जिसके कारण इन कुर्सियों से उखड़ने के पहले उसे इतना तो सन्तोष रहे कि हमने एक आध तो अच्छा और पूरा काम किया है। कम से कम हर गांव में हरिजनों के लिये एक कुआं तो हो, यह बात-चीत होनी चाहिये। एन० ई० एस० ब्लाक्स के द्वारा जो होता है कि आधा सरकार दे और आधा गांव के लोग दें, इससे काम नहीं चल सकता। सरकार देखे और जांच कराये कि किन गांवों में हरिजनों के लिये कुएं नहीं हैं और जहां नहीं हैं उन गांव में हरिजनों के लिये अपनी ओर से पक्के कुएं बनवाये।

मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे कुछ समय बढ़ा कर दिया और सरकार से इस बात का अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो पूंजीवादी राष्ट्रीय विकास का रास्ता पकड़ा है उसको स्पष्ट कहना चाहिए। समाजवादी नारे में उस विकास के रास्ते को ढकने की कोशिश करना बेकार है। आज संसार में विशेषकर एशिया अफ्रीका के पिछड़े हुए देशों में समाजवाद का सच्चा मार्ग ही वह मार्ग है जिस पर चल कर करोड़ों मानव सही माने में विकास की ओर बढ़ सकते हैं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---बहुत से माननीय सदस्यों की इच्छा है, जैसे आप लोग खड़े हैं, तो क्या यह सम्भव है कि १५ मिनट के बजाय १० मिनट कर दिया जाय?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---दस मिनट कर दिया जाय।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि सदन की राय हो तो साधारण तौर पर दस मिनट और जैसा माननीय अध्यक्ष, या उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता अपने अधिकार का प्रयोग करते रहे हैं, जिसको उचित समझें बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष---तो यह ठीक ही है। दस मिनट का समय रहेगा और चेयर को विशेषाधिकार रहेगा कि विशेष अवस्थाओं में पांच या दस मिनट का समय और बढ़ा दे।

श्री ब्रजभूषण शरण (जिला देहरादून)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के सामान्य विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैंने बजट लिटरेचर को और माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े गौर से पढ़ा और सुना।

सरकार, इस पंचवर्षीय योजना के काल में, जो धन की इतनी बड़ी आवश्यकता है और बड़ी-बड़ी विकास की योजनाएं चल रही हैं, कोई नया कर न लगाने के कारण हमारे धन्यवाद की हकदार जरूर हो जाती है। मगर जब अनाज पर १९५६-५७ में टैक्स लगाया था तो सरकार ने नौ करोड़ कुछ लाख के घाटे का बजट पेश किया था और उसमें यह जाहिर किया था कि बड़ी-बड़ी विकास योजनाओं के लिए चूंकि रुपये की जरूरत है और घाटे का बजट है इसलिए इसको पूरा करने के लिये अनाज पर टैक्स लगाना जरूरी है। सरकारी आंकड़े थे, बेचारी जनता क्या करती? मानना ही पड़ता है। लिहाजा वह टैक्स लग गया। जैसा कि माननीय सदस्यों के भाषणों से आपको विदित हुआ होगा वह नौ करोड़ कुछ लाख का घाटा कुछ लाख के लाभ में परिणत हो गया। तो बड़ी-बड़ी विकास योजनाएं जिनके लिए अनाज पर टैक्स लगाया गया था, वह हाथ में न ली जा सकीं, कम से कम कुछ तो न ली जा सकीं, तभी कुछ लाख का फायदा हुआ। तो मैं समझता हूं कि इसी तरीके से १९५७-५८ के वर्ष में देखें तो घाटे का बजट बताया गया था वह वित्त मंत्री महोदय के भाषण से सिर्फ चार करोड़ का ही रह गया है। अभी तो डेढ़ दो महीने बाकी हैं। कौन जानता है कि इसमें यमुना स्कीम जैसी योजनाओं की कहीं अकाल मृत्यु हो जाय? तो मैं आपके द्वारा सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि जो अनाज पर टैक्स लगा रखा है जिसकी वजह से लगाया था, वह टैक्स अब जरूर हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी योजनाएं खुद पूरी नहीं हैं, फिर टैक्स लगा कर रुपया इकट्ठा करने का फायदा क्या?

माननीय तिवारी जी ने अपने भाषण में यह बात कही कि सरकार को चुर्क सीमेंट फ़ैक्ट्री का लेखा-जोखा बजट में रखने से क्या नुकसान होगा। मैंने भी इस बजट साहित्य को बड़े गौर से उल्टा पल्टा मगर उस सीमेंट फैक्टरी का कुछ पता इस तमाम बजट लिटरेचर में न लग पाया। बहुत देखने भालने के बाद यह नजर आया कि इस चुर्क सीमेंट फैक्ट्री से दो करोड़ रुपये का सीमेंट बिकेगा और एक और जगह यह नजर आया कि १ करोड़ ८९ लाख इस पर खर्च होगा। उस खर्च को अगर देखा जाय और उस आमदनी को देखा जाय जो कि सीमेंट से होने वाली है तो जरूर वित्त मंत्री के भाषण के मुताबिक एक थोड़े से मुनाफे की स्कीम नजर आती है। मगर उस खर्चे में कैपिटल आउटले जो है, जो वर्किंग कैपिटल है उस पर भी इंटरेस्ट नहीं लगाया है। अगर उस पर भी इंटरेस्ट लगा दिया जाय तो वह भी घाटे में तब्दील हो जायगा। इसलिये जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार की हर अंडरटेकिंग घाटे में जा रही है, ठीक ही है। इर्रीगेशन की स्कीम्स पर कैपिटल आउटले पर इंटरेस्ट लगा कर देखा जाय तो वह भी माइनस में हो जायगा। कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें कोई फायदा हो रहा हो।

इन आंकड़ों के जाल में उलझकर हमें खुद समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों देश की, प्रदेश की चौमुखी उन्नति हो रही है और पर कैपिटा इनकम घट रही है। एक आर्ग्यूमेंट यह दिया गया कि पर कैपिटा इनकम इसलिए घट रही है कि आबादी बढ़ रही है। इसी उत्तर प्रदेश की फिगर्स में आप यह देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम गांवों की उतनी नहीं घटी जितनी कि शहर की घटी है। तो क्या गांवों में पैदावार बन्द हो गई है? मैं समझता हूं कि यह सब इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जिनकी बाबत कुछ न कुछ तो कहा ही जा सकता है। असलियत यह है कि हम बिल्कुल तरक्की के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। यह दूसरी बात है कि कुछ चीजों में हमने जरूर तरक्की की है और तरक्की की तरफ नजर भी रखनी चाहिए। मगर यह कोई तरीका नहीं है कि दूसरों के सुझाव को न मानें, किसी तरफ तवज्जह न दें, जिस लाइन पर चल पड़े हैं उसी पर चले जा रहे हैं।

मैं कुछ शब्द खर्चों की बाबत कहूंगा कि क्यों सरकारी अंडरटेकिंग में नुकसान रहता है। उसका कारण यह है कि सरकार जब कभी कोई योजना

[श्री ब्रजभूषण शरण]

बनाती है तो सब से पहले स्टाफ भरती करना शुरू कर देती है। स्टाफ जहां भरती हुआ कि उनकी तनख्वाह तो बंटनी शुरू हो गई काम चाहे हो या न हो। तो जब स्टाफ बढ़ाते जायेंगे और काम कम होगा तो मजबूरी है, घाटा तो रहेगा ही।

(व्यवधान)

काम पहले से हो और स्टाफ बाद में, ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन काम पहले निश्चित तो हो जाय। ऐसा तो न हो कि स्टाफ भरती कर लिया, बड़े-बड़े ट्रैक्टर्स सब देहरादून की घाटी में भेज दिए और बाद में पता लगा कि अभी तो तफतीश करनी है।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था जैसा माननीय विरोधी दल के नेता के भाषण से पता लगा और माननीय झारखंडे राय के भाषण से पता लगा कि अल्यूमीनियम प्लांट बिरला को दे दिया गया है और माननीय विरोधी दल के नेता ने यह भी बताया कि अल्यूमीनियम प्लांट के लिए बिजली कास्ट प्राइस से भी कम पर दी गई है। मैं आपके द्वारा सरकार की तवज्जह इस बात की तरफ दिलाना चाहूंगा कि जब अल्यूमीनियम मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें बिजली एक कच्चा माल है, रा मैटीरियल है, उसके प्रोडक्शन में बिजली का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। वही आपने कास्ट प्राइस से भी कम पर दे दिया तो आपने मुनाफे का चेक तो पहले ही उन्हें काट दिया। अगर यह बात सही है तो इसकी छानबीन होनी चाहिये।

एक मांग चारों तरफ से की जाती है कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग-अलग किया जाय। उसके लिए एक दलील पेश की जाती है कि अगर दोनों को अलग-अलग कर दिया जावे तो खर्चा बहुत बढ़ जायगा। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि खर्चा कैसे बढ़ जायगा। आखिर जुडिशियरी का काम जो मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं उन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही है क्या? अगर तनख्वाह दी जा रही है तो फिर खर्चा कैसे बढ़ जायगा? अगर एक आई० सी० एस० जज हो सकता है, श्रीमन्, दो मिनट और मुझे मिल जायं...

श्री उपाध्यक्ष—दो मिनट हैं अभी आपके।

श्री ब्रजभूषण शरण—तो मैं अर्ज कर रहा था कि अगर एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग करना है तो उसमें दिक्कत क्या है। जितनी तनख्वाह अब देनी पड़ती है उतनी ही तब देनी पड़ेगी। आज जो ग्रेड मुंसिफ का है वही डिप्टी कलेक्टर्स का है। आज तक नहीं कर सके तो न सही, कल से मुंसिफ की भर्ती कीजिये और डिप्टी कलेक्टर्स की भर्ती कम करते जाइये। कुछ समय में यह कमी पूरी हो जायगी। इसमें कोई ज्यादा खर्चे की बात नहीं है।

पुलिस के मुताल्लिक मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। हर जिले में, बड़ा भारी प्रयोग किया गया है, कम्प्लेन्ट्स आफिसर मुकर्रर कर दिये गये हैं। आफिसर मुकर्रर करने से क्या होगा? हरिजन वेलफेयर आफिसर्स हैं, इंडस्ट्रियल आफिसर्स हैं, लेकिन यह भी तो गौर से देखना चाहिये कि इन आफिसरों ने किया क्या है। कम्प्लेंट्स आफिसरों ने हर जिले में क्या काम किये हैं? उतना ही काम किया है जो हर जिले में पहले से होता चला आ रहा था। हां, एक काम किया है। जब पुलिस की शिकायतें पहुंची हैं तब लीपापोती करने की कोशिश जरूर की गयी है। इसके अलावा और कोई काम कम्प्लेंट्स आफिसर्स ने नहीं किया।

श्रीमन्, एक सुझाव मैं आपके द्वारा देना चाहता हूं। वह यह है कि करों के अलावा आमदनी को बढ़ाने का कोई और तरीका भी सोचना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि जब भी कमी पड़ी तब आपने कोई न कोई टैक्स लगा दिया। और भी तरीके आमदनी बढ़ाने के हो सकते हैं। उन तरीकों को एक्सप्लोर करने की आज कोई जरूरत नहीं समझता। मैं बताता हूं कि ऐसा एक तरीका हमारे जिले में मौजूद है। हमारे जिले से बीस तीस लाख रुपये के स्लीपर्स निकाले जाते हैं और यमुना नहर से यमुनानगर पहुंच जाते हैं। वेस्टर्न यमुना

कैनाल में न बहाये जा कर यदि वे ईस्टर्न यमुना कैनाल से सहारनपुर में आने लगें तो बीस तीस लाख रुपये से एक तो सहारनपुर की भी तरक्की होगी, सरकार को भी कुछ सेल्स टैक्स में ज्यादा मिलेगा और कुछ इन्कमटैक्स में आपको ज्यादा हिस्सा मिलेगा। यह एक मामूली सी चीज है जिसकी तरफ कई बार इरीगेशन मिनिस्टर साहब का पहले भी ध्यान दिलाया गया है। लेकिन पता नहीं है कि सरकार इस तरफ क्यों नहीं तवज्जह देती। इससे करीब पन्द्रह बीस लाख की आमदनी सरकार को निश्चित रूप से होगी।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं जो अभी कांग्रेस पार्टी से माननीय सदस्य महोदय बोले हैं उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज जो इस देश और इस प्रान्त की हालत है उसकी सही तसवीर कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी दिखने लगी है। मैं यह समझता हूं कि अब आगे शायद उनको ऐसा भाषण देने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन जो आज उन्होंने अपना पहला भाषण दिया उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी वे ऐसे ही भाषण करते रहेंगे और सही बातें अपनी पार्टी के लोगों को बतायेंगे।

यह सही कहा गया है कि इस साल के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है, लेकिन कुछ ही दिन पहले एक टैक्स वृहत्-जोतकर के नाम से लगाया गया है। सरकार यह भी कहती है कि अधिक अन्न पैदा करो। देश की मांग है कि अन्न पैदा करो। अन्न की कमी है और उसको दूर करने के लिये सब लोग प्रयत्न करें। देश की उन्नति और द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसी पर निर्भर हैं। किन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसी के साथ खिलवाड़ भी किया जाता है। अभी हमारे मित्र झारखंडे राय जी ने बताया कि १ करोड़ २० लाख टन अन्न बाहर से लायेंगे। बाहर वालों को रुपया देने में आपको नहीं खलता, लेकिन यहां वाले जब अन्न पैदा करते हैं, बड़ी जोत से या छोटी जोत से, तब उसके लिये यह उपेक्षापूर्ण नीति बरती जाती है। वह इसी प्रान्त के हैं, अगर उनको कुछ रुपया बच जाय उनको कुछ थोड़ा सा मुनाफा हो जाय तो उसके लिये आप को परेशानी होती है। मैं हर पार्टी, जो भी इस देश में है, से अपील करता हूं कि इनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि बाहरवालों की बनिस्बत यहां के जो बाशिन्दे हैं उनको अगर कुछ थोड़ा-सा मुनाफा मिल जाता है तो वे इस देश के हैं और पैसा हमारा यहीं रहेगा।

जिस तरह से १ करोड़ २० लाख टन का मूल्य आप बाहर देने के लिये तैयार हैं, श्री झारखंडे राय उसको बुरा नहीं कहते, क्योंकि यह तो रूस में या कहीं बाहर जायगा। मैं आपके जरिये से यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमने इस प्रदेश के बजट को देखा है जब यह १५ करोड़ या ११ करोड़ से शुरू हुआ था और आज वह १११ करोड़ का है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रान्त की आमदनी बढ़ी, लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से बेतहाशा और बेबुनियाद का खर्चा हो रहा है उस ओर भी हमारी निगाह होनी चाहिये। आमदनी के साथ बढ़ती हुई फिजूलखर्ची को हरगिज़ बरदाश्त नहीं करना चाहिये।

मैं एक छोटी-सी मिसाल दूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् के चुनाव होने जा रहे हैं और जहां तक मैं समझता हूं उन पर २६ लाख रुपया खर्च होगा। यह सब जानते हैं कि यह चन्द दिनों के लिये बोर्ड्स बनाये जा रहे हैं, उसके बाद फिर आप दूसरा चुनाव करेंगे, तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्यों नहीं समझते हैं कि १० साल तक आपने चुनाव नहीं कराया, कोई स्कीम नहीं बनायी, कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया और आज २ साल के लिये चुनाव करायेंगे? क्या ६ महीने नहीं रुक सकते और यह नहीं समझते कि ६ महीने के अन्दर इस काम को पूरा किया जा सकता है? मैं तो कहूंगा, श्रीमन्, कि बोर्डों का बने रहना जरूरी नहीं है जिस गलत तरीके से कि वे १० साल से चल रहे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्र शाह---]

हैं। मेरी राय है कि इन बोर्डों को खत्म कीजिये और ६ महीने के अन्दर, बल्कि साल भर के अन्दर, आप बोर्ड का नया नक्शा जो कुछ आपको बनाना है, नियोजन कमेटियां रखनी हैं या डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनानी है, जो कुछ भी करना है उसको कर लीजिये और यह २६ लाख रुपया बचाइये। यह मेरी राय है।

एक सदस्य---आपकी पार्टी की क्या राय है ?

राजा वीरेन्द्रशाह---पार्टी की राय तो जब पार्टी के नेता बोलेंगे तो मालूम होगी, हम अपनी राय देने में स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र दल के हम मेम्बर हैं। तो गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करें कि जहां तक हो सके ऐसा खर्चा जिसे हम और जनता समझती है कि फिजूल है तो वह न किया जाय। जिस प्रकार से नियोजन कमेटी अपना फैसला देती है वह सब पर विदित है। वहां किसी को अपनी राय देने का अधिकार नहीं है, सारी स्कीमें ऊपर से बनकर जाती हैं।

आपने अल्प बचत योजना के जरिये रुपया इकट्ठा करने की बात कही। मेरा सुझाव है कि हम रुपया इकट्ठा करने के लिये तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि जितना रुपया हम इकट्ठा कर दें उतने रुपये की स्कीम हमारे यहां चालू कर दी जाय। जैसे कि हमने सवा लाख रुपया इकट्ठा किया तो फिर जनता जो चीज़ चाहे, ब्रिज वगैरह, उसको सरकार उस रुपये से बनवा दे। जब तक आदमियों को यह विश्वास रहता है कि सरकार जो रुपया लेती है वह रूस और अमरीका और बाहर भेजती है और कह देती है कि हमने अन्न में खर्च कर दिया तब तक वह सहयोग करने के लिये तैयार नहीं हैं। जब उनको यह विश्वास हो जायगा कि जो रुपया आप लेंगे वह उन पर ही खर्च होगा, तो आपकी योजना सफल हो सकती है। आपका वसूल करने का तरीका वही पुराना है, लेखपालों के जरिये से वसूली की जाती है। अगर मैं कुछ कहूंगा तो मंत्री जी कहेंगे कि शिकायत करने लगे लेकिन जिस प्रकार से ४-४ सौ रुपये बन्धे हुये हैं इस में आप हर किसी स्कीम के उद्देश्य को मार देते हैं। हम लोग कोई नहीं जाते हैं। हमारे जितने काम करने वाले आदमी हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि लेखपाल और हम लोग क्या साथ-साथ मांगेंगे ? हम सरकारी एजेन्सी नहीं हो सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार हम लोगों का कोआपरेशन चाहती है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि यहां तो मंत्री जी हमारा कोआपरेशन मांगते हैं लेकिन जिले के जो नेता हैं, जो कार्यकर्त्ता हैं वह केवल इस बात में रहते हैं कि विरोधी दल का अगर किसी काम में कुछ हिस्सा हो तो उसका उल्टा कहा जाय और अफसरों पर यह दबाव रहता है उन लोगों का कि जो विरोधी दल वाले कहते हैं उसका उल्टा होना चाहिये। इसका नतीजा यह होता है कि आजकल जो आफिसर्स उनका कहना नहीं मानते हैं उनके रोज ट्रांसफर्स होते रहते हैं। इनको बलिया भेजा जाय, इनको वहां भेजा जाय, आदि आदि।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि चोरी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं अपने जिले की बात कहता हूं कि सरई में दस हजार की चोरी हुई और एक बंदूक भी गई। इसकी रिपोर्ट की गई और सुपरिंटेंडेंट से भी कहा गया और आदमी भी पकड़ा गया। लेकिन कोतवाल ने उसे छोड़ दिया और कोई कार्यवाही इस में नहीं हुई। इसका नतीजा यह होता है कि छोटी-छोटी चोरियां तो लोग पुलिस में लिखाते ही नहीं हैं। देहात में यह हालत हो रही है कि रोज ब रोज गुंडाशाही बढ़ती चली जा रही है। अगर कोई पार्टी नहीं बनाता है तो गांव में नहीं रह सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---दस मिनट हो गये हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह---अगर दो, तीन मिनट और मिल जायं तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष---अच्छी बात है।

राजा वीरेन्द्रशाह---अब वही बात सुनते आ रहे हैं कि लोग कहते थे कि सत्तावन किस तरह होता है। सत्तावन अपनी सरकार के खिलाफ नहीं होता है। लेकिन जब आप एक आदमी की जिन्दगी दुश्वार कर देंगे तो वह क्या करेगा ? कहा जाता था कि जमींदारी के खत्म होने के बाद सबका सिर ऊंचा होगा। अब किसका सिर ऊंचा है ? सरकार ऊंचा करे। जमींदारों का कोई हक नहीं है। जमींदारी खत्म हो गई।

आप बात तो कोआपरेटिव की करते हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। आज मिल वाले दो सौ, तीन सौ आदमी हैं। वही आज दो सौ फीसदी का फायदा उठाते हैं। उनको करोड़ों का फायदा होता है। इसलिये आप ऐसा करें कि कोई पांच साल की योजना बनाकर शुगर मिल्स कोआपरेटिव तरीके पर चालू करें। जमींदारियों का नाश होना जरूरी था, वह हो गया। लेकिन इनको रखने की क्या जरूरत है ? लांछन यह लगता है कि इलेक्शन फंड के लिये रखे जाते हैं। आप क्यों नहीं सोचते हैं जब कि दूसरे प्रान्त ने आर्डर दे दिया है कि कोई शुगर मिल बिना कोआपरेटिव के नहीं चल सकती है, तो हमारी सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है ? क्यों सरकार आज इन २००-३०० आदमियों की रक्षा करती है ? उनको कम्पैन्सशन दे दिया जाय। धीरे-धीरे ५-१० साल में उनको रुपया दे दिया जाय। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को जब तक मजबूर नहीं किया जायगा सरकार सुनने वाली नहीं है। इनको राजी रखिये तो बुरा से बुरा काम करे और कोई बात नहीं और अगर नाराज कर दो तो अच्छे से अच्छे आदमी का सिर भी गढ़े में चला जायगा। इतना कहकर मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि वह होशियारी से काम करे।

*श्री आर्थर सी० ग्राइस (आंग्ल भारतीय नाम निर्देशित)---उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश हुआ है उसके ऊपर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। अब मैं आपके द्वारा कैबिनेट को दो मिनट के लिये कानपुर ले जाना चाहता हूं। कानपुर पहले भी था और अभी भी है पर जिस हालत में आज वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वह बहुत ही खराब है। रो सब रहे हैं पर कोई असल बात नहीं कह रहा है। मैं कहता हूं कि जब तक मिलों का रेशनलाइजेशन नहीं होगा तब तक मिलों का सुधरना बहुत मुश्किल है। मुमकिन है कि अगर कानपुर काटन मिल्स को रेशनलाइजेशन की इजाजत मिल जाती तो वह चालू रहती और ३,००० आदमी बैठे न रहते जो आज बैठे हैं। सिर्फ ५०० आदमी निकाले जाते और बाकी ३,००० आदमी काम में लगे रहते। आज ईमानदारी से पूछ लिया जाय कि एक-एक मिल में कितना कपड़ा पड़ा है। वह बिक इसलिये नहीं रहा है कि पर कैपिटा इन्कम बहुत कम हो गई है और कोई इतने बढ़े हुये दामों पर कपड़ा खरीदने के लिये तैयार नहीं है। अगर रेशनलाइजेशन हो जाय तो दाम कम हो जायं।

एक सदस्य---और जो लोग निकाल दिये जायेंगे वे कहां जायेंगे ?

श्री आर्थर सी० ग्राइस---उनके लिये यह हो सकता है कि सरकार लेबरवेलफेयर स्कीम पर लाखों रुपया खर्च कर रही है, उस स्कीम को वहीं छोड़ दिया जाय और जितना रुपया आपक बजट म रखा गया है वह रिहैबिलिटेशन में खच कर दिया जाय और जो आदमी निकाल जायं उनको दूसरे काम दिये जायं। अगर रेशनलाइजेशन नहीं होता है तो मिलों की हालत सुधर नहीं सकती।

अब मैं स्टट इन्श्योरेंस स्कीम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इससे अच्छी स्कीम अबतक कोई तैयार नहीं हुई, खासतौर से सोशलिस्टिक पैटर्न आफ स्टेट में, मगर इसक इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी कसर रह गयी है। कसर यह है कि डाक्टरों को आप काफी पैसा नहीं दे रह हैं। पहले तो आप उनको कुल ३० रुपये महीना नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स देते हैं और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री आर्थर सी० ग्राइस---]

२५ रुपये महीना हाउस एलाउन्स। कानपुर में कोई झोपड़ी भी २५ रुपये महीने में रहने के लिये नहीं मिलेगी और फिर एक डाक्टर, जिसे हैसियत बढ़ाना है वह २५ रुपये में कैसे रह सकता है? इस सब का नतीजा यह होता है कि वह कोशिश करते हैं कि वहां से निकाल दिये जायं और अस्पताल में वापिस चले जायं तो उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस भी मिलेगी और फ्री एकोमोडेशन भी मिलेगा। आप पैसा कम दे रहे हैं। इसी वजह से करप्शन वहां बढ़ रहा है। आप किसी को हमारे साथ लगा दीजिये। यह बिलकुल तयशुदा बात है कि ९० फ़ीसदी डिस्पेन्सरियों में दलाल ३ रुपया लेता है और छुट्टी दिलवा देता है।

दूसरी बात यह है कि सब्स्टीट्यूट से हमें काफी शिकायत है। जिसको पता लग गया कि अबके हफ्ते से बैठा दिया जायगा वह स्टेट इन्श्योरेंस डिस्पेंसरी में चला जाता है और ३ रुपये देकर के एक हफ्ते की छुट्टी लिखा लेता है। क्या यह जरूरी बात है कि हर आदमी साल में ५२ दिन बीमार रहे? लेकिन आप देख सकते हैं कि लेबर फ़ोर्स में हर आदमी साल में ५२ दिन बीमार रहता है। मुझ से पूछा जाय। मैं बता सकता हूं कि क्या हालत है। सर्दी के मौसम में वह बीमार पड़ते हैं और फिर देहात में चले जाते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब इस तरफ़ गौर करें। हमारे जो कम्पाउन्डर और डाक्टर हैं उनके रहने का और उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस का इन्तजाम पक्के तौर पर होना जरूरी है। तभी करप्शन हट सकता है। नहीं तो नहीं हट सकता है।

अब अपनी बात भी इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं। एक शख्स ने हमसे कहा कि ये जो एंग्लो इंडियन स्कूल्स हैं उनके लिये बजट में ७ लाख ८० हजार रुपया रखा गया है। मैं ७ साल से यह रोना रो रहा हूं कि उन स्कूलों की तरफ तवज्जह नहीं दी जाती है। यह रुपया जो बजट में रखा गया है इसमें से साढ़े ६ लाख रुपया तो खर्च हो जाता है, लेकिन १ लाख ३८ हजार रुपये की सेविंग हो जाती है। मैं मिनिस्टर साहब के पास भी गया और सारे डिपार्टमेंट में घूम आया हूं कि यह जो सेविंग होती है इसको स्कूलों की लायब्रेरी और रिपेयर के लिये लगा दिया जाय। मगर कोई सुनवाई नहीं होती है। वहां पर फरनीचर नहीं है, लायब्रेरी का सत्यानाश हो रहा है। १० साल से कोई किताब नहीं मिली है। बिल्डिंग की रिपेयर नहीं हुई है तो इसके लिये कोई इन्तजाम नहीं हो रहा है। जब मैं किसी के पास जाता हूं तो गवर्नमेंट के आफिसर यह कहते हैं कि शार्टेज आफ मनी है। इस तरह से १ लाख ३८ हजार रुपये की सेविंग है। मैं उसको ज्यादा रिकांसाइल तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं हिसाब-किताब का इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। लेकिन मैं एजूकेशन मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करता हूं कि वह इस तरफ अपना ध्यान दें और इन दिक्कतों को दूर करें।

एक बात और इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इन स्कूलों का नाम ही अब एंग्लो इंडियन स्कूल रह गया है, वरना उनके अन्दर अब दूसरे लोगों के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। एंग्लो इंडियन बच्चे उनमें १८ परसेंट पढ़ते हैं और ८२ परसेंट नान-एंग्लो इंडियन बच्चे पढ़ते हैं। हमारे नेशन की यही वैल्थ है। इसकी तरफ हमको खयाल करना चाहिये। हमारे इन स्कूलों में ही यह सेविंग नहीं हो रही है, बल्कि जनरल एजूकेशन के बजट में भी सेविंग हो रही है। हमारा खयाल यह है कि डिपार्टमेंट की तरफ से शायद उनको यह हिदायत है कि तुम इसमें ज्यादा सेविंग करो। अगर ऐसी बात है तो फिर ऐसी सेविंग से खुदा बचाये। थैंक यू, सर (Thank you, Sir.)।

श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बजट को शुरू से आखिर तक पढ़ा। एक दफा पढ़ने से तसकीन नहीं हुई तो मैंने इसको दोबारा पढ़ा। मैं तो इस को आराइशी बजट कह सकता हूं। इसमें अच्छी जुबान का इस्तेमाल किया गया है। इसक अतिरिक्त और कोई चीज हमें इसमें नहीं मिलती जिस से हमको

तसल्ली होती। इस बजट को पढ़ने के बाद मैं यह तजकिरा करना चाहता हूं कि अन-एम्पलाइमेंट का जिक्र इस पूरे बजट को पढ़ने के बाद भी कहीं नहीं मिलता है। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इसके बिषय में एक शब्द भी नहीं कहा।

जहां तक बेकारी का सवाल है चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हों या अन्डर ग्रजुएट हों सबके सब निहायत परेशान नजर आते हैं। हमारी यू० पी० की सरकार ने इस बेकारी की दिक्कत को दूर करने के लिये कुछ नहीं किया है और न करने जा रही है। । कर्जा लेना भी बुरा नहीं है। जब आदमी परेशान होता है तो उस वक्त कर्ज लिया जा सकता है। कर्ज लेना कोई बुरी चीज नहीं है लेकिन कर्जा लेने के बाद उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से होना चाहिये। कर्जा लेने के बाद अगर यह सरकार उसका सदुपयोग करती जिससे कि हमारा फ्यूचर अच्छा होता, देश की बेकारी दूर होती और लोगों का रहन-सहन का स्तर भी ऊंचा होता, खाने पीने का सामान लोगों को मिलता तो ज्यादा खुशी की बात थी कि अच्छी चीजों के लिये कर्जा लिया गया। लेकिन यहां पर दूसरी बात ह। इस सदन को मालूम है कि यहां पर सवाल किय गये तो सरकार ने तसलीम किया। यह अगर मुसल्लिमा है कि एक मौत पूर्वी इलाके में भूख की वजह से हुई आज भी हमारे देश में जब हमारा ऐलान है कि हम किसी को भूखा नहीं मरने देंगे, हम देखते हैं कि लोग गुठली खा कर मरते हैं और लोगों को पेट भर खाना नहीं मिलता। यह बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश में ऐसे आदमी हों कि जिनके पास खाने को भोजन, पहनने को कपड़ा और अपने लिये रोजगार न हो। ऐसे देश में किसी भी राज्य को, किसी भी सरकार को फख्र से सर उठाने का मौका नहीं होता।

हमारी सरकार ने जो वायदे किये थे वह गलत निकले। इसके पहले का जो बजट था और यह जो बजट है, उनमें कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के लिये एक भी लफ्ज नहीं कहा गया है। सबसे पहले आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया था कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग कर दिया जाय। उसके बाद वांचू कमेटी ने भी यही सिफारिश की, लेकिन वह आज तक नहीं हुआ। थोड़ दिन हुय मने यह सवाल किया था कि हाईकोर्ट, लखनऊ और इलाहाबाद म कुल कितने मुकदमें पेंडिग हैं, तो पता लगा कि उनकी तादाद ३९,००० से ज्यादा है। इसके अलावा जितनी दर होती है इंसाफ इन में, इंसाफ उतना ही ठीक नहीं होता। १५,१५ साल के मुकदमें पड़े हैं कि जिनका फैसला अभी नहीं हुआ। इस से हम अंदाजा कर सकते हैं कि कैसा न्याय हो रहा है। आज भी अदालतों को देखा जाय तो पता चलेगा कि एक मामूली जुर्म की इनजरी रिपोर्ट मिलने में १५ रोज लग जाते हैं। जस्टिस के लिय इस साल कुल १,७४,३१,४०० रुपये की मांग की गई है, लेकिन देखने से पता लगता है कि इंसाफ मिलने में दिक्कतें हो गई हैं और इंसाफ पाना मुश्किल हो रहा है। इतनी देर हो गई है इंसाफ देने में कि जिसने मुकदमा दायर किया है वह भी नहीं है, जिस पर दायर हुआ है, वह भी नहीं है और अदालतें भी नहीं हैं। यह तो मैंने इंसाफ की बात रखी। जिस राज्य में इंसाफ न हो वह राज्य फख्र से सर उठाने लायक नहीं है।

इसके अलावा आजादी की लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा लिया और अपने देश के लिये जिन्होंने खून बहाया वह भी आज परेशान हैं। मेरा इशारा पोलिटिकल सफरर्स की तरफ है। उनके लिये १३ लाख ३५ हजार रुपया रखा गया है। पिछले साल कुछ ज्यादा रुपया था और इस साल इसमें ५०,००० रुपये की कमी की गई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया है और उसे जारी रख कर अपना खून बहाया है उनमें से ज्यादा तर के आंख नहीं हैं, किसी के हाथ पैर ठीक नहीं हैं और वे काम करने से कासिर हैं, परेशान हैं। उनके पास रोजी का कोई जरिया नहीं है। ऐसे लोगों को, किसी को आप २० रुपया पेंशन देते हैं और किसी को १५ रुपये। पहले तो

[श्री शिवराजबहादुर—]

यह था कि उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सार्टिफिकेट देता था कि वे जेल गये हैं या नहीं, लेकिन अब शायद असेम्बली के मेम्बर भी सार्टिफिकेट देते हैं। ऐसा करना, मैं समझता हूं कि उनके साथ खिलवाड़ करना है।

इस के अलावा फैमिन रिलीफ के लिये ५२,६६,२०० रुपया रखा गया है। यह बहुत कम है, इस से रिलीफ नहीं होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय माल मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि यह पूर्व या पश्चिम का सवाल नहीं है। पूर्व की बात सुनते-सुनते हमारे पश्चिम में भी वही हालत हो गई है। २०–२१ अक्तूबर को जब यह बारिश आयी उस समय मैं अपनी कांस्टीट्यूयेन्सी में ही था। मैंने देखा कि ओला पड़ रहा था और बारिश हो रही थी। मैंने जब सवाल किया तो जवाब मिला कि १४० गांव ऐसे हैं कि जहां नुकसान पहुंचा है। उसमें रुपये में १४ आने का नुकसान है। अगर उसको छोड़ दिया जाय तो नामुनासिब बात होगी, वे इम्दाद के मुस्तहक हैं।

हमारी सरकार ने इंडस्ट्री के लिए कई वादे किये। "वादा भी टल गया शबे वादा भी टल गया"। यह कहा गया था कि बरेली में कारखाना खुलने वाला है। इस साल भी बजट स्पीच में रबर का कारखाना खुलने का जिक्र है लेकिन अभी तक खुला नहीं है। छोटी इंडस्ट्री को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। आपका कहना है कि कपड़े पर से सेल्स टैक्स हटा दिया गया है। लेकिन उसी कपड़े को खरीद कर जब एक दर्जी ले जाता है और उससे रेडीमेड कपड़े तैयार करता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। इसी तरह से बाजार में खड़ा होकर जो कपड़ा बेचता है, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है। छोटे-छोटे मोजे के कारखाने हैं, उन पर भी टैक्स लग जाता है। इवेजन आफ टैक्स की बात तो दूसरी है, लेकिन यहां आपने छोट-छोटे रोजगार वालों को भी इससे तलाफी नहीं दी है।

मेडिकल डिपार्टमेंट की हालत भी बहुत खराब है। बाहर से आने वाले मरीजों को बड़ी दिक्कत होती है। अगर ब्लड टेस्ट कराया जाय तो बाजार में जब कि २ रुपया लगते हैं, हास्पिटल में ५ रुपया लिया जाता है। अस्पताल में मरने वालों की तादाद भी ज्यादा हो गयी है। मरीजों की तादाद ज्यादा है और बिस्तरों की बहुत कमी है। कानपुर हमारे सूबे का एक बहुत अच्छा शहर है, लेकिन उसमें टी० बी० के मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है। जितना बड़ा शहर है उतनी ही तादाद टी० बी० के मरीजों की वहां है, यह बहुत शर्म और अफसोस की बात है।

इसके अतिरिक्त सेंटर से यह फैसला हुआ है कि सब प्राविन्सेज में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स कायम किये जायं, लेकिन यू० पी० में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अभी तक कायम नहीं हुआ है। यह मसला भी सरकार की तवज्जुह का मोहताज है।

तालीम के सिलसिले में छठी क्लास तक की फीस माफ की गयी है, लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां माफी नहीं हुई है।

इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के जरिये से बहुत बड़ा काम चल रहा है। कहा गया कि इसके जरिये से लोगों को खुशहाल बना देंगे, हर जगह लोगों को पानी मिलेगा, गल्ल की पैदावार में इजाफा हो जायगा। लेकिन एक तरफ तो मुसीबत नाजिल हुई है और दूसरी तरफ आबपाशी के साधन भी नहीं बढ़ाये गये हैं।

छोटी सर्विसेज के लोगों की हालत बहुत ही खराब है। पतरोलों की तनख्वाह ५० रुपया है। और इससे ज्यादा बढ़ने का कोई इमकान भी नहीं है। अगर इन लोगों को कुछ ऊंचा करने की कोशिश हम नहीं करेंगे तो हम अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करेंगे।

सफा ४ पर यह कहा गया है कि "इस पर निगाह रखने से अधिक विकास के साथ फल ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को मिल जाय जिन पर लक्ष्मी की अभी तक पूर्ण कृपा नहीं है" । लेकिन मेरा कहना यह है कि हम सब पर लक्ष्मी की नजर होते हुए भी उसकी कृपा नहीं है । जिस तरीके से एक चिड़िया कफस में फंस जाती है, बार-बार वह फड़फड़ाती है लेकिन उड़ नहीं पाती, उसी तरह से हमारे वित्त मंत्री जी अल्फाज और खुशहाली के अल्फाज में ऐसे फंसे हुए हैं कि वह कफस में से निकल कर उड़ना चाहते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते । हमारे देश में और प्रदेश में ऐसी हालत पैदा होनी चाहिये जिससे हर आदमी आसानी से अपनी जिन्दगी बसर कर सके, उसे खाने को मिले, कपड़ा पहनने को मिले और इसके साथ उसकी तालीम का बंदोबस्त हो । इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कहूंगा ।

*श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो इस वर्ष का बजट बनाया है, उसमें कोई नया कर नहीं लगाया है । जब मैं माननीय वित्त मंत्री जी को यह धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष कोई नया कर नहीं लगाया है, वहां अपने खयाल से मैं यह भी सोचता हूं कि बजट को बनाने वालों ने अच्छी तरह से सन्तुलन के साथ बजट को नहीं बनाया है । अगर आपकी बजट स्पीच की ओर जाता हूं तो देखता हूं कि जिस समय आपने सन् ५६-५७ का बजट पश किया था तो उस वक्त घाटे का बजट बनाया था, लेकिन जब अन्त में देखा गया तो वह सरप्लस बजट रहा । इससे मालूम होता है कि जो आपके अधिकारी हैं, जो इस बजट को बनाने वाले हैं, उन्होंने आप के साथ अच्छी तरह से कोआपरेशन नहीं किया जिससे घाटे का बजट बनाया गया । माननीय वित्त मंत्री जी से आपके द्वारा श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री ने कई मर्तबा यह कहा है कि प्रादेशिक सरकारें अपने भरोसे पर ही ऐसा बजट बनावें और सेंटर की तरफ ज्यादा निगाह न रखें । सेंटर से उनको ज्यादा मदद नहीं मिल सकती है । हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह भी कहा कि जो बजट बनावें, वे घाटे का बजट न बनावें, लेकिन हमने देखा कि केरल की सरकार को छोड़कर सभी सरकारों ने घाटे का ही बजट बनाया है । मैं भी घाटे का बजट नहीं पसन्द करता हूं ।

अब मैं बजट की विशेषताओं की तरफ जाता हूं तो देखता हूं कि ४०० रु० मासिक पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में आपने महंगाई भत्ते का आधा जोड़ दिया है, लेकिन इससे उनको कोई इमीडियेट फायदा नहीं हो पायेगा । उनके पेंशन के वक्त कुछ फायदा भले ही हो जाय । मेरे खयाल से यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग इमीडियेट फायदे को न देखकर भविष्य के फायदे को देखते हैं । सरकार को उधर भी ध्यान देना चाहिये ।

इसके अलावा इस बजट में हरिजनों के लिये कुछ मकानात का भी प्रबन्ध किया गया है । जहां तक हरिजन स्कूलों के टीचरों की बात है, उनके लिये जो सर्विस कंडिशंस हैं, वह आपने और स्कूलों के बराबर ही रखा है । मुझे तो आपको बधाई देनी है कि आपने हरिजनों की हालत को देखा और उनके मकानात के लिये थोड़ा सा इन्तजाम किया । जहां पर मैं आपको बधाई देता हूं, वहीं पर मैं आपसे यह भी कहता हूं कि हरिजनों की दशा ऐसी है, और हरिजनों की दशा ही क्या, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश में इंसान नहीं पैदा होते हैं । हमारे देश में ब्राह्मण पैदा होते हैं, हमारे देश में क्षत्रिय पैदा होते हैं, हमारे देश में चमार पैदा होते हैं । तो यह जो आपने थोड़ा सा धन उनके मकानात के लिये रखा है, इसी से आपको स्थिर नहीं होना है । जब मैं हरिजनों की हालत को देखता हूं तो मेरे मन में यह खयाल होता है कि अभी तक यह हरिजन कहीं जाने वाली जाति क्यों हिन्दू धर्म से चिपटी हुई है, जिसका समाज के अन्दर कोई स्थान ही नहीं है । फिर भी मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनके मसले को अहम समझते हुए उनके रहने के लिये मकानात की कुछ व्यवस्था की है और उनकी तरफ ध्यान दिया है । मेरे खयाल से अगर उनकी आर्थिक हालत सुधर गयी तो भविष्य में सामाजिक हालत भी अच्छी हो जायगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गनेशीलाल चौधरी—]

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में वे कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं लाये। पिछले साल सरकार ने यह किया था कि छठी कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की थी और हम आशा करते थे कि इस वर्ष जब माननीय वित्त मंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे तो अगली दो एक कक्षाओं में भी वह निःशुल्क शिक्षा देने की योजना लायेंगे, लेकिन उस दिशा में हमें निराशा हुई । हमें इस बात की खुशी भी है कि एडेड स्कूलों के अध्यापकों को भी सरकारी नौकरों की तरह मेडिकल फेसिलिटीज देने का विचार किया गया है । मैं शिक्षा के बारे में इतना और कहूंगा कि हमारे यहां का शिक्षा का स्तर स्वतन्त्रता आने के बाद गिरा है, उठा नहीं है । इस विषय में अभी एक सर्वेक्षण कमेटी बैठी थी उसकी रिपोर्ट है कि यहां का शिक्षा का स्तर कुछ गिरा है इसलिये माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां की शिक्षा के स्तर को उठाने की ओर विशेष ध्यान दें ।

आप ने इस जमाने में काफी अस्पताल खुलवाये हैं और वहां चिकित्सा का प्रबन्ध किया है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जो कुछ भी यह प्रबन्ध हुआ है वह कामन पीपुल के लिये नहीं है, हां, यह जरूर है कि जिन लोगों के जरिये हैं उनको वहां अधिक फेसिलिटीज मिल जाती हैं ।

मैं सिंचाई विभाग की ओर भी सदन का ध्यान दिलाऊंगा। आप ने कहा कि हम ने सिंचाई में काफी तरक्की की है, लेकिन जब हम देखते हैं कि सिंचाई से जो पैसा हमें मिल रहा है उसमें कमी हुई है । इसका कारण क्या है ? सिंचाई के लिये वहां पानी है, लेकिन पैसा कम आता है इस का कारण यह है कि वहां के इंतजाम में बड़ी गड़बड़ी है, गूलों में पानी बह रहा है लेकिन वह किसानों को नहीं मिलता । इस सम्बन्ध में मैं अपने यहां की एक मिसाल दूंगा कि जून, सन् १९५६ में हमारे यहां के लोगों ने एक गूल या नाली को बदलने की कोशिश की लेकिन वह गूल अभी तक नहीं बनी है । मैं चाहूंगा श्रीमन्, मुझे थोड़ा-सा समय और दे दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—अभी २ मिनट आप और बोल सकते हैं ।

श्री गनेशीलाल चौधरी—धन्यवाद श्रीमन्, जब हम अपनी पंचवर्षीय योजना की ओर देखते हैं तो उसमें चौमुखी उन्नति हुई है परन्तु जब हम एम्पलायमेंट के प्रश्न को लेते हैं तो देखते हैं कि बहुत कम लोगों को नौकरियां मिली हैं । यदि इस सेक्रेटेरियेट को ही देखें तो आप पायेंगे कि एक आदमी का तो पूरा खान्दान, बाप भी, लड़का भी, मां भी सब कोई लगे हैं लेकिन जो बाहर के आदमी हैं, गांव के आदमी हैं, उनको कभी भी यहां जगह नहीं मिलती । जितना भी एम्पलायमेंट यहां क्रियेट होता है वह यहां दफ्तर के लोगों तक ही सीमित रह जाता है । जबतक आप प्रोफेशन की डायरेक्शन नहीं करते, जबतक आप यह नहीं कहते कि एक आदमी पर ४–५ आदमियों को खिलाने पिलाने का भार रहेगा तबतक यह समस्या हल नहीं हो सकती ।

जहां तक पूर्वी जिलों का ताल्लुक है वहां के लिये विशेष इंतजाम किया जाता है, वह वहां की दशा को देखते हुये ठीक ही है, लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि पूर्वी और पश्चिमी जिलों के झगड़े में उनको तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हमारे जो यह अवध के बीच के १२ जिले हैं उन को कुछ नहीं मिल पाता, जब कोई स्कीम बनती है तो वह पूर्वी जिलों के लिये या पश्चिमी जिलों के लिये बन जाती है और हमारे जिले नेगलेक्टेड रह जाते हैं । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जब भी कोई स्कीम बनाई जाया करे तो हमारे अवध के बीच के जिलों की अवहेलना न की जाया करे बल्कि बराबर खयाल रखा करें । इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मैं यह देखता हूं कि माननीय सदन के अंदर भी दो बिरादरी हैं एक अंग्रेजी जानने वाले और दूसरे हिन्दी । जो अंग्रेजी जानते हैं उनको समय मिलता है, हिन्दी वालों को यहां भी कोई नहीं पूछता । यह तो मैंने एक खास चीज देखी है ।

बजट के ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है। उसके काफी आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं। बजट को गांव में हिसाब-किताब कहते हैं। जिसके घर का हिसाब किताब ठीक होगा उसका घर ठीक होगा, जिस सरकार का हिसाब किताब ठीक होगा उसका शासन ठीक होगा। जिस घर के हिसाब में गड़बड़ी होगी, कमी होगी उसका घर नहीं रहेगा और जिस राज्य के हिसाब में गड़बड़ी होगी वहां का प्रजातन्त्र खत्म हो जायगा। मोटी सी बात है। ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता।

जमींदारी प्रथा हमारी कांग्रेस सरकार ने खत्म की। यह पहला कदम सोशलिज्म की तरफ था। लेकिन नौ कदम टाटा, बिड़ला, डालमिया, दौलतराम, होराचन्द, पद्मपति सिंहानिया आदि की तरफ। कहने की बात है। दो मिनट समय तो ले ही लूंगा। शायद मिल जाय हिन्दी वालों को भी। जमींदारी प्रथा खत्म हुई। बड़ी खुशी मना रहे थे किसान कि लगान आधा होगा। लेकिन हुआ क्या, दस गुना। दस गुना महकमे, दस गुना अहकाम दस गुना झूठ, दस गुनी दलाली, दस गुना अन्याय, दस गुने इंस्पेक्टर, दस गुने कलेक्टर सब दस गुने बढ़ गये। 'अंधेर नगरी बेपूछ राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा'। हमें बड़ी आशा थी। मैं यह नहीं कहता कि मैं किसी के ऊपर अपनी ठीकरें लगा रहा हूं। मैं तो एक चीज कह रहा हूं। प्रजातन्त्र के अन्दर हम और आप एक हैं। पचास रुपये लगान वाले किसान को पांच सौ रुपया दस गुने का देना पड़ा। लगाइये इसका अन्दाज। दो रुपये सैकड़े पर नहीं मिलता है। तो वह तो किसान उल्टा मर गया। फिर सन् ५५ में किसान का गल्ले का भाव गिर गया। सात रुपये मन जौ, साढ़े सात रुपये मन चना, छः रुपये मन मटरा, चौदह रुपये मन सरसों, वही गेहूं जो मई के महीने में दस रुपये में बिका, अक्तूबर में जाकर १५ रुपये मन बिका, सरसों जो मई में १४ रुपये मन में बिकी वही अक्तूबर में २४–२५ रुपये मन बिकी। ऐसा डकैत और चोर आज तक हिन्दुस्तान में कोई नहीं हुआ जिसने सारे क्षेत्र और घरों के अन्दर नकबजनी की हो, इतनी बड़ी चोरी कि साढ़े छः करोड़ घरों में एक रात ही में सेंध लगा दी और किसान को मालूम पड़ा छः महीने के बाद कि हम लूट लिये गये। मई में जो गेहूं दस रुपये मन बिका वही अक्तूबर में १५ रुपये मन बिका। सब किसान घबड़ा गये। यह इनकी नेकनीयती। अरे मेरे भाई, मेरे साथी, कुछ तो खयाल करो। समाजवाद की तरफ तो जा रहे हो। पर क्या समाजवाद को निर्गुण बना लिया है? ओम्, ओम्, ओम्। जैसे कि ईश्वर को रटते हैं। उसी प्रकार समाजवाद की रट लगा रखी है। समाजवाद, समाजवाद, समाजवाद। यह है किस चिड़िया का नाम? एक के पेट में कब्ज से दर्द हो रहा है और एक भूखा चिल्ला रहा है, क्या इसी का नाम समाजवाद है? अरे, उसके पेट की खराबी निकल जाय और दूसरे के पेट में रोटी जाय, इसका नाम है समाजवाद। सन् ३७ में जब महात्मा जी थे तब कांग्रेस ने सराहनीय कार्य किया। उस वक्त कांग्रेस समाजवाद की तरफ चल रही थी। करों को हटा रही थी, बकाया लगान को माफ कराया था। उस वक्त की एक कविता याद आ गई :—

भूमि कर विरुद्ध होती, छूट की न बात होती,
दूध वाले, फलवाले, कर वाले होते तो।
कर धन पर कर होते, गान्धी न गर होते,
लाखों नर बिना दिये हवालात होते तो॥
पशुओं की भांति नरपशुओं की हाट होती,
त्राहि-त्राहि जनता और बाल सब रोते तो॥
देशी सुदेशी की नाम आज मिट जाती,
लुट जाती भारत गर गान्धी न होते तो॥

श्रीमन्, इस देश में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा है? विदेशों में २०–२५ सैकड़े पुश्तैनी गुलाम हैं तो हमारे हिन्दुस्तान में ६५ फीसदी हैं। जब तक यह प्रतिक्रियावादी, यह चापलूसी करने

[श्री टीकाराम पुजारी---]

वाले, यह पुश्तैनी गुलाम रहेंगे, इनके सहायक गुलाम रहेंगे तब तक इस देश से भ्रष्टाचार नहीं जा सकता, तब तक शुद्ध समाजवाद नहीं आ सकता । उसने हमको भ्रष्ट किया, अच्छों-अच्छों को भ्रष्ट किया । मोटी बात मैं कहता हूं । मुझे याद आ गयी :---

राज को काज चले करघा सौं, पंचन में खुदगर्जी भरी है ।
निशदिन दीन सतावन की विधि नित नई रोज रचें जबरी है ।।
रोक न टोक न भाव न न्याय न देश प्रजा उलटी सगरी है ।
सुराज वर्षा होते मेढक उछल पड़े नहिं देर करी है ।।
कभी न गान तिरंगा गाया चोहत्तो नहीं खर्च करी है ।
समता करें तुरंगन की खर, गधों के ऊपर झूल पड़ी है ।
चोर गवांर लबारन की ऐसी बबरी में बड़ी बबरी है ।।

यह है इनका समाजवाद और प्रजातन्त्र । मैं कह रहा हूं एक चीज श्रीमन्, दो सौ रुपया मिलते हैं हमें । सब इधर और उधर के बैठने वाले सांप नाथ, नागनाथ, एक ही हैं । उनमें कोई फर्क नहीं है । दस रुपया रोजाना भत्ता और फर्स्ट क्लास का किराया । मेरा सुझाव है, कुछ त्याग करके दिखाइये । मैं पहले १४४ माननीय सदस्य जो विरोधी पार्टी के हैं उनसे अर्ज करता हूं कि १५० रुपया महीना तनख्वाह लो और ५ रुपया दैनिक भत्ते के लो और रेल का पास ले लो । फिर उधर कांग्रेसी सदस्यों पर भी असर पड़ेगा कि समाजवादी या विरोधी दल यह कर रहा है । सच्ची बात है । एक बात और याद आ गई । एक दोहा हमारे यहां प्रसिद्ध है :---

राम नाम को लूट है लूटी जाय सो लूट,
अन्त काल पछतायेगा जब प्राण जायेंगे छूट ।

बिलकुल वैसी ही बात है---

प्रजातन्त्र की लूट है लूटो जाय सो लूट,
अन्त समय पछतायेगा जब ये कोठी जायेंगी छूट ।।

तब क्या होगा ? बस इतना ही कह के मैं बैठ रहा हूं ।

श्री रामचन्द्र देशमुख (जिला अलीगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । आज दो-तीन दिनों से मैं बराबर इस बजट पर बहस सुन रहा हूं । सब लोगों ने इसके ऊपर आंकड़े दिये और सब कुछ किया, लेकिन एक बात अभी तक सुनने में नहीं आयी कि इस समाज का निर्माण करने के लिये हमें किस चीज की जरूरत है । सब कहते हैं कि आज समाज में चोरी बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, यह सब कुछ हो रहा है । लेकिन मैं यह समझता हूं कि सरकार के साथ-साथ प्रजा और विरोधी दलों का भी कुछ फर्ज है । उनका कितना सहयोग हमको मिलता है, यह देखने की बात है । अगर हमको सहयोग मिले तो हम कह सकते हैं कि समाजवाद बहुत नजदीक है । पर हमें तो सहयोग नहीं मिलता । हम तो देखते हैं कि केवल क्रिटिसाइज करने के लिये वे यहां हैं । मैं यह कह सकता हूं कि हम लोगों की भी कमियां हैं । हम अपने चरित्र निर्माण की तरफ नहीं देखते । अगर हम उसकी तरफ देखें तो भुखमरी दूर होना मुश्किल नहीं । जितने पढ़े लिखे लोग हैं वह हमें कितना सहयोग देते हैं ? कितना सहयोग सरकार को देने की कोशिश करते हैं ? हम लोग केवल यह समझते हैं कि जो कुछ भी जिम्मेदारी है वह सरकार की है और सरकार जो कुछ भी करती है वह अपने लिये करती है । हम यह नहीं देखते कि हमें समाज के लिये क्या करना चाहिये ?

जहां तक भुखमरी का सवाल है, मैं सरकार से कहता हूं कि भुखमरी बड़ी आसानी से दूर की जा सकती है । जहां तक सर्विसेज की बात है उसमें पढ़े लिखे किसानों के लड़के आने चाहिये । मालदारों के लड़के, जिनके पास साधन हैं, आते हैं । उनको क्यों नौकरी

दी जाय, मैं यह पूछता हूं ? जो गरीब हैं उनको नौकरी दी जानी चाहिये । जब पढ़े-लिखे लड़के गरीब किसानों के आयेंगे तो वे ग्रो मोर फूड की स्कीम को उठायेंगे और देश के चरित्र को भी ऊंचा उठायेंगे । उससे भुखमरी का भी सवाल दूर होता है और बेकारी का सवाल भी दूर हो सकता है। लेकिन गवर्नमेन्ट के अन्दर आज जो भी हैं वे समझते हैं कि सारी जिम्मेदारी उनकी ही है और अपने रिश्तेदारों को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें गरीब का हिस्सा नहीं रहता। इसीलिये मैं कहता हूं कि जब किसान पढ़ा लिखा होगा तब सब ठीक हो जायगा। उसके साथ जो अन्याय होता है, जो लूटमार होती है वह नहीं हो सकती। जो बेकार लोग हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिनके पास रहने के लिये स्थान नहीं है वे अगर नौकरियों में आवें तो बेकारी तो दूर हो ही सकती है, लेकिन अगर सरकार ध्यान दे तो उससे भुखमरी भी दूर हो सकती है ।

क्राइम के लिये कहा जाता है कि वह बढ़ता चला जाता है । मैं पूछता हूं कि समाज उनको रोकने में कितना सहयोग देता है ? पुलिस के सामने ऐसे सवाल रोज आते हैं। जहां डकैती पकड़ी जाती है, जहां चोरी पकड़ी जाती है वहां समाज के लोग जाकर उनसे कहते हैं, कोशिशें करते हैं, उनको छुड़ाते हैं, अदालतों में जाकर उनकी ओर से गवाहियां देते हैं। नतीजा यह होता है कि क्राइम्स नहीं रुकते हैं। जो कानून बने भी हैं उनको भी इधर उधर से तोड़ मरोड़ कर फायदा उठाते हैं। अगर उनका बहिष्कार किया जाय तो मैं समझता हूं कि चोरी, डकैती नहीं हो सकती। जो कानून हमारे हैं वे भी पुराने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। उसमें पुलिस के सामने यह फायदा रहता है कि जो चोरों को, डकैतों को पकड़े उनको शाबाशी मिलती है। लेकिन जो चोरों और डकैतों को नहीं पकड़ सकते हैं उनको तनज्जुली मिलती है। जब थानेदार देखता है कि उसकी जिम्मेदारी है और चोरों और डकैतों को पकड़ने से ही उसकी तरक्की होनी है और चोरियां न पकड़ने से उससे कहा जायगा कि तुम्हारे इलाके में चोरी डकैती क्यों नहीं है, तो इसका नतीजा यह होता है कि उसको चोरों, डकैतों से मिलना पड़ता है और अपनी केस डायरी में दिखाना पड़ता है कि उसने इतने केस पकड़े। इससे उसकी बढ़ती होती जाती है। वह सोचता है कि उसकी तरक्की इसी पर है कि उसने इतने अधिक डकैतों को, इतने अधिक चोरों को पकड़ा और उसने बड़ा भारी काम किया, अगर सरकार ईमानदारी से सोच ले कि किसी इलाके में कोई भी चोरी डकैती हुई तो उस तरफ के अधिकारी को निकाल देंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उसके इलाके में चोरी डकैती नहीं हो सकती। ईमानदारी से वह यह कोशिश करेगा कि चोरी डकैती उसके इलाके में न हो तो चोरी डकैती रुक सकती हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार करें जो चोरी डकैती ज्यादा दिखाने में शाबाशी समझते हैं, तो चोरियां और डकैतियां रुक सकती हैं ।

जहां तक शिक्षा की बात है, मैं आज जो पढ़े लिखे हैं उनकी बात कहता हूं। वे छोटे काम करने वालों को नालायक समझते हैं और यहां तक कि अपने अपढ़ बाप को बाप नहीं कहना चाहते। उसका बेपढ़ा लिखा किसान बाप उसके समीप बैठ जाय तो फौरन कह देंगे 'He is not my father' तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं ? मैं सरकार से कहता हूं कि जितना काम करने वाला समाज है, जितना छोटा समाज है अगर उनको समाज में आदर दिया जाय तो मैं कह सकता हूं कि निर्माण काम आगे बढ़ेगा। वह रुक नहीं सकता।

आज जो काम हो रहा है वह अफसरों के हित में हो रहा है। पब्लिक के काम करने वालों का सम्मान नहीं है। कमिश्नर साहब जायं, कोई बड़ा अफसर जाय तो उसकी तारीफ होती है और जो निर्माण कर रहा है जिसने वाकई काम किया है, उसका पूछने वाला कोई नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी काम करने वाले हैं उनके साथ समानता का बर्ताव होना चाहिये, उनको आदर मिलना चाहिये। आज जो यह समस्या आ जाती है, जो यह अनादर की बात होती है उससे समाज का हित कभी नहीं हो सकता। आज जो जूता बनाने वाला है, वह जानता है कि वह समाज की सेवा कर रहा है। धोबी है, वह कपड़े धोता है, नाई बाल काटता है और मेहतर सफाई करता है, लेकिन समाज की दृष्टि में ये सब काम जो इतनी महत्ता रखते हैं उनका कोई ल्यूय नहीं है और इन सब समाज की सेवा

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

करने वालों को अनादर की दृष्टि से देखा जाता है। आज निर्माण में लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है, परन्तु निर्माण सीमित है अफसरान तक। वह अपना स्वयं निर्माण कर रहे हैं, लेकिन वह मजदूर जिससे काम कराया जाता है उसके निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं है। उसकी मजदूरी का जहां तक सवाल है उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलता। अगर उसको क्रेडिट नहीं मिलता तो कम से कम सम्मान तो मिल जाय, लेकिन वह भी नहीं मिलता। इसलिये यह काम रुक रहा है। सम्मान जिनके हाथ में शक्ति है, उनका होता है।

चुनाव क्षेत्र की बातें होती हैं, मैं कहता हूं कि आज गवर्नमेन्ट में एम० एल० ए० की कोई वकअत नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है कि वह सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अगर किसी जिले के एम० एल० ए० कोई बात कहते हैं तो कहा जाता है कि वह इंटरफियर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इंटरफियर करने वाली बात हमारे सामने आ जाती है। यह तो उसका कर्तव्य है कि वह अपने जिले और अपनी कांस्टीटुएंसी को सम्भाले। उसकी बात आप नहीं मानते, लेकिन एक अफसर अगर चपरासी भी कोई बात कहता है तो उसको सही माना जाता है। जहां तक रेग्रेजेंट करने की बात है, जहां तक स्तर ऊंचा उठाने की बात है, आज समाज ऐसी हालत में है कि जब तक इस समाज में ऐसी चीजें रहेंगी तब तक आप किसी की सही बात मानने के लिये तैयार नहीं होंगे।

आज हरिजनों के लिये मंदिर खुलवाने की बात बजट में कही जाती है कि हरिजनों के लिये मंदिर खुलवा दिये। मुझे कहना पड़ता है कि क्या मंदिर खोलने से आपने उन पर बड़ा एहसान कर दिया? वे मंदिर तो हरिजनों ने, शिल्पकारों ने स्वयं बनाये और उसके बाद उसमें उनको जाने से रोका जाय। करपात्री जी ने कहा था कि हरिजनों के जाने से मंदिर में देवता नहीं रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि उस मंदिर में देवता रहता ही नहीं है। बल्कि मंदिर हरिजनों के लिये खुलवा देने से भगवान को जिन्होंने कैद कर रखा था उनसे अब हरिजनों के द्वारा भगवान को मुक्ति मिली।

आज हरिजनों के मकानों के लिये सोचा जाता है और कठिनाइयां बतलायी जाती हैं। जिस हरिजन ने पहाड़ों को और जंगलों को काट-काट कर मैदान किया हो, नहरें निकाली हों उनके लिये छोटे से मकान की समस्या खड़ी हो जाती है। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह इस सम्बन्ध में अवश्य कदम उठाये और मजदूरों के मकान बनवाने की कोशिश करे। श्रीमन्, गवर्नमेन्ट की तरफ से कहा गया कि शरणार्थियों के लिये कितने क्वार्टर बनाये, लेकिन हरिजन अब भी पिछड़े पड़े रहें और उसी प्रकार समाज की सेवा करते रहें। आज उनके मकान के लिये इतनी बाधायें उपस्थित होती हैं। उनसे कहा जाता है कि आधा रुपया दो और उनके बच्चों से कहा जाय कि तुमको यह करना पड़ेगा।

आज रिजर्वेशन की बात कही जाती है और १८ परसेंट रिजर्वेशन की बात होती है, लेकिन बात तो डिपार्टमेन्ट में अछूत मिटाने की है। यह देखने की बात है कि समाज में कोई अन्तर पड़ा है या उसके दृष्टिकोण में कोई अन्तर पड़ा है? आज विभागों के रवैये में कोई अन्तर पड़ा है? 'स्टेबिलिटी' जो वर्ड है उसको आगे कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जब तक हमें सूटेबिल कैंडीडेट नहीं मिलते तब तक हरिजनों को लेने में असमर्थ हैं। आज यही दशा चारों ओर है। मैं बराबर कहता हूं कि हरिजन समाज की रीढ़ होते हैं, लेकिन उनको जमीन नहीं दी जाती है, उनको अच्छा वेतन नहीं मिलता है, उनको कोई नहीं पूछता है। आगे चलकर यह हमारी सरकार के लिये एक बड़ा भारी कलंक होगा। अगर यह समाज आगे चलकर पिछड़ जायगा और उसको उठाने का कोई साधन नहीं रहेगा तो सरकार कमजोर रह जायगी।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि दुनिया की कोई खुदगर्ज और रिएक्शनरी सरकार इससे अच्छा बजट तैयार नहीं कर सकती थी। हमने इस बजट में देखने का प्रयत्न किया कि

इसमें गरीबों के लिये क्या है, हरिजनों के लिये क्या है, विस्थापितों के लिये क्या है, होमलेस लोगों के लिये क्या है और भूख से तड़पने वाले लोगों के लिये क्या है ? बहुत ढूंढ़ने पर भी हम नहीं पा सके कि इन गरीब लोगों के लिये इस बजट में हमारी सरकार द्वारा क्या इम्दाद की गई है। यह सरकार तो मिल मालिकों के लिये, बड़े-बड़े लोगों के लिये करोड़-करोड़, डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपया कर्ज देती है।

यह सिस्टम यूनिवर्सल है। जब तक एक पार्टी की सरकार रहेगी तब तक हमारे देश से ये डिफेक्ट्स दूर नहीं हो सकते हैं, यह बुराइयां दूर नहीं हो सकती हैं। स्वीडन में जब बजट तैयार होता है तो उस वक्त वहां पर तमाम पार्टियों से मश्विरा लिया जाता है। एशिया का शेर नासिर जहां रहता है और जिसने आज सारी दुनियां को अपने कामों से चकित कर दिया है, उसने इतनी बहादुरी का काम किया है कि जब तक इस दुनियां में चांद और सूरज कायम रहेंगे तब तक कर्नल नासिर का नाम भी अमर रहेगा। उसी कर्नल नासिर ने मिस्र में अपने भाषण में कहा है :—

"The Party system of Government is not only no democracy but it strikes at the very root of democracy.

जब तक एक पार्टी का राज्य रहेगा तब तक डेमोक्रेसी कभी भी पनप नहीं सकेगी और उसकी जड़ धीरे-धीरे खोखली होती चली जायेगी। जब आप एक तिहाई हिस्सा एम० एल० सीज को देते हैं और एक तिहाई हिस्सा हर कमेटी में देते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि आप बजट बनाते समय या कैबिनेट की मीटिंग करते समय उनकी याद क्यों नहीं करते हैं ? यह पहला प्वाइंट है। इसको सरकार को नोट कर लेना चाहिये। नीति निर्धारित करते समय आप इन वन थर्ड को भूल जाते हैं।

मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा इस सदन से कह देना चाहता हूं कि जब तक इस तरह से यह सरकार चलेगी तब तक हालत ठीक नहीं होगी। अंग्रेजी राज्य में हमारे देश में और हमारे सूबे में जो कुछ था उसका आजकल से मुकाबिला करें। मैं एक छोटा सा काश्तकार हूं। मेरे लिये कह दिया जायगा कि यह तो दिन रात सियासी काम में लगा रहता है। लेकिन मैं बड़े-बड़े काश्तकारों के लिये कह सकता हूं कि वह लोग अंग्रेजी जमाने में समय से पहले अपना लगान अदा कर दिया करते थे। आज मेरे जिले में ५० फीसदी काश्तकार ऐसे हैं, जो हथकड़ियां पहन कर जाया करते हैं अदम अदायगी लगान में, अदम अदायगी आबपाशी में और अदम अदायगी मालगुजारी में। आज सारी दौलत कहां चली गई ? यह सारी दौलत आज हमारे देश के थोड़े से लोगों के हाथ में सिमट कर चली गई है। इसलिये यह सारी परेशानियां हैं। आज इस देश की नौका हम सब लोगों को मिलकर पार लगानी है। हम कोई मुखालिफ नहीं हैं, हम तो आपके हितैषी हैं, हम आपके खैरख्वाह हैं, हम आपका भला चाहने वाले हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा देश लाल क्रांति की ओर बढ़े, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में कोई खूनी इंकलाब आये। हम तो चाहते हैं कि प्रजातांत्रिक तरीके से आपका नाम और भी ऊंचा हो और महात्मा गांधी जी जिस सत्य और अहिंसा का आन्दोलन चलाते थे, उसमें सच्चे फल लगें। लेकिन हमारी परेशानी यह है कि आप हमारा कोआपरेशन लेने के लिये तैयार नहीं हैं, किसी भी मामले में। यह कहा जाता है और बाद को भी जब इस बजट के ऊपर मिनिस्टीरियल स्पीचेज होंगी तो कहा जायगा कि किसी भी विरोधी दल के सदस्य ने कोई भी कांस्ट्रक्टिव सजेश्चन नहीं दिया। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि भगवान हमारी सरकार को सद्बुद्धि दे जो वह मेरे सुझाव मान सके।

मेरा सबसे पहला सजेश्चन आबपाशी के मुताल्लिक है। आबपाशी में आप जानते हैं कि साढ़े ५ करोड़ रुपये का घाटा है। आपका ट्यूबवेल डिपार्टमेन्ट घाटे में रन करता है और काश्तकारों की कुर्की होती है और बदनामी गवर्नमेन्ट की होती है। जो ट्यूबवेल्स साढ़े बारह हार्स पावर के हैं, दस हार्स पावर के हैं, उनके लिये ८० रुपया फी हार्स पावर देते हैं। मैं पूर्वी जिला का हिसाब आपके सामने नहीं रखता हूं, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का हिसाब आपके

[श्री यशपालसिंह—]

सामने रखता हूं। साल भर में १० महीने ट्यूबवेल्स चलते हैं और ८० रुपये माहवार फी हार्स पावर, ट्यूबवेल डिपार्टमेंट, हाइडल डिपार्टमेंट को देता है। ज्यादा से ज्यादा जो कुछ देता है, एक हजार रुपया साल देता है। मैं हिसाब के मामले में जरा पठान हूं, अगर रुपये पैसे की कुछ गलती हो जाय तो माफ कर दीजियेगा। १०० रुपये माहवार, यानी सवा ३ रुपया रोजाना हाइडल डिपार्टमेन्ट को ट्यूबवेल डिपार्टमेन्ट पे करता है और काश्तकार ट्यूबवेल डिपार्टमेन्ट को ३२ रुपये रोजाना पे करता है। हम ३२ रुपये रोजाना देते हैं ट्यूबवेल डिपार्टमेन्ट को और ट्यूबवेल डिपार्टमेन्ट सवा ३ रुपये रोजाना देता है हाइडल को लेकिन फिर भी वह साढ़े ५ करोड़ के घाटे से चल रहा है।

क्यों चल रहा है, इसका भी एक रहस्य है। अगर आप बजट लिटरेचर को पढ़ें तो फल संरक्षण डिपार्टमेन्ट ने गवर्नमेन्ट से मांग की है कि एक ट्यूबवेल के लिये १८,००० रुपये मंजूर किये जायं। मैं मेरठ डिवीजन के ऐसे कई सौ ट्यूबवेल्स को जानता हूं जो २,००० रुपये में तैयार हो गये और हमारी मेहरबान सरकार एक ट्यूबवेल पर ६०,००० रुपये खर्च दिखलाती है। सरकार ६०,००० रुपये खर्चा दिखलाती है, उसी सरकार का फल संरक्षण डिपार्टमेन्ट १८,००० रुपये दिखलाता है और एक काश्तकार २,००० रुपये में तैयार करता है। इन तीनों ट्यूबवेल्स के बीच में कितनी बड़ी खलीज है। मेरी दरख्वास्त आपके द्वारा यह है कि न तो ट्यूबवेल डिपार्टमेन्ट साढ़े पांच करोड़ के घाटे में चले, न हमारे काश्तकार की रोजाना कुर्की और नीलामी हो, न उसको रोज हथकड़ियां पड़ें यदि मेरा छोटा सा सुझाव मान लें। जैसा कि गांधी जी ने कहा कि आबपाशी का महकमा डिसेन्ट्रलाइज्ड पैदा किया गया है, यह कुदरती तौर से डिसेंट्रलाइज्ड है, विकेन्द्रित है। आप इतना ही कीजिये कि ग्राम समितियों को, सहकारी समितियों को, कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट को, ग्राम पंचायतों को या ग्राम समाज को या भूसिचन समिति बनाकर ये ट्यूबवेल्स सौंप दीजिये और वे साल भर में आपके घाटे को पूरा कर देंगे। लेकिन आप मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

अब जरा मेडिकल डिपार्टमेन्ट की तरफ चलिये। अब तक करोड़ों, अरबों रुपये की दवाइयां आ चुकी हैं, लेकिन इस देश की उन दवाओं से बीमारी बढ़ी है। जहां गांधी जी की मूर्ति के नीचे सरकार कायम हो, जहां गांधी जी से प्रेरणा ली जाती हो, उस देश में बीमारी बढ़ी है। गांधी जी ने एक दफा नहीं दस हजार दफा यह बात कही थी कि उनकी "मेरे ब्रह्मचर्य के अनुभव" नामक पुस्तक में लिखा है, वे रोजाना प्रेयर में कहते थे, "हरिजन" में भी आप देख सकते हैं कि जो दवायें योरूप से आती हैं उन्हें इकट्ठा करके अगर समुद्र में डाल दिया जाय तो मानव जाति तो बच जायगी, लेकिन मछलियां सब मर जायंगी। आज अगर आपको यह सजेशन दिया जाय कि धूप के जरिये से, प्राणायाम के जरिये से, पानी और मिट्टी के जरिये से आदमी अच्छा हो सकता है, बीमारियां दूर हो सकती हैं तो आप हर्गिज उसे मानने के लिये तैयार नहीं होंगे। इसी सूबे में स्वामी रघुनाथाचार्य जी रहते हैं, इसी सूबे में बिट्ठलदास मोदी रहते हैं, इसी सूबे में डाक्टर दिलकश रहते हैं और इसी सूबे में आपका यह छोटा सा सेवक रहता है लेकिन आपको कसम है कि मशवरा लें। आप यह नहीं मान सकते कि मिट्टी, पानी और हवा से कोई बीमारी अच्छी हो सकती है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से डंके की चोट पर कहता हूं और उनसे मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा नहीं साल भर आजमा कर देखें। अगर विरोधी पार्टियों के सुझाओं पर सरकार थोड़ा बहुत भी अमल करती है तो मैं चैलेंज करके कहता हूं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी १० हजार बीमारों की टुकड़ी मुझे सौंप कर के देखें। एक साल में अगर ऐलोपैथिक चिकित्सा से कहीं ज्यादा कामयाब न हो सकूं तो मुझे इसी हाल में खड़ा करके कैपिटल पनिशमेन्ट दें। लेकिन मानता कौन है। बार-बार यह कहा जाता है कि कास्ट्रविटव सजेशन दीजिये। बार-बार यह कहा जायगा कि क्या करें उधर से कोई रचनात्मक सुझाव ही नहीं दिया गया।

स्कूलों के अन्दर धार्मिक शिक्षा होती तो आज यह हालत न होती जो कि १० साल में हुई। आप कालेजों में जाइये, यूनिवर्सिटी में जाइये वहां पर चश्मों की तादाद बढ़ी हुई मिलेगी। वहां पर पायरिया के दांतों की तादाद बढ़ी है, झुकी हुई कमर के शरीरों की तादाद बड़ी है। पिचके हुये गालों के ये हमारे विद्यार्थी, जो हमारी आशाओं के केन्द्र थे, उनके चरित्र को अगर आप देखें, तो वह दिन ब दिन गिरता जाता है। मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से कई बार प्रार्थना की है। उनकी साधना, तपस्या को पुकार कर यह कहा कि आपसे ही यह आशा है और आप ही यह काम कर सकते हैं। आप इस पुलिस डिपार्टमेन्ट को छोड़िये। इसको किसी नौजवान के हवाले कीजिये, केवल इस शिक्षा विभाग को अगर वे सम्भालें तो हमारे देश के नौजवानों की उन्नति के लिये, उनके शारीरिक निर्माण के लिये और चरित्र निर्माण के लिये कार्य कर सकते हैं।

श्रीमती विद्यावती बाजपेयी (जिला हरदोई)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि ८–१० दफा उठ बैठने केबाद आपने मुझे थोड़ा सा समय दिया। मैं माननीय वित्त मंत्री को बजट प्रस्तुत करने के लिये बधाई देती हूं। ३ दिन से बराबर इस बजट पर दोनों ओर से भाषणों को सुनने के बाद मैं इतना समझने में असमर्थ रही कि उस ओर के बठने वालों ने इस बजट का विरोध किया और उनको कोई अच्छायी नहीं दिखाई दी। यह हो सकता है कि इस बजट में कोई कमी हो। हम इस बात को नहीं कहते कि इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको कोई अच्छाई भी तो इसमें नजर आनी चाहिये थी। मैं यह नहीं कहती कि उनका कोई हक़ आलोचना करने का नहीं है लेकिन उनको यह भी कहना चाहिये कि यह सरकार कुछ अच्छाई का काम भी कर रही है। मैं समझती हूं कि अगर पिछले १०–५ वर्षों को देखा जाय तो हमारे प्रदेश में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुये हैं जिस पर हमें गर्व होना चाहिये। मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कह सकती हूं कि बहुत से काम सरकार की ओर से ऐसे किये गये हैं जिससे हमारे प्रदेश की बिलकुल कायापलट हो गई है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि उत्पादन के विषय में बहुत कहा गया है, बहुत कुछ हमारी सरकार की ओर से कृषि के विषय में अन्न उत्पादन करने के लिये प्रयत्न किया गया। सहकारिता के आधार पर अच्छा बीज, खाद और नये यंत्रों का आविष्कार करके, तकावी बांटकर, किसानों के लिये जमींदारी का विनाश करके भूमिधर बनाकर बहुत काम किये गये। हमारे गांवों का स्तर बहुत ऊंचे उठाया गया है और कृषि में भी काफी जन्नति हुई है। हमारे गांवों के आदमियों की अगर १० वर्ष पहले की कल्पना की जाय तो बहुत अन्तर इसमें हो गया है। एक किसान गेहूं पैदा तो करता था लेकिन उसको खाने को वह नहीं मिलता था। वह बिझरी खाता था। १० वर्ष पहले किसी भी किसान के तन पर पहनने के लिये कपड़ा नहीं मिलता था। लेकिन आज वह दशा नहीं है। मुझे दुख हुआ कि आज एक माननीय सदस्य ने, जो गांव के ही हैं, बताया कि उनको परेशानी है और गांव में परेशानी है। लेकिन गांव की हालत जो मेरी समझ में आई वह १० वर्ष से पहले से बहुत ही अच्छी है। अगर मैं दस गुना अच्छा कहूं तो अनुचित न होगा, अन्न की कमी हम शायद पूरी नहीं कर पाये हैं और उसका कारण यह भी है कि स्वास्थ्य आदि की ओर अधिक ध्यान देने के कारण हमारी आबादी कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अगर हम गांवों में फैमिली प्लानिंग की ओर कुछ ज्यादा ध्यान दें, तो सम्भव है कि हमारी यह अन्न की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है।

इसके बाद श्रीमन्, बेकारी के लिये बहुत सी बातें कही गयीं। बजट में मैंने १५–१६ कारखानों का जिक्र पढ़ा और मैं समझती हूं कि इस से हमारे प्रदेश की बेकारी में काफी कमी होगी। प्रदेश में कुटीर उद्योग और माध्यमिक उद्योग भी काफी खोले गये हैं। आगे भी बहुत सा प्रयत्न किया जा रहा है इनको बढ़ाने का, लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारे गांव के भाई और बहन जो चार महीने बेकार रहते हैं इनके उस समय को काम में लगाने और उनकी कपड़े की समस्या को हल करने के लिये यह जरूरी है कि उनको चरखे का इस्तेमाल कराया जाय, सिखाया जाय और मैं तो मुख्य मंत्री जी से आपके द्वारा अपील करती हूं कि उनमें ज्यादा से ज्यादा अम्बर चर्खे का प्रचार किया जाय ताकि वह अपने समय का सदुपयोग कर सकें।

[श्रीमती विद्यावती वाजपेयी---]

इसके अलावा समाज कल्याण की ओर भी ठोस कदम उठाया गया है। अभी हमारे एक हरिजन भाई कह रहे थे कि हरिजनों की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। मैं कहती हूं कि बापू जी ने और उन के बाद हमारी इस सरकार ने उन के लिये काफी प्रयत्न किया है और जो किया है वह प्रसंशनीय है। गांवों में मकान और कुंवें बनाने के लिये उनको तकावी दी गई है, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य आदि का प्रबन्ध किया गया है। लेकिन थोड़े से समय में ही एक दम से सारा काम नहीं हो सकता। उसके लिये हम को इंतजार करना पड़ेगा। इस विषय में मैं अपनी सरकार का ध्यान एक-दो बातों की ओर खासकर दिलाना चाहती हूं। आपने जो बूढ़े और अपाहिजों के लिये पेंशन की व्यवस्था की है उसके लिये मैं बहुत आभारी हूं और इस से देश की एक बड़ी समस्या हल हुई है।

हमारे देश में अभी दो चीजें एक कोढ़ के रूप में रह गई हैं, एक तो भिक्षावृत्ति और दूसरी वेश्यावृत्ति। इन दोनों के लिये इन पिछले १० सालों में कोई खास प्रयत्न नहीं किया गया है। मैं आशा करती हूं कि हमारी सरकार इन दोनों की ओर खास ध्यान देगी और ठोस कदम उठायेगी। जैसे चीन में आजादी के बाद उन्होंने वेश्यावृत्ति को समाप्त किया, वहां एक ओर उनको ट्रेनिंग देने के लिये स्कूल खोले गये, उनके विवाह करा दिये गये और उनको उस बुरे काम से हटाने के प्रयत्न किये गये और दूसरी ओर उसको किसी भी रूप में प्रचलित नहीं रहने दिया गया। चीन में हमारे देश से कहीं अधिक इसका प्रचार था। मैं माननीय मंत्री जी से इस विषय में फिर से अनुरोध करूंगी कि यदि यह चीज आजादी के बाद हमारे देश में रहती है कि हमारी बहनें अपनी इज्जत बेचकर अपना पेट पालें, तो यह बड़े शर्म की बात है। इसलिये मंत्री जी को इधर जल्दी ध्यान देने की आवश्यकता है।

भिक्षावृत्ति भी हमारे देश में एक कोढ़ जैसा है। स्टेशनों पर जाइये तो छोटे-छोटे बच्चे भिक्षा मांगते हुये दिखाई देते हैं। अपाहिजों की बात तो दूसरी है। मगर अच्छे हाथ पांव वाले भी भीख मांगते हैं। इसके लिये यदि सख्त कदम उठाया जाय तो बुरी बात नहीं होगी।

भ्रष्टाचार के विषय में यहां बहुत कुछ कहा गया। हमारे देश में अंग्रेजी राज्य सैकड़ों वर्षों से कब्जा जमाये था जिसे एकता और सहयोग के सहारे हम लोगों ने हटा दिया। यदि हम दोनों ओर के बैठने वाले ही इस बात में एक हो जावें, यही प्रतिज्ञा कर लें कि हम भ्रष्टाचार को मिटावेंगे तो यह दूर हो सकता है। माफ कीजिये, हमारे लोगों का ध्यान पार्टीबन्दी में ज्यादा रहता है कि कैसे हमारी पार्टी का प्रोपेगेंडा हो। कैसे हमारी पार्टी की ताकत बढ़े। यदि हम सब सोच लें कि भ्रष्टाचार हमारे देश के लिये एक बड़ा भारी कलंक है और अपने-अपने क्षेत्र में इसके विरुद्ध प्रयत्न करें तो बहुत कुछ कार्य हो सकता है। लेखपालों या पटवारियों को ही लीजिये यदि अपने-अपने क्षेत्र में हम लोग प्रचार करें कि उनको रिश्वत देकर काम न कराया जावे तो वहां से भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। कम वेतन पाने वाले लोग, जैसे कचहरियों में पेशकार और चपरासी हैं या लेखपाल हैं, ये लोग लालच में जल्दी आ जाते हैं। ऊंचे वर्ग में शायद यह चीज ज्यादा नहीं है। जनता अगर इस बात की प्रतिज्ञा करे कि वह रिश्वत देकर काम नहीं करायेगी तो यह चीज बहुत जल्द दूर हो सकती है।

चोरी, कत्ल और डाके आदि के बारे में बहुत कुछ कहा गया। आंकड़े भी बतलाये गये जो विभिन्न विभागों से लिये जाते हैं। अलग-अलग विभाग अपनी-अपनी रिपोर्ट देते हैं। आंकड़ों में अगर असमानता रहती है तो यह हमारी सरकार की सच्चाई का सबूत है कि हमारी सरकार उसे एक ही न करके ठीक-ठीक हाल बतला देती है। एक डिपार्टमेंट से ये आंकड़े प्रस्तुत हुये हैं। और दूसरे डिपार्टमेंट से ये आंकड़े प्रस्तुत हुये हैं। अगर कोई बेईमानी की भावना होती तो आंकड़ों को एक करके दिखा देते। उसमें कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन नहीं, जैसे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स से आये वैसे ही आपके सामने रख दिये गये। यही कारण है कि अलग-अलग किताबों में कहीं-कहीं आंकड़े अलग-अलग हैं, लेकिन इसके लिये यह कहना कि सरकार बेईमान है, ठीक नहीं है।

चौधरी खजानसिंह (जिला उन्नाव)––आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बजट को पढ़ा लेकिन मुझे तसल्ली न हुई। मुझे खुशी तब हुई जब कि बरसरे इक्तदार पार्टी के माननीय सदस्यों ने माननीय त्रिलोकी सिंह साहब का समर्थन किया मैं भी उनका समर्थन करता हूं।

माननीय गोविन्दसहाय जी ने मुल्क में गरीबी को बताया। कहा कि गरीबी बहुत बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बहुत फैलता जाता है, लेकिन उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया कि क्यों गरीबी बढ़ती जाती है और भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा। दूसरे माननीय नवलकिशोर साहब ने बतलाया कि अफसरशाही, नौकरशाही का जोर है और उसकी वजह से जनतंत्र में आराम नहीं है। अफसरों की तनख्वाहें ज्यादा हैं, कम की जायं और कोई सुझाव उन्होंने नहीं दिया। माननीय जगदीशशरण अग्रवाल ने बजट को कलरलैस बताया और इस तरह से हमारे विरोधी दल के नेता का समर्थन किया। आपने भी कोई सुझाव नहीं दिया।

एक साहब, माननीय बेचनराम गुप्त ने फरमाया कि समाजवाद आ रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता, यह पश्चिम से आ रहा है, लेकिन उन्होंने कोई ठोस सुझाव नहीं दिया।

माननीय सुल्तान आलम खां साहब को रेवेन्यू में खतरा दिखायी दिया। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू फंड खत्म हो रहा है। दूसरी स्कीमों में रेवेन्यू फंड को लगा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि कोई दिन ऐसा आयेगा जब कि वह खत्म हो जायगा और तबाही आ जायेगी उन्होंने भी कोई ऐसा ठोस सुझाव नहीं दिया न उन्होंने इस बात की कोशिश की कि बजट को ठीक कराते।

माननीय झारखंडेराय जी ने कहा कि २२,००० बीघे के फार्म, २३,००० बीघे के फार्म रहें और उनकी सीलिंग मुकर्रर न हो? मैं पूछता हूं कि क्या आप उनसे वृहत् जोत कर नहीं लेते हैं? १० आने रुपये में जब वे टैक्स देंगे तो २० हजार और २२ हजार बीघे के फार्म्स तो उनके ऐसे ही उसी में नीलाम हो जायेंगे, महल भी नीलाम हो जायेंगे। उनकी जितनी जायदाद है वह इसी तरह से खत्म हो जायगी, खतम हो रही है।

एक सदस्य––गजब हो गया।

चौधरी खजानसिंह––गजब की क्या बात है, कोई कुछ कहे उसे बुरा नहीं मानना चाहिये। जहां फार्म वाली बात वे कहते हैं, वहां पांच एकड़ की बात तो कही नहीं। इसके अलावा मैं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––माननीय चौधरी खजानसिंह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने और सुझाव आप कल को दें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२४ फरवरी, १९५८।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९४ का उत्तर पीछे २८ पर)

हरदोई जिले में निर्मित तथा प्रस्तावित नलकूपों की तहसीलवार सूची

तहसील	राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र व प्रगाढ़ क्षेत्र द्वारा निर्मित नलकूप	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्मित राजकीय नलकूप		द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जितने नलकूपों के निर्माण की सम्भावना है
	१९५५–५६	१९५६–५७ जो बन चुके हैं		१९५७–५८ जो बनाये जा रहे हैं
१	२	३	४	५
बिलग्राम ..	८	९	२	६
हरदोई ..	२	१	..	..
शाहाबाद ..	१	१०	३	३

रामम्रूति,
सिंचाई मंत्री।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२ पर)

नाम ग्राम		क्षति फसलों की (आने में)	राजस्व कर में जो छूट किया गया (आने में)
१		२	३
१--माउर बोझ	..	०-१६-०	०-१६-०
२--फतेहपुर तालरतीय	..	०-१६-०	०-१६-०
३--बसहा	..	०-१६-०	०-१६-०
४--धवरिया साफ	..	०-१६-०	०-१६-०
५--परदहा	..	०-१६-०	०-१६-०
६--तराई डीह	..	०-१६-०	०-१६-०
७--ढढवल मटरावं	..	०- ४-०	शून्य
८--सिसवा	..	०-१६-०	०-१६-०
९--खेरा मुहम्मदपुर	..	०-१६-०	०-१६-०

उपरोक्त क्षति के अतिरिक्त कुछ कच्चे मकानों को भी हानि पहुंची थी ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५ पर)

जिले का नाम	ग्राम पंचायत द्वारा		व्यक्तिगत ठेकेदारों द्वारा कार्य की लागत
	ग्रामों की संख्या	कार्य की लागत	
१	२	३	४
	रु०	रु०	रु०
१—इलाहाबाद	—	—	४,४८,०५४
२—प्रतापगढ़	—	—	१,००,०००
३—सुल्तानपुर	१	२,४००	१,८५,०००
४—जौनपुर	१	२,४००	१,८०,०००
५—बलिया	१६	१८,२८०	७,८८,९०८
६—आजमगढ़	१०३	२,१५,९४९	२८,०४,४२६
७—गाजीपुर	६८	१३,५००	११,००,०००
८—हमीरपुर	—	—	९६,५६५
९—बहराइच	—	—	१५,२०,०००
१०—गोंडा	—	—	१५,४५,४००
११—फैजाबाद	—	—	१६,४४,०००
१२—बाराबंकी	—	—	४,२०,९८०
१३—सीतापुर	—	—	४,४७,०००
१४—बस्ती	३०	२,४०,०००	३५,२०,०००
१५—देवरिया	२५	५०,६७५	७,१०,०७५
१६—गोरखपुर	—	—	५,५४,४३९
योग	—	६,८३,२०४	१,६०,५७,८५७

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५ पर)

१—जहां वर्तमान नाले काम कर रहे हैं, किन्तु अत्यन्त वर्षा होने पर इसमें बाढ़ आ जाती है—

(अ) गांवों के नाम—	योजनाएं—
अरदाया व अछनेरा	अरदाया नाला
(ब) मंगरौल जाट, रैमा, थापी, सैवा कुसमाला जनूया, भगुरा, कठवारों	वेस्टर्न डिपरेशन डेन को चौड़ा करने की योजना तैयारी तथा जांच पड़ताल के अन्तर्गत है ।
(स) दूरा मई बुजुर्ग वरनावई	स्थित युविच्स डेन क्षेत्र को सहायता देती है और जब ज्यादा वर्षा होती है तब इन गांवों में पानी फैल जाता है वस्तई और रेपुरा नाले वर्षा की अधिकता से गांवों में पानी फैल जाता है ।
(द) मई सस्तई रेपुरा अहीर	
(य) मिलावटी	मिलावटी नाला

२—वह गांव जिनके नालों की योजनाएं मंजूर हो चुकी हैं उन पर कार्य उसी समय किया जा सकता है जबकि कोष उपलब्ध होंगे—

(अ) सलेमाबाद	सलेमाबाद नाला
(ब) कामौटी	ब्राच कसौटी नाला
(स) देवरेठा	चांदी डेन

३—उन गांवों का क्षेत्र जहां नालों पर कार्य किया जा रहा है और उनकी आगामी वर्षा ऋतु तक पूर्ण होने की आशा की जाती है—

(अ) हंसपुरा व देवनारी	हंसपुरा नाला
(ब) डिर्थेवार	डिर्थेवार नाला
(स) नया बांस	नयाबांस नाला
(द) निनवाया	निनवाया डेन
(य) बहरावटी खास व नगला वह हावटी	बहरावटी नाला

४—उन गांवों व क्षेत्र जिनके नालों की मंजूरी बाकी है—

(अ) हसेला व गरीमा	बाच गरीमा नाला

वह गांव जिनमें नाले का सर्वे हो रहा है—

मुरेडा, अरसेना, धनौली मोपऊ, उलेरा, विसुरी, मोखर, अरूआखास, वियारागढ़ी, चन्दमन, दौलताबाद, जाजऊ, कोरई वदनपुर, सकरोंदा, गढ़ी, जिदपुरा, नूरपुर, पुरामना व मालिकपुर ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—३०२ एल० ए०—१९५८—८२५ ।